BLM Academy

Affiliated to C.B.S.E. New Delhi, C.B.S.E. Affiliation No.: 3530343
ISO 9001:2015 (QMS) Certified School

Wish You all a Very Happy New Year

"The Best Way To Predict Your Future Is To Create It With BLM Academy."

Vision - To prepare the children empowered with Indian ethical and spiritual values to face the global challenges.

Mission- To produce enriched and enlightened human resource for the country.

Pillars - SATYA, PURUSHARTH & PARAMARTH

Goal- ब्रह्म तत् लक्ष्यम्

Admission Open
For The Academic Session 2024-25
(Classes Nursery to IX & XI)

LIMITED SEATS
APPLY NOW

Streams: Science, Commerce & Humanities

Celebrate The Gift of Life

+91 7055515681
+91 7055515683
www.blmacademy.com

Padampur Devaliya, Gora Parao, Haldwani (Nainital), Uttarakhand

blma.principal@gmail.com

प्रणवो धनुः शरो हि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्मुच्यते।
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ।। (मुण्डक उपनिषद)

पोस्टल रजि.नं.यूए-नैनीताल-356-2021-2023

सितंबर 2024

उत्तरांचल दीप पत्रिका

यशस्वी पत्रकार वेदप्रकाश गुप्ता को समर्पित

₹:40

हिमालय में बादल फटने से तबाही

तानाशाह कौन मोदी या ममता ?

ममता बनर्जी के आग लगाने वाले बयान में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल सहित इंडिया गठबंधन के नेताओं को तानाशही क्यों नहीं नजर आती ? क्या इंडिया गठबंधन को ममता बनर्जी का आग लगाने वाला बयान शांति और सद्भाव वाला लगता है ?

ई-मेल: uttaranchaldeepatrika@gmail.com

Web: uttaranchaldeep.com

FOUNDER OF

UTTARANCHAL DEEP
BLM ACADEMY
TRINITY INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES
SHRI SHYAM COLONISERS Pvt. Ltd.
V.P. GUPTA INFRATECH
NUPUR NRITYA KALA KENDRA

भावपूर्ण
श्रद्धांजलि

A loving tribute to

Shri.Ved Prakash Gupta Ji

OUR ROLE MODEL

(29th Feb, 1944 - 06th Sep, 2014)

उत्तरांचल दीप | V.P. GUPTA INFRATECH | SHRI SHYAM

मासिक
उत्तरांचल दीप
पत्रिका

वर्ष:7, अंक 5, सितंबर 2024

संस्थापक संपादक
स्व.वेदप्रकाश गुप्ता
प्रधान संपादक
साकेत अग्रवाल
संपादक
श्रीमती आदेश अग्रवाल
मुख्य कार्यकारी संपादक
केके चौहान
मुख्य उप संपादक
उदयभान सिंह
मार्केटिंग हेड
तारु तिवारी
प्रबंधक
दीपक तिवारी
वरिष्ठ संवाददाता
रवि दुर्गापाल

उत्तरांचल दीप ब्यूरो
दिल्ली : शालिनी चौहान
लखनऊ : पारस अमरोही
रुद्रप्रयाग : हिमांशु पुरोहित
नैनीताल : अफजल फौजी
अल्मोड़ा : कमल कपूर
पिथौरागढ़ : ललित जोशी
बागेश्वर : नरेंद्र बिष्ट
चंपावत : मनोज राय
बरेली : अनुज सक्सेना
मुरादाबाद : आशेंद्र कुमार अग्रवाल
डोईवाला : चंद्रमोहन कोठियाल
किच्छा : राजकुमार राज
रामनगर : एचसी भट्ट
थत्यूड़ : मुकेश रावत
रुद्रपुर : मुकेश गुप्ता
बाजपुर : इंद्रजीत सिंह
ग्राफिक्स डिजाइन: देवेंद्र सिंह बिष्ट
सभी पद अवैतनिक एवं परिवर्तनीय

मुख्यालय
हल्द्वानी: चंद्रकांता हाउस, जजी के सामने
नैनीताल रोड, हल्द्वानी (उत्तराखंड)

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक श्रीमती आदेश अग्रवाल द्वारा उत्तरांचल दीप, चंद्रकांता हाउस, जजी के सामने नैनीताल रोड हल्द्वानी से मुद्रित व प्रकाशित।
आएनआई नंबर: UTTHIN/2018/77440
पोस्टल रजि.नं.यूए-नैनीतील-356-2021-2023

उत्तरांचल दीप पत्रिका में प्रकाशित लेख, पत्र व अन्य कालम में लेखकों के विचार होते हैं, उनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।
समस्त विवाद हल्द्वानी न्यायालय के अधीन होंगे।

www.uttaranchaldeep.com
uttranchaldeepatrika@gmail.com
+91 8881788066 @uttranchaldeep

अंदर

कांग्रेस इतिहास ही बांटने का रहा है, पहले पंडित जवाहर लाल नेहरु ने देश बांट कर पाकिस्तान बनाया, फिर नेहरु की बेटी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को बांटकर बांग्लादेश बनाया और अब राहुल गांधी जातियों के नाम पर हिंदू समाज का बंटवारा चाहते हैं।

बिहार देश

भारत को कट्टरपंथ से खतरा ?

बांग्लादेश की तरह भारत में भी कट्टरपंथ हावी होने की कोशिश में है, प्रतिबंधित पीएफआई के अंडर ग्राउंड एजेंट अभी भी ...

उत्तराखंड

24 साल में 16 फीसदी बढ़े मुसलमान

धर्म नगरी ऋषिकेश में कोई मुस्लिम नहीं था, पर अब शहर के चारों तरफ मुसलमान ...

सोसायटी

सोच बदलने से थमेगी यौन हिंसा

पुलिस 50 फीसदी रेप केस दर्ज ही नहीं करती है, पुलिस पीड़िता को सामाजिक प्रतिष्ठा का डर ...

प्रतिभा

अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन लक्ष्य से चूके

लक्ष्य सेन ने 9 साल की उम्र में बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण की एकेडमी में प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था ...

साकेत अग्रवाल

कंगाली की राह पर बांग्लादेश ?

आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन की आड़ में कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्तापलट कर दिया। अब बांग्लादेश पूरी तरह आतंकियों और कट्टरपंथियों के हाथ में है। जिस देश में कट्टरपंथियों और आतंकियों की पकड़ मजबूत रहती है वो निश्चित ही कंगाली की तरफ चलने लगता है। पाकिस्तान इसका जीता जागता उदहारण है। पाकिस्तान के जुल्मों से तंग आकर ही बांग्लादेश अलग लोकतांत्रिक देश बना था। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों और आतंकियों का ऐसा कॉकटेल तैयार हुआ कि शेख हसीना को बांग्लादेश तक छोड़ना पड़ गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कट्टरपंथी बांग्लादेश को कंगाली की तरफ धकेलना चाहते हैं? क्योंकि बांग्लादेश के जो हालात है उन्हें देखते हुए क्या कोई देश बांग्लादेश के साथ व्यापार करना पसंद करेगा? क्या बांग्लादेश में कोई विदेशी निवेश करने को तैयार होगा? क्या कट्टपंथ और आतंक के सामने जो इंडस्ट्री बांग्लादेश में अभी चल रही हैं वो टिक पाएंगी? क्योंकि कट्टरपंथियों ने हिंसा के दौरान बांग्लादेश में चल रही तमाम इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचाया है। लूटपाट करने के बाद कई उद्योगों को आग के हवाले कर दिया। हिंदुओं के प्रतिष्ठानों को लूट लिया। ये सब किसी देश को कंगाल करने के साफ-साफ संकेत नहीं तो और क्या है? वैसे भी जब से शेख हसीना की सरकार का पतन हुआ है और मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया बने हैं तब से कट्टरपंथियों के मनमुताबिक फैसले किए जा रहे हैं। कट्टरपंथियों के दबाव में ही प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी पर लगा बैन हटाया गया। जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी मुस्लिम पार्टी है। इस पार्टी पर छात्र आंदोलन के दौरान दंगे भड़काने का आरोप है। फिर भी बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने गजट अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि जमात-ए-इस्लामी और उसके सहयोगियों के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कोई सबूत नहीं हैं। इसलिए बैन हटाया जा रहा है। इससे हर किसी के जहन में सवाल आएगा कि जो अंतरिम सरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार रोकने में नाकाम है, जो मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार कानून व्यवस्था को पटरी पर नहीं ला पाई उसने किस एजेंसी से रातों रात जमात-ए-इस्लामी की जांच कराई है? किस जांच एजेंसी ने उसे क्लीन चिट दी? क्या मोहम्मद यूनुस या उनके सहयोगी दुनिया को इन सवालों का जबाव दे पाएंगे?

जमात-ए-इस्लामी की स्थापना 1941 में ब्रिटिश शासन काल के दौरान अविभाजित भारत में हुई थी। इस संगठन ने 1971 में अलग बांग्लादेश बनाने का विरोध किया था। जमात-ए-इस्लामी के ज्यादातर सीनियर लीडर्स को 1971 के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान की गई हत्याओं, किडनैपिंग, बलात्कार और अन्य अपराधों में गिरफ्तार कर जेल में बंद किया गया था। इनमें से कुछ को फांसी दी जा चुकी है। यह संगठन खुद को पाकिस्तान परस्त बताता है। जमात-ए-इस्लामी का हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जमात के लोगों ने 2001 में भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की थी। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने क्या कट्टरपंथियों और आतंकवादी संगठन अल-कायदा से ताल्लुक रखने वाले संगठनों को खुली छूट दे दी है? 26 अगस्त को कट्टरपंथी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी को रिहा कर दिया। जशीमुद्दीन रहमानी को ब्लॉगर राजीव हैदर की हत्या के लिए उकसाने के मामले में 5 साल की सजा हुई थी। 15 फरवरी 2013 की रात राजधानी ढाका के पल्लबी के पलाशनगर में राजीव हैदर की उनके घर के सामने हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद राजीव के पिता ने पल्लबी थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था। जशीमुद्दीन रहमानी की इसी साल जनवरी में रिहाई हुई थी, मगर एक अन्य मामले में उसे फिर जेल भेजा गया था। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम अल-कायदा से प्रेरित आतंकी संगठन है, जिसे अब अंसार-अल-इस्लाम के नाम से जाना जाता है। शेख हसीना सरकार ने 2015 में अंसारुल्लाह बांग्ला टीम पर बैन लगाया था। इस संगठन पर भारत में आतंकवाद फैलाने के आरोप लगते रहे हैं। भारत में भी इस संगठन के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है।

कट्टरपंथी मौलानाओं की तकरीर साफ बता रही हैं कि बांग्लादेश में शायद शरिया कानून लागू करने की तैयारी है। शरिया कानून लागू होगा तो निश्चित ही बांग्लादेश कंगाल हो सकता है। क्योंकि कट्टरपंथियों के बीच विदेशी निवेश बंद हो जाएगा, दूसरे देशों से कारोबार बंद होगा। इससे निश्चित ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था चरमराएगी। अभी तक भारत, बांग्लादेश से वस्त्र, जूट और जूट के सामान, चमड़े के सामान और कृषि उत्पाद जैसे फल, सब्जियां और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ आयात करता रहा है। बांग्लादेश के कपड़ा और परिधान उद्योग दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। भारत प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता के कारण बांग्लादेश से तैयार वस्त्र और बुना हुआ कपड़ा आयात करता रहा है। बांग्लादेश जेनेरिक दवाओं और फार्मास्यूटिकल उत्पादों का प्रमुख निर्यातक भी है। भारत बांग्लादेश से विभिन्न फार्मास्यूटिकल फॉर्मूलेशन और कच्चे माल का आयात करता रहा है, जो भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विकास में योगदान करता है। बांग्लादेश उच्च गुणवत्ता वाले चमड़े के सामान का उत्पादन करता रहा है। इसलिए भारत, बांग्लादेश से चमड़े के जूते, बैग और पर्स आयात करता है। यानी अभी तक बांग्लादेश, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। साथ ही भारत, बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात साझेदार भी रहा है। भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में बांग्लादेश को 6,052 वस्तुओं का निर्यात किया। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का बांग्लादेश को निर्यात 12.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वित्त वर्ष 2022-23 में 16.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत से बांग्लादेश को सूती धागा, पेट्रोलियम उत्पाद, अनाज और सूती कपड़े प्रमुख रूप से भेजे जाते रहे हैं। शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत रहे हैं। इसका प्रमाण दोनों देशों के बीच भारतीय रुपये में ट्रेड होना था। लेकिन बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा आरजकता फैलाने से राजनीतिक अस्थिरता हावी हुई है। जिससे दो महीने से बांग्लादेश के हालात खराब होने से भारत व बांग्लादेश के कारोबारियों को हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है।

'ओम' की लुकाछिपी

कुमाऊं मंडल विकास निगम ने कहा कि सोशल मीडिया में ओम पर्वत की बिना बर्फ की एक फोटो वायरल हो रही है, जिससे भक्तों में निराशा है, लेकिन उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी होने से फिर से ओम पर्वत पर बर्फ पड़ गई है, अब यहां ऊँ स्पष्ट दिखाई देने लगा है।

उत्तरांचल दीप डेस्क

उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ में बर्फ की सफेद चादर लिपटा रहने वाला ओम पर्वत अचानक बर्फ विहीन हो गया है। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र रही ओम की आकृति भी लुकाछिपी करने लगी। क्योंकि अगस्त के पहले सप्ताह में ओम पर्वत पर सिर्फ देखने के लिए काला पहाड़ बचा था बर्फ पिघल चुकी थी। ओम पर्वत की ऐसी हालत देखकर स्थानीय ग्रामीणों के साथ ही सैलानी और वैज्ञानिक भी हैरान रहे। ओम पर्वत से बर्फ पिघलने की वजह हिमालय पर लगातार बढ़ता तापमान बताया गया। विश्व प्रसिद्ध ओम पर्वत से बर्फ पूरी तरह से पिघल गई थी। बर्फ पिघलने और ग्लोबल वार्मिंग के कारण सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र ओम की आकृति भी पूरी तरह से लुप्त हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ में ओम पर्वत के दर्शन करने के बाद यहां पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है। किंतु इस सीजन में गर्मी अधिक होने की वजह से पहाड़ों में भी तापमान बढ़ गया था। चूंकि पर्यटन गतिविधियां बढ़ी तो इस हिमालयी क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही भी बढ़ गई जिससे वातावरण में तेजी से परिवर्तन आना स्वभाविक था। इसी परिवर्तन का सीधा असर ओम पर्वत पर दिखाई दिया। ओम पर्वत चीन सीमा से लगे लिपुलेख दर्रे के पास है। इस पर्वत पर ओम की आकृति बनी रहती थी जिससे यह पर्वत ओम पर्वत के नाम से पहचाना जाता है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब ओम पर्वत पर बनने वाली आकृति गायब हो गई है। पर्यावरणविद वैश्विक तापमान में वृद्धि और उच्च हिमालयी क्षेत्र में हो रहे निर्माण को इसके लिए दोषी मान रहे हैं। पिछले दिनों पिथौरागढ़ प्रवास पर अपने मूल गांव गुंजी गई उर्मिला सनवाल गुंज्याल ने खुलासा किया था कि वो 16 अगस्त को ओम पर्वत के दर्शन के लिए गई थीं। जब वह फोटो खींचने के लिए नाभीढांग गई तो उन्हें ओम पर्वत पर बर्फ नजर नहीं आई, ऊँ भी गायब था जिससे वह बहुत निराशा हुई। ओम पर्वत पर पर्यटन काफी बढ़ा है। पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए यहां सड़कों का निर्माण भी हो रहा है जिसका सीधा असर हिमालय के पर्यावरण पर पड़ रहा है। हालांकि इसके नौ दिन बाद ही 27 अगस्त को कुमाऊं मंडल विकास निगम ने दावा किया कि ओम पर्वत फिर से बर्फ से आच्छादित हो गया है। बर्फवारी होने से ओम पर्वत पर ऊँ का चिह्न फिर से दिखाई देने लगा है।

ऊँ स्पष्ट दिखाई देने लगा

ओम पर्वत पिथौरागढ़ जिले से 170 किलोमीटर दूर नाभीढांग में स्थित है। इस पर्वत पर बर्फ से कुदरती ओम की आकृति बनती है। जिसे हिंदू धर्म को मानने वाले भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। ओम पर्वत के धार्मिक और पौराणिक महत्व का उल्लेख महाभारत, रामायण एवं वृहत पुराण जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। इसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने कहा कि सोशल मीडिया में ओम पर्वत की बिना बर्फ की एक फोटो वायरल हो रही है। जिससे भक्तों में निराशा है। लेकिन उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी होने से फिर से ओम पर्वत पर बर्फ पड़ गई है। अब यहां ऊँ स्पष्ट दिखाई देने लगा है। कुमाऊं मंडल विकास निगम का कहना है कि यह पर्वत कई बार बर्फ विहीन रहा है। एसडीसी फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल का कहना है कि केएमवीएन का कहना है कि ओम पर्वत पर ऊँ का चिह्न फिर दिखाई देने लगा है। ये अच्छी बात है, लेकिन विषय ये है कि ग्लोबल वार्मिंग और मानवीय गतिविधियों को लेकर सरकार का क्या स्टेंड है। इसी तरह हीटवेब को लेकर इस बार लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था।

ओम पर्वत यानी छोटे कैलाश की कहानी

स्कंद पुराण के मानस खंड में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा को कैलाश मानसरोवर यात्रा जितना महत्वपूर्ण और सार्थक बताया गया है। यही कारण है कि ओम पर्वत को छोटा कैलाश भी कहा जाता है। समुद्र तल से ओम पर्वत की ऊंचाई 6,191 मीटर है। इस पर्वत की विशेषता है कि जब इस पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो ओम की आकृति अलग ही चमकती है। यह पल बेहद खूबसूरत और अद्भुत अनुभूति वाला होता है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले बर्फ कम होने के बावजूद ओम पर्वत की आकृति कभी भी नहीं मिटी थी। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि ओम पर्वत की पूरी बर्फ पिघल गई और ओम की आकृति लुप्त हो गई। इस आकृति के गायब होने की सबसे बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि 2019 में ओम पर्वत तक सड़क बना दी गई जिससे करीब 100 गाड़ियां रोज ओम पर्वत तक जा पहुंच रही हैं। वाहनों से निकलने वाले कार्बन और वाहनों की गर्मी का सीधा असर पहाड़ी वातावरण पर पड़ता है। इसके अलावा कुमाऊं मंडल विकास निगम (केएमवीएन) ने हेलीकॉप्टर दर्शन सेवा भी शुरू करा दी है। हेलीकॉप्टर ओम पर्वत पर ही उतर रहे हैं। जिसकी वजह से हिमालय क्षेत्र में प्रदूषण तेजी से बढ़ा है। हालांकि हैलीसेवा के खिलाफ स्थानीय लोगों ने आंदोलन भी किया था। स्थानीय लोगों की मांग थी कि हेलीकॉप्टर को आदि कैलाश और ओम पर्वत तक ना ले जाया जाए। ओम पर्वत से 16 किलोमीटर पहले गूंजी में हेलीकॉप्टर रोक दिया जाता तो इससे पर्यावरण भी बचता और लोगों को रोजगार का अवसर भी मिलता।

सुर्खियां

हिमाचल का राजकोष खाली

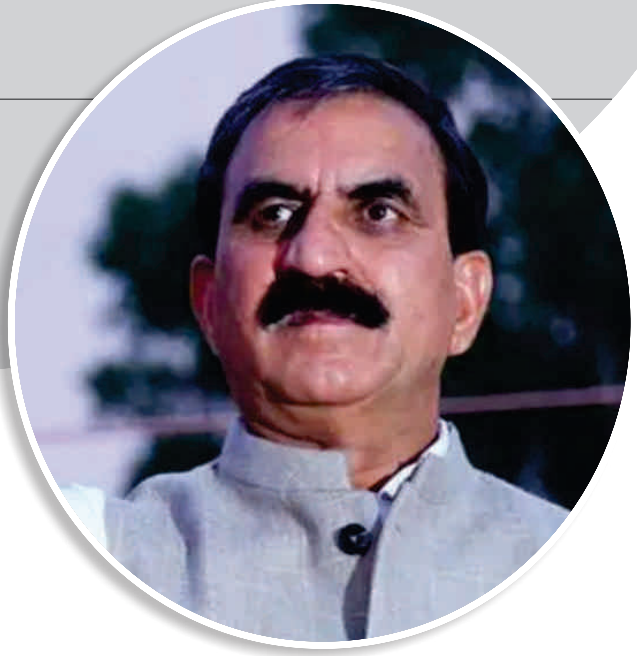

हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, बिहार के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव यूपी के सपा नेता अखिलेश यादव कह रहे थे कि देश की हर गरीब महिला के खाते में खटाखट...खटाखट... एक लाख रुपये सालाना आएंगे। इस खटाखट वाली योजना ने हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट पैदा कर दिया है। विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने फ्री की योजनाओं का ऐलान किया था। मुफ्त के लालच में फंसी हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को वोट दिया और सरकार भी बनवा दी। लेकिन अब यही मुफ्त की योजनाएं हिमाचल की जनता पर भारी पड़ रही हैं। सरकारी खजाना मुफ्त की योजनाओं ने खाली कर दिया है। हालत ये है कि सरकार विभागीय कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है। खुद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह अपनी नाकामी और मुफ्त की योजनाओं का ठिकरा पूर्व की भाजपा सरकार के सिर फोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि पूर्व की भाजपा सरकार की गलत नीतियों की वजह से कर्मचारियों का लंबित डीए और एरियर भुगतान नहीं हो पा रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग की सचिव प्रियंका बसु की ओर से 30 जुलाई 2024 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष का वेतन 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 30 रुपये रुपये कर दिया गया है। इस वेतन के साथ अध्यक्ष को अन्य भत्ते भी मिलेंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि अगली बैठक में इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मंजूर कर दिया जाएगा। एक तरफ सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे का अभाव है और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष का वेतन 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 30 रुपये रुपये कर दिया जाता है। ऊपर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टीवी न्यूज चैनल पर आकर कहते हैं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार होने तक वो खुद और उनकी सरकार में मंत्री दो महीने तक वेतन, डीए व टीए नहीं लेंगे। यह घोषणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान की गई। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री और मंत्री ये दो महीने का वेतन नहीं लेंगे, बल्कि राजकोष में धन की व्यवस्था होने पर इकट्ठा वसूलेंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यह सांकेतिक होने के साथ बड़ा कदम हैं। हालांकि इससे कोई ज्यादा अंतर तो नहीं आएगा, लेकिन यह सरकार का ऐतिहासिक और सांकेतिक निर्णय है। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के राजकोष का राज बताया तो भाजपी को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। भाजपा के विधायक और पूर्व शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने सरकार पर तंज करते हुए लिखा सोशल मीडिया पर लिखा कि एक तरफ सरकार आर्थिक बदहाली का रोना रोकर वेतन डिले करवा रही है और दूसरी तरफ एक बोर्ड के अध्यक्ष के वेतन में एक साथ एक लाख रुपये की बढ़ोतरी की जा रही है। वो भी एक दौर था, जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, यह भी एक दौर है। भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा- मैं, मेरे परिवार और मित्रों का काम बनता भाड़ में जाए जनता। झूठ बोलना और जनता को गुमराह करना कोई प्रदेश की सुक्खू सरकार से सीखे। एक तरफ मंत्रियों, चेयरमैन व मुख्य संसदीय सचिवों द्वारा दो माह का वेतन न लेने का दिखावा किया जा रहा है और दूसरी तरफ एक चेयरमैन के वेतन में सीधे से पांच गुना वृद्धि की गई है। वाह रे व्यवस्था परिवर्तन। लोगों की आंखों में धूल झोंकने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। सत्ता लोभ में झूठी घोषणाएं कर प्रदेश को कर्ज के बोझ में दबाया जा रहा है, पर मित्रों को रेवड़ियां बांटना जारी है। फिर ये वेतन न लेने का दिखावा क्यों?

निकाय चुनाव तीन माह खिसके

उत्तराखंड में स्थानीय नगर निकाय के चुनाव तीन महीने और आगे खिसक गए हैं। हालांकि पहले से ही नगर निकाय चुनावों को लेकर तमाम आशंका बनी हुई थीं। क्योंकि कई महीनों से निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर सरकारी कसरत हो रही है, लेकिन सरकारी औपचारिकताएं फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच पाई हैं। यही वजह है कि नगर निकाय के चुनाव में विलंब हो रहा है। सरकार की तैयारी पूर्ण नहीं हो पाई इसलिए चुनाव की कोई तारीख भी तय नहीं हो पा रही है। यह मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा। हाईकोर्ट ने भी नगर निकाय चुनाव कराने के लिए सरकार को निर्देश दिए। करीब दो महीने पहले ही हाईकोर्ट में निकाय चुनाव को जल्द से जल्द कराने का आदेश दिया था, नगर निकायों के प्रशासकों का कार्यकाल भी नहीं बढ़ाने की बात कही गई थी। इन सबके बीच सरकार ने उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव तीन महीने आगे खिसका दिए। प्रशासकों का कार्यकाल अगले 3 महीने या नगर निकाय बोर्ड का गठन होने तक के लिए बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि प्रशासकों के अगले 3 महीने तक बढ़ाए गए कार्यकाल के दौरान ही नगर निकाय के चुनाव कराने की सरकार की प्लानिंग है। उत्तराखंड में 1 दिसंबर 2023 को नगर निकायों के बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो गया था। लिहाजा नगर निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई थी। प्रशासकों का कार्यकाल भी 31 जून 2024 को 6 महीने का पूरा हो गया है। ऐसे में अब सरकार के सामने संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। जिससे निपटने के लिए अब प्रशासकों का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाना सरकार की मजबूर बन गई।

आंध्र में कौशल जनगणना

देश में जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा नेता अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आदि ने गदर मचा रखा है। देश को जातियों में बांटने वाले इन नेताओं को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में कौशल (स्किल) जनगणना कराने का ऐलान कर आइना दिखा दिया है। जातिवाद की राजनीति करने वाली जमात से अब सवाल पूछे जाने लगे हैं कि कौशल यानी हुनर से बेहतर रोजगार मिलेगा या जातिवाद से? सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या ये नेता सिर्फ युवाओं को रोजगार के नाम पर गुमराह कर रहे हैं? क्योंकि जब युवाओं के पास हुनर ही नहीं होगा तो वो किसी भी पद पर बेहतर काम कैसे कर पाएंगे? देश में पहली बार हो रही कौशल जनगणना के तहत सरकार विभिन्न क्षेत्रों में रुचि रखने वाले युवाओं की पहचान करेगी। पहले चरण में 33 लाख रोजगार देने वाले संस्थानों का सर्वे कर यह पता लगाया जाएगा कि उन्हें किस तरह के हुनरमंदों की आवश्यकता है। इसके बाद 25 से 50 साल के लोगों के बीच सर्वे कर यह पता लगाया जाएगा कि वो किस कार्य में कुशल हैं। यदि उन्हें किसी तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी तो सरकार उन्हें कौशल विकास की ट्रेनिंग देगी। इसके अलावा सरकार उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिलाकर प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से प्रमाण-पत्र जारी करेगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने देश में पहली बार कौशल गणना सर्वेक्षण प्रायोगिक तौर पर तीन सितंबर से शुरू कर दिया है। मंगलगिरी विधानसभा क्षेत्र के नागार्जुन विश्वविद्यालय में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। सर्वेक्षण के लिए विशेष रूप से एक ऐप तैयार किया गया है। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद यदि वेबसाइट उपलब्ध करा दी जाती है तो बाजार में आने वाले नए लोगों को अपना विवरण दर्ज कराने का मौका मिलेगा। इस सर्वे के लिए हर गांव और वार्ड में छह कर्मचारियों को लगाया जाएगा। जिन्हें सितंबर की 23, 24, 30 और 31 तारीख को दो किस्तों में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद वे घर-घर जाकर टैब में जानकारी एकत्र करेंगे। साक्षर, निरक्षर, कर्मचारी, जिन्हें पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं मिली। क्या नौकरी संगठित क्षेत्र की है? असंगठित क्षेत्र की? बेरोजगारों की शैक्षणिक योग्यता क्या है? पीएचडी, एमएस, डिग्री, इंटरमीडिएट, 10वीं, 8वीं। अगर आपने बीटेक की पढ़ाई की है तो क्या आपको डोमेन नॉलेज है? 25 तरह के सवालों के जरिए जानकारी एकत्रित की जाएगी। इसके अलावा संगठित क्षेत्र में काम करने वालों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के पीएफ अकाउंट का हिसाब ई-श्रम के जरिए लिया जाएगा। कौशल विकास संगठन का अनुमान है कि राज्यव्यापी सर्वेक्षण के जरिए डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने में लगभग 8 महीने लगेंगे? इस सर्वेक्षण के पूरा होने के बाद कितने लोग बेरोजगार हैं? कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है? रोजगार पाने वालों में से कितने लोग अभी भी बेहतर नौकरी चाहते हैं? कितने लोग निरक्षर हैं? उन्हें जो भी जानकारी चाहिए, वह उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों का अनुमान है कि यह जानकारी कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सृजन के लिए करीब 20 साल तक उपयोगी रहेगी। किसको किस डोमेन में कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इसकी पहचान करने के बाद नए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कौशल कॉलेज, हब, केंद्र स्थापित किए जाएंगे और प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। किस तरह के कौशल की आवश्यकता है, इसका विवरण भी कंपनियों से लिया जाएगा। फिर युवाओं को उसी के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा है और संबंधित कंपनियों से जोड़ा जाएगा। प्रशिक्षण के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और केंद्रीय सरकारी क्षेत्र कौशल परिषदों की सेवाओं का भी उपयोग किया जाएगा।

भूत के साथ पुलिस भर्ती परीक्षा

महराजगंज जिले में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान अंतिम दिन परीक्षा केंद्र पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां पहली पारी की परीक्षा में शामिल होने आई एक महिला अभ्यर्थी भूत के साये के साथ परीक्षा में शामिल हुई। सिपाही भर्ती परीक्षा देने आई महिला की जब जांच की गई तो वह कमर में लोहे की चेन को ताले में बंद करके आई थी। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने जब चेन निकालने को कहा तो महिला अभ्यर्थी ने कहा कि इसे नहीं निकाल सकती, भले ही परीक्षा क्यों न छोड़नी पड़े। गेट पर खड़े उसके परिजनों ने भी सुरक्षाकर्मियों से कहा कि ताला मत खोलिएगा नहीं तो महिला को संभालना मुश्किल हो जाएगा। काफी देर तक अभ्यर्थी को किनारे खड़ा रखा गया। बाद में उच्चाधिकारियों से बात करने के बाद कक्ष निरीक्षक की विशेष निगरानी में उसे परीक्षा देने की इजाजत दी गई। दरअसल सिपाही भर्ती परीक्षा के अंतिम दिन की पहली पारी में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज धनेवा धनेई केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने आई महिला अभ्यर्थी की जब सुरक्षा कर्मियों ने जांच की तो मेटल डोर डिडेक्टर से आवाज आने लगी। इस पर छात्रा ने बताया कि भूत-प्रेत के साए को भगाने के लिए उसने तांत्रिक के सुझाव पर अपनी कमर में लोहे की जंजीर को ताले से बंद कर रखा है। उसी से आवाज आ रही है। इस पर महिला सुरक्षाकर्मियों ने ताला खोलकर लोहे की जंजीर को निकालने को कहा, लेकिन महिला अभ्यर्थी इस बात पर अड़ गई कि वह जंजीर नहीं खोल सकती भले ही सिपाही भर्ती परीक्षा उसे छोड़नी पड़ जाए, लेकिन वह ताला नहीं खोलेगी इतना ही नहीं गेट पर अभ्यर्थी के परिजन भी मौजूद थे। उनका कहना था कि युवती पर भूत का साया है जिससे वो काफी समय से परेशान है। कई भूत उसके उपर सवार थे। झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र करने वाले के सुझाव पर युवती के शरीर पर 11 लोहे की जंजीरों को ताले से बंद किया गया था। 10 भूत उसका पीछा छोड़ चुके हैं। जिसके बाद 10 ताला अपने आप खुल गए। अभी 11वां ताला नहीं खुला है। अगर परीक्षा के लिए ताला खोला जाता है तो भूत से युवती को मुक्ति नहीं मिलेगी। लिहाजा ताला नहीं खोलने की बात पर अभ्यर्थी की सघन जांच हुई। कोई डिवाइस अथवा आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिलने पर कक्ष निरीक्षक की विशेष निगरानी में कमर में ताला लगाकर ही महिला अभ्यर्थी ने परीक्षा दी।

तानाशाह कौन मोदी या ममता?

ममता बनर्जी के आग लगाने वाले बयान में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल सहित इंडिया गठबंधन के नेताओं को तानाशही क्यों नहीं नजर आती? क्या इंडिया गठबंधन को ममता बनर्जी का आग लगाने वाला बयान शांति और सद्भाव वाला लगता है?

केके चौहान

हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी दलों का एक लोकप्रिय शब्द था 'तानशाह'। नारा दिया जाता था कि 'मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी।' विपक्ष के कुछ बड़े नेता मोदी का नाम लिए बिना भी कहते थे कि देश में तानाशाह की सरकार है। इस शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कांग्रेस के राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल करते थे। अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष के पास तानाशाही देखने वाले चश्मे अलग-अलग है? क्या पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो तानाशाही से कम है? पश्चिम बंगाल में अभिव्यक्ति की आजादी है क्या? क्योंकि कोलकाता पुलिस ने सरकार और पुलिस के खिलाफ बोलने वालों को नोटिस थमा दिए। पश्चिम बंगाल में किसी को धरना प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता क्यों नहीं है? कोलकाता के जीआर कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद नृशंस हत्या कर दी जाती और सरकार का सिस्टम घटनास्थल से सबूत नष्ट कर देता है, क्या ये तानाशाही की श्रेणी में नहीं आता? क्योंकि सबूत मिटाने से अपराधी को सीधा फायदा होता है। आखिर सबूत मिटाकर दुराचारी को सरकारी सिस्टम क्यों बचाना चाहता है? ऊपर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तृणमूल छात्र परिषद के कार्यक्रम में देश को धमकी देती है कि अगर बंगाल जलता है, तो असम, पूर्वोत्तर, यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे? ममता बनर्जी के इस बयान में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल सहित इंडिया गठबंधन के नेताओं को तानाशही क्यों नहीं नजर आती? क्या इंडिया गठबंधन को ममता बनर्जी का आग लगाने वाला बयान शांति और सद्भाव वाला लगता है? क्यों नहीं इंडिया गठबंधन के नेता पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसकी निंदा करते। पश्चिम बंगाल को लेकर तो कांग्रेस भी बटी हुई है। एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस के सभी बड़े नेता खामौश हैं तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी अकेले ममता सरकार से दो-दो हाथ कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देश में आग क्यों लगाना चाहती है? सवाल ये भी है कि देश में आग लगाने की धमकी देने वाली ममता बनर्जी तानाशाह है या बेईमान और भ्रष्ट नेताओं पर सख्त कार्रवाई करने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार तानाशाह हैं? हालांकि जनता ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को बता भी दिया और जता भी दिया कि तानाशाह कौन है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बस बहुत हो गया, मैं इस घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूं, अब बहुत हो चुका, समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर केस के 20 दिन बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला बयान है।

दिल्ली पुलिस से ममता की शिकायत

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। जिंदल का तर्क है कि ममता बनर्जी का यह बयान भड़काऊ और राष्ट्र विरोधी है। उनका बयान क्षेत्रीय घृणा और दुश्मनी भड़काने वाला हैं, देश में अशांति फैलाने वाला है। शिकायत में दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी जनता पर प्रभाव डालती हैं। संवैधानिक पद आसीन ममता बनर्जी के इस बयान का उद्देश्य अशांति फैलाना, भड़काना और देश की अखंडता एवं संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करना है। शिकायत में इस बात पर जोर दिया गया है कि मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी की स्थिति उनके बयान की गंभीरता को बढ़ाती है। उनकी भूमिका उन्हें पश्चिम बंगाल में प्रशासनिक और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को नियंत्रित करती है, और उनकी टिप्पणी राज्य के भीतर और अन्य क्षेत्रों में व्यापक अशांति को भड़काने वाली है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उनका बयान भड़काऊ और उत्तेजक प्रवृति का है और भारत के लोगों के बीच वैमनस्य पैदा कर दुश्मनी को बढ़ावा देता है। क्योंकि उन्होंने अपने बयान में दिल्ली का नाम एक राज्य के रूप में लिया है। दिल्ली का निवासी होने के नाते ममता बनर्जी के खिलाफ मेरी एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152, 192, 196 और 353 के तहत दर्ज की जाएं।

क्या न्याय दिलाना चाहती हैं ममता

दरअसल कोलकाता में तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता की महिला डॉक्टर के बलात्कार के बाद हत्या की घटना को लेकर बंगाल में आग लगाने के लिए अपनी पार्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यह बांग्लादेश है, मुझे बांग्लादेश से भी प्यार है। वे हमारी तरह बोलते हैं और हमारी संस्कृति साझा करते हैं, लेकिन याद रखें, बांग्लादेश एक अलग देश है और भारत एक अलग देश है। 'मोदी बाबू अपनी पार्टी का इस्तेमाल यहां आग लगाने के लिए कर रहे हैं। अगर आप बंगाल जलाएंगे, तो असम, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। हम आपकी कुर्सी गिरा देंगे।' बंगाल के गरीब लोग ढाकी, धामसा मादोल, आदिवासी नृत्य, लोक शिल्पी और बाउल से रोजगार करते हैं। इससे उनका घर चलता है, लेकिन केंद्र सरकार ने इन्हें बंद कर दिया है। ये हम नहीं होने देंगे, हम प्रधानमंत्री की कुर्सी हिला देंगे। नौ अगस्त को कोलकाता के जीआर कर अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद से पश्चिम बंगाल देश की राजनीति का केंद्र बन गया है। राजनीतिक दल एक-दूसरे पर ना सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, बल्कि अब धमकी के लहजे में भी बात हो रही है। सीएम ममता बनर्जी का आरोप है कि भाजपा एक युवती की मौत पर आम लोगों की भावनाओं का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। बंगाल को बदनाम करने की कोशिश हो रही हैं। घटना की जांच को पटरी से उतारने की साजिश रची जा रही है। ताकि पीड़िता और उसके परिवार को न्याय न मिले। ममता बनर्जी क्या महिला डॉक्टर को सच में न्याय दिलाना चाहती हैं? यदि ममता सरकार को न्याय दिलाना था तो फिर सुप्रीम कोर्ट में 21 वकीलों की फौज क्यों खड़ी की है? क्यों नहीं घटनास्थल से सबूत मिटाने वालों पर कार्रवाई की? क्यों नहीं आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ करने वालों पर एक्शन लिया। क्यों आरजी कर अस्पताल के आंदोलित डॉक्टरों को धमका रही हैं? ममता ने कहा कि आंदोलनकारी चिकित्सकों के प्रति शुरू से ही मेरी सहानुभूति रही है, क्योंकि वे अपनी सहकर्मी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। घटना के इतने दिन बीत जाने के बावजूद हमने डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। हम आपका दर्द समझते हैं, लेकिन अब काम पर लौट आएं, क्योंकि मरीज परेशान हैं। लेकिन ममता सरकार ,डॉक्टरों को सुरक्षा का भरोसा क्यों नहीं दे पा रही हैं? इसलिए आंदोलित डाक्टरों ने मांगे पूरी होने तक आंदोलन समाप्त करने से साफ इंकार कर दिया। हालांकि महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए पैदल न्याय मार्च निकालने वाली ममता बनर्जी देश की पहली सीएम हैं जो खुद से न्याय मांगने के लिए मार्च निकालती हैं। क्योंकि वो ही पश्चिम बंगाल की सीएम हैं वो ही गृह मंत्री हैं और वो ही स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। फिर ममता बनर्जी किससे न्याय मांगने सड़क पर निकली, यह सब नौटंकी नहीं तो और क्या है?

ममता सरकार की सद्भावना?

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद नृशंस हत्या से पूरे देश में आक्रोश है। कोलकाता हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को विफल बताया है। देशभर में इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। भाजपा लगातार ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही है। यह मुद्दा अब इतना गरमा चुका है कि इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बस बहुत हो गया। उन्होंने कहा, मैं इस घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूं। अब बहुत हो चुका। समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर केस के 20 दिन बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला बयान है। वैसे पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध की यह कोई पहली घटना नहीं है। महिलाओं के साथ जो भी अपराध होते हैं उसके आरोपी को बचाने के लिए ममता सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। आरजी कर अस्पलात की घटना में आरोपियों की पैरवी के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की सुप्रीम कोर्ट में 21 वकीलों की फौज खड़ी कर ही। वकीलों की इस फौज में देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक कपिल सिब्बल भी शामिल हैं। कपिल सिब्बल कांग्रेस के सीनियर लीडर भी हैं। वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के कारण ममता बनर्जी सरकार का केस लड़ेंगे या फिर कोलकाता के आरजी अस्पताल की ट्रेनी महिला डॉक्टर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेंगे। क्योंकि आरजी अस्पताल की ट्रेनी महिला डॉक्टर की जिस नृशंस तरीके से हत्या की गई उसे देखकर तो देश के हर काबिल वकील को महिला डॉक्टर के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। इससे पहले पश्चिम बंगाला के संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों पर आदिवासी महिलाओं का यौन उत्पीड़न एवं जमीन हड़पने का आरोप लगा। ममता दीदी की पुलिस ने भाजपा और हाईकोर्ट के आदेश के दबाव में शाहजहां शेख को गिरफ्तार तो किया, लेकिन उसे वीआईपी बनाकर रखा गया। उसके अदालत में पेश होते समय विक्टरी साइन बनाने वाली तस्वीर देश ने देखी थी। ममता सरकार ने शाहजहां शेख को बचाने की भरपूर कोशिश की। हाईकोर्ट द्वारा संदेशखाली का मामला सीबीआई को ट्रांसफर करने के बाद ही शाहजहां शेख पर सख्त कार्रवाई हो पाई। बंगाल में टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं का इतना आतंक है कि कमजोर तबके के लोग उनका हर जुर्म सहते हैं पर शिकायत किसी से नहीं करते। इस पर भी यदि यह कहा जाए कि केंद्र में तानाशाह की सरकार है और पश्चिम बंगाल में ममता सरकार सद्भावना का विस्तार कर रही है तो आश्चर्य और हैरानी तो होनी ही चाहिए। ●

- **कोलकाता के जीआर कर अस्पताल में महिला डॉक्टर की रेप के बाद नृशंस हत्या कर दी जाती और सरकार का सिस्टम घटनास्थल से सबूत नष्ट कर देता है, क्या ये तानाशाही की श्रेणी में नहीं आता? क्योंकि सबूत मिटाने से अपराधी को सीधा फायदा होता है।**
- **पश्चिम बंगाल को लेकर कांग्रेस बटी हुई है, एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस के सभी बड़े नेता खामौस हैं तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी अकेले ममता सरकार से दो-दो हाथ कर रहे हैं।**

बटेंगे तो कटेंगे

कांग्रेस इतिहास ही बांटने का रहा है, पहले पंडित जवाहर लाल नेहरू ने देश बांट कर पाकिस्तान बनाया, फिर नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को बांटकर बांग्लादेश बनाया और अब राहुल गांधी जातियों के नाम पर हिंदू समाज का बंटवारा चाहते हैं।

बाबू सिंह
वरिष्ठ पत्रकार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार योगी आदित्यनाथ ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आगरा में एक ऐसा बयान दे दिया जिससे विपक्षी दलों की हिंदुओं को बांटने वाली योजना पर पानी फिरता नजर आया। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी एंड कंपनी ने जातीय जनगणना की रट लगा दी थी। यह रट अभी तक जारी है। राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता है जो जातियों के बंटवारे को लेकर इतने मुखर हैं कि कई बार वो खुद भी नहीं जानते कि वो कहां और क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी सवाल उठाते रहते हैं कि भारत सरकार के सचिवालय में कितने अधिकारी आदिवासी, ओबीसी और दलित हैं? प्रयागराज में तो उन्होंने हद ही कर ही। यहां राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पूर्व मिस इंडिया के विजेताओं की सूची देखी है। जिसमें कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी महिला नहीं मिली। 90 प्रतिशत आदिवासी, दलित और ओबीसी की भागीदारी के बिना मिस इंडिया प्रतियोगिता होती हैं, ऐसे देश नहीं चल सकता। यहां तक कि मीडिया के शीर्ष एंकर भी 90 प्रतिशत लोगों में से नहीं हैं। इससे समझा जा सकता है कि राहुल गांधी पर किस हद तक जातीय जनगणना का फोबिया हावी हो चुका है। वो देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी के नेता है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, इतना बड़ा नेता मिस इंडिया में भी दलित, आदिवासी और ओबीसी खोजे तो इसे बचकाना हरकत ही कहा जाएगा। प्रधानमंत्री यदि ऐसे नेताओं को बालक बुद्धि कहते हैं तो इसमें गलत क्या है? हालांकि राहुल गांधी यहां तक कह चुके हैं कि जातीय जनगणना कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कराएंगे तो कोई दूसरा प्रधानमंत्री कराएगा। यानी उन्हें लगता है कि वो जल्दी ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का मकसद 20 प्रतिशत मुस्लिम को एक जुट रखना है और 80 प्रतिशत हिंदुओं को जातियों के नाम पर बांटना है। वैसे कांग्रेस इतिहास ही बांटने का रहा है। पहले पंडित जवाहर लाल नेहरू ने देश बांट कर पाकिस्तान बनाया, फिर नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को बांटकर बांग्लादेश बनाया और अब राहुल गांधी जातियों के नाम पर हिंदू समाज का बंटवारा चाहते हैं?

याद कीजिए 1947 के वो दिन जब कांग्रेस ने भारत के दो टुकड़े किए थे, बंटवारे के बाद किस तरह हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं पर रुह कंपा देने वाले अत्याचार हुए थे, शायद आज की पीढ़ी ने तो बंटवारे का यह इतिहास पढ़ा भी नहीं होगा।

मुस्लिम जातीय जनगणना क्यों नहीं ?

राहुल गांधी हो या यूपी के सपा प्रमुख अखिलेश यादव अथवा बाकी वो राजनीतिक दल जो जातीय जनगणना को चुनावी हथियार बनाए हुए हैं। एक तरह से विपक्षी दल हिंदू जातियों को बांटने की कोशिश में है। इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव हों या शरद पवार, ममता बनर्जी सहित टीवी न्यूज चैनल की डिबेट में चिल्लाने वाले नेताओं में एक भी ऐसा नहीं है जिसने कभी मुस्लिम समाज में शिया, सुन्नी, वहाबी, अहमदिया, बरेलवी, देवबंदी, तुर्क, मुगल, शेख, मनिहार, हलालखोर रंगरेज, सैयद, मेहतर, कसाई, कुरैशी, अल्वी, पिंडारी, मेवाती, वन गुज्जर, घोसी, पठान, घाची, तेली, मशालची, अंसारी, फकीर, कुंजड़े की जातीय जनगणना कराने की बात कभी गलती से भी हो। ये नेता सिर्फ हिंदुओं को ही जातियों में बांटकर राजनीति लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन इन सबके षडयंत्र पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो शब्दों 'बंटेंगे तो कटेंगे' से पानी फेर दिया। सीएम योगी ने आगरा के एक कार्यक्रम में लोगों को राष्ट्र की एकता का संदेश देते हुए कहा-'बंटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे।' याद कीजिए 1947 के वो दिन जब कांग्रेस ने भारत के दो टुकड़े किए थे। बंटवारे के बाद किस तरह हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं पर रुह कंपा देने वाले अत्याचार हुए थे। शायद आज की पीढ़ी ने तो बंटवारे का यह इतिहास पढ़ा भी नहीं होगा। इसलिए सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र भी तब सशक्त होगा जब हम सब एक होंगे। लेकिन 'बंटेंगे तो कटेंगे'। सभी बांग्लादेश की हालत देख रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। वहां हिंदुओं के घरों को आग लगाई जा रही है, हिंदुओं की संपत्ति लूटी जा रही है, हिंदू महिलाओं के साथ दुराचार किया जा रहा है। ऐसी गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। इसलिए एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की कल्पना को स्वीकारना है।

योगी चले हिंदुत्व की ओर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों अपने पुराने रंग में रंगे हैं। हिंदुत्व को लेकर वो अपने पुराने दिनों की तरह मुखर हो गए हैं। शायद योगी का यह रूप ही भाजपा में उन्हें पोस्टर बॉय बनाने में मददगार रहा है, पर मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राजधर्म अपना लिया। पर लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिली करारी हार और पार्टी में उनके खिलाफ उठती आवाज ने शायद उन्हें फिर से अपने पुराने रूप में लौटने को प्रेरित किया है। पिछले कुछ दिनों में उनके फैसलों और उनके बयानों को देखकर लग रहा है कि योगी फिर से हिंदुत्व की ओर चल दिए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार ने उन्हें व्यथित कर दिया है या उसे वो रानजीतिक रूप से हिंदुओं को मोबिलाइज करने के लिए महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। जो भी हो इस पखवाड़े उन्होंने जब भी बांग्लादेश को लेकर मुंह खोला चर्चा का केंद्र बन गए। उत्तर प्रदेश के आगरा में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए 26 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर बदले हुए थे। उन्होंने हिंदुओं को चेतावनी दी कि बंटेंगे तो कटेंगे। उनके इस बयान से विपक्ष बोखला गया और योगी पर समाज को बांटने का आरोप लगाने लगा। हालांकि योगी भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा मुखिया अखिलेश यादव और एआईएमआईएम मुखिया असद्दुदीन ओवैसी उनके (योगी) खिलाफ जितना बोलेंगे उतना ही वो यूपी में और मजबूत होंगे। योगी आदित्यनाथ अब भाजपा के बड़े नेताओं की श्रेणी में आते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं लिहाजा वो जो बोलते हैं उस पर पूरा देश गौर करता है यहां तक कि पड़ोसी देश पाकिस्तान भी योगी के बयानों पर प्रतिक्रिया करता है।

बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत पर विपक्ष खामौश ?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही कहा कि एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, विपक्ष के कान खड़े हो गए। मुख्यमंत्री योगी यही नहीं रुके उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब को दुष्ट बताते हुए कहा कि उसका संबंध भी इसी आगरा से था। आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दी थी और मुगल बादशाह से साफ कह दिया था कि तुम चूहे की तरह ऐसे ही तड़पते रह जाओगे, लेकिन हिन्दुस्तान पर तुझे कब्जा नहीं करने देंगे। यह कोई पहला मौका नहीं था बल्कि योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले कम से 4 मौकों पर अपने ऐसे तेवर दिखाएं जिसमें उनका पुराना

विपक्षी मुस्लिम समाज में शिया, सुन्नी, वहाबी, अहमदिया, बरेलवी, देवबंदी, तुर्क, मुगल, शेख, मनिहार, हलालखोर रंगरेज, सैयद, मेहतर, कसाई, कुरैशी, अल्वी, पिंडारी, मेवाती, वन गुज्जर, घोसी, पठान, घाची, तेली, मशालची, अंसारी, फकीर, कुंजड़े की जनगणना क्यों नहीं चाहते।

हिंदुत्ववादी रूप देखा जा सकता है। इसी साल जुलाई के अंत में राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया, जिससे उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 को और अधिक सख्त बना दिया गया। कावड़ यात्रा मार्ग पर सड़क किनारे दुकानदारों व ढ़ाबों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अपना नाम प्रदर्शित करने का आदेश पारित करना भी इसी क्रम में माना गया, जिसे विपक्ष ने मुसलमानों के खिलाफ बताया। योगी ने बांग्लादेश संकट और पड़ोसी देशों में हिंदुओं की स्थिति पर विपक्षी की खामौशी पर कहा था कि विपक्ष वोट-बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करता है। जबकि बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करना और संकट के समय में उनका समर्थन करना हमारा कर्तव्य है और हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। परिस्थितियां कैसी भी हों, हमारे मूल्य अटल रहते हैं। बांग्लादेश में हिंदू होना कोई पाप नहीं है बल्कि एक आशीर्वाद है। अयोध्या रेप केस में समाजवादी पार्टी से जुड़े एक मुस्लिम नेता के आरोपी होने पर उसके खिलाफ मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाल लिया था। आरोपी सपा नेता के प्रतिष्ठानों पर बुल्डोजर की कार्रवाई कराई गई थी। जाहिर है कि योगी एक बार फिर हिंदुत्व का चेहरा बन गए हैं।

योगी के बयान का क्या असर होगा?

इस समय भारत-बांग्लादेश संबंध बहुत नाजुक मोड़ पर है। योगी आदित्यनाथ जैसे सीनियर लीडर्स के बयानों का गलत प्रभाव पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि योगी आदित्यनाथ भारत में जो भी कह रहे हैं उसे तोड़ मरोड़ कर बांग्लादेश में दिखाया जाएगा। इन सबके पीछे भारत विरोधी लॉबी पहले से ही पीछे पड़ी हुई है। भारत विरोधी लॉबी ने ही बांग्लादेश में आई बाढ़ के पीछे भारत का हाथ बता दिया। लिहाजा भारत सरकार को इस मुद्दे पर सफाई देनी पड़ी है। भारत में होने वाली प्रतिक्रियाओं को बांग्लादेश में इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है कि वहां हिंदुओं पर हमले का आधार बना सके। भारत में विपक्ष जिस तरह योगी के बयान की आलोचना कर रहा है उससे भी बांग्लादेश को भारत के खिलाफ आग उलगने का मौका मिलेगा। योगी के बयान पर आग तो भारत में भी उगली जा रही है। बंटेंगे तो कटेंगे वाले योगी के बयान पर अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं उन्हें कम से कम पीएम का रोल प्ले नहीं करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री का है कि दुनिया में किसके साथ कैसे संबंध रखने हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले योगी को समझाएंगे कि दिल्ली के फैसलों में दखल न दे।

योगी ने बदली रणनीति

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पिछले दिनों जिस तरह योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पार्टी में माहौल बन रहा था उससे निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ को रणनीति में बदलाव करना पड़ा। इसके लिए वो हार्ड कोर हिंदुत्व के अपने पुराने रूप में लौटने के लिए मजबूर हो गए। इसके साथ ही यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। योगी समझते हैं कि अगर उपचुनावों में उन्होंने कमाल कर दिया तो पार्टी में उनकी पहले जैसी साख फिर बन जाएगी। भाजपा भी कमोबेश यही समझती है। उसे पता है कि हिंदुओं के ध्रुवीकरण के अलावा उत्तर प्रदेश में जीत की गारंटी और कुछ भी नहीं है। विकास का मुद्दा यहां नहीं चलता। उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान जातिवाद सबसे ऊपर रहता है। जिस तरह समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों और दलितों को एकजुट किया है अगर उससे निपटना है तो हार्डकोर हिंदुत्व की राह पर ही चलना होगा। हालांकि विधानसभा उप चुनावों में समाजवादी पार्टी पीडीए की जगह एमवाई फार्मूले पर काम कर रही है। अखिलेश यादव हों या उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव और गोपाल यादव कोई भी पीडीए का नाम तक नहीं ले रहा है। सब मुस्लिम यादव समीकरण बैठाने में लगे हैं। क्योंकि जिन विधानसभा सीटों पर उप चुनाव होने हैं वहां पीडीए का कोई समीकरण कारगर नहीं है। वहां सिर्फ एमवाई समीकरण ही कारगर है।

भारत को कट्टरपंथ से खतरा?

बांग्लादेश की तरह भारत में भी कट्टरपंथ हावी होने की कोशिश में है, प्रतिबंधित पीएफआई के अंडर ग्राउंड एजेंट अभी भी भारत में गजवा-ए-हिंद का ख्वाब देख रहे हैं, पीएफआई का संबंध बांग्लादेश के आतंकवादी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन और प्रतिबंधित संगठन सिमी से रहा है।

कृष्ण कुमार चौहान

बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पर कट्टपंथियों ने हिंसा और दरिंदगी का जो नंगा नाच किया वो सभी लोकतांत्रिक देशों के लिए सबक है। बांग्लादेश के विपक्षी दलों की तरह ही भारत में भी विपक्ष खासतौर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनके सहयोगी व प्रवक्ता लगातार युवाओं और छात्रों को रोजगार, आरक्षण, बेरोजगारी के नाम पर भड़काने की पूरी कोशिश में जुटे रहते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में भारत को पूरी तरह सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि बांग्लादेश की तरह भारत में भी कट्टरपंथ हावी होने की कोशिश कर रहा है। प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के अंडर ग्राउंड एजेंट अभी भी भारत में गजवा-ए-हिंद का ख्वाब देख रहे हैं। पीएफआई का संबंध बांग्लादेश के आतंकवादी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन और प्रतिबंधित संगठन सिमी से रहा है। देश में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट यानी सिमी पर बैन लगने के चंद माह बाद ही पीएफआई का गठन भी हुआ था। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से केंद्र सरकार ने सितंबर, 2022 में पीएफआई पर पांच साल के लिए पाबंदी लगाई थी। सरकार ने पीएफआई पर गुप्त एजेंडा चलाकर एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाने और आतंकवादी संगठनों से जुड़े होने का दावा किया था। पीएफआई पर भले ही सरकार की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया हो, लेकिन उसके एक्टिव सदस्य गुप्त रूप से अपना अभियान चला रहे हैं। पीएफआई का स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसी तरह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) नाम का राजनीतिक संगठन भी पीएफआई से संबद्ध है। पीएफआई से जुड़ा छात्र संगठन और राजनीतिक दल कट्टरपंथियों के बीच राजनीति करता है। कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में तो एसडीपीआई 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ चुका है। एसडीपीआई के लोकसभा प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने वालों में पीएफआई से जुड़े लोग ही शामिल थे। केरल के वायनाड से ही 2019 में राहुल गांधी सांसद चुने गए थे। अब उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से लोकसभा का उप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। पीएफआई भले ही प्रतिबंधित संगठन हो, लेकिन उसके सदस्य गुपचुप तरीके से गजवा-ए-हिंद की तैयारी कर रहे हैं। इसका प्रमाण 30 मार्च 2024 को तब मिला जब ईडी ने अब्दुल खादर पुत्तूर, अंशद बदरुद्दीन और फिरोज को गिरफ्तार किया। ये तीनों पीएफआई के लिए फिजिकल ट्रेनर के रूप में काम कर रहे थे। यानी गजवा-ए-हिंद के लिए युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। हालांकि तीनों की गिरफ्तारी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की गई। लिहाजा भारत की खुफिया एजेंसियों को पीएफआई और इससे जुड़े छात्र संगठन और राजनीतिक संगठन पर कड़ी और पैनी नजर रखने की जरूरत है। क्योंकि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने उग्रवादी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन और जमात-ए-इस्लामी को प्रतिबंधित किया था, लेकिन यही संगठन शेख हसीना के खिलाफ साजिश रचते रहे और एक दिन तख्ता पलट कर दिया।

ईडी ने सनसनीखेज खुलासा किया था जिसमें ईडी अधिकारियों ने दावा किया था कि जुलाई, 2022 में बिहार की राजधानी पटना में पीएफआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रैली को संबोधित करने के दौरान हमले की खतरनाक योजना बनाई थी।

मोदी पर भी हमले का प्लान था

पीएफआई खुद को सामाजिक संगठन कहता है। इस संगठन ने कभी चुनाव नहीं लड़ा है। किंतु सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) नाम का राजनीतिक संगठन पीएफआई की ही एक इकाई है, जो चुनाव आयोग में पंजीकृत है और चुनाव भी लड़ती है। जब एनआईए और ईडी ने जांच की और पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारे तब पता चला कि पीएफआई चरमपंथी और कट्टरपंथी संगठन है। लिहाजा 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी। एनआईए की जांच में इस संगठन के कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के सबूत मिले थे। एनआईए के डोजियर के मुताबिक यह संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि यह संगठन मुस्लिमों पर धार्मिक कट्टरता थोपने और जबरन धर्मांतरण कराने का काम भी करता रहा है। एनआईए ने पीएफआई पर हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप भी लगाया था। इतना ही नहीं यह संगठन युवाओं को कट्टर बनाकर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए भी उकसाता रहा है। पीएफआई के खिलाफ जांच कर रही एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा भी किया था। ईडी अधिकारियों ने दावा किया था कि जुलाई, 2022 में बिहार की राजधानी पटना में पीएफआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रैली को संबोधित करने के दौरान हमले की खतरनाक योजना बनाई थी। इसके लिए संगठन ने पटना में बाकायदा ट्रैनिंग कैंप भी लगाया था। पीएफआई द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। इसके लिए कई सदस्यों को ट्रेनिंग देने का काम किया था। इतना ही नहीं यह संगठन वित्तपोषण के लिए कई विदेशी ताकतों के संपर्क में भी था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2022 मे न केवल पीएम मोदी पर हमले का प्लान था बल्कि पीएफआई अन्य हमलों के लिए भी टेरर मॉड्यूल तैयार कर रहा था।

क्या चाहते हैं कांग्रेस नेता?

प्रतिबंधित पीएफआई का जो इरादा है वो कुछ कांग्रेस नेताओं से मिलता जुलता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा कह चुके हैं कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं। राहुल गांधी विदेश जाकर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसे में हमें सावधान और सतर्क रहकर सोचने की जरूरत है। क्योंकि जिस दिन ये पश्चिमी देश भारत में लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर घुसे, उस दिन निश्चित ही बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं। भारत सरकार को यह भी देखना होगा कि क्या विपक्ष हिंदू समुदाय को जातियों में बांटकर भारत को कमजोर तो नहीं कर रहा? भारत में इंडिया गठबंधन खासकर कांग्रेस ने जिस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में 'आरक्षण खत्म होगा' और 'संविधान बदला जाएगा' का डर दिखाकर चुनाव की पूरी व्यवस्था को अलग रंग दिया, कहीं वो ताकतें देश में बांग्लादेश वाली स्थिति तो नहीं पैदा करना चाहती हैं? जिस तरह देश के कुछ राजनीतिक दल धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों को डरा रहे हैं और बहुसंख्यकों को जातियों में बांट रहे हैं। उन्हें आरक्षण, जाति जनगणना और हिस्सेदारी के नाम पर भड़का रहे हैं, कहीं वो भारत में बांग्लादेश की तरह तख्तापलट कर सत्ता पर काबिज होने की कोशिश तो नहीं हैं? क्योंकि पिछले दस वर्षो में देश में जिस तरह से आंदोलन खड़े किए गए। जिस तरह से सीएए और किसान आंदोलन के नाम पर सड़कों को घेरा गया, दिल्ली दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की जान गई। किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को समर्थन देकर उग्र बनाया गया। लाल किले के प्राचीर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा जिस तरह से भड़काऊ गतिविधियों को अंजाम दिया गया। तिरंगे के साथ जिस तरह से लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराया गया। जिस तरह से देश की संस्थाओं को बदनाम करने और उसके खिलाफ लोगों के मन में भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के सुर में सुर मिला रहे हैं वो कहीं भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति को यहां दोहराने की कोशिश तो नहीं है?

बांग्लादेश में कट्टरपंथ के हवाले

बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ छात्र आंदोलन कट्टरपंथियों ने हाइजैक कर लिया और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी सत्ता छोड़कर देश से भागना पड़ा। जिस तरह के हालात बांग्लादेश में बने उसे देख कर ऐसा नहीं लगता कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, वो बांग्लादेश तक ही सीमित रहने वाला है। क्योंकि जब अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकी ताकतें किसी देश में हस्तक्षेप करती हैं तो ऐसा ही होता है। इसके पहले अफगानिस्तान और श्रीलंका में भी ऐसा हो चुका है। हालांकि श्रीलंका की परिस्थिति अलग थी। वहां फ्री की योजनाओं की वजह से अर्थ व्यवस्था चरमरा गई थी, वहां राशन, पानी, डीजल सब खत्म हो चुका था। जबकि बांग्लादेश में ऐसा नहीं था। शेख हसीना अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए संजीदा थी और इसके लिए वो लगातार काम भी कर रही थी। फिर भी मान लिया जाए कि प्रदर्शनकारी आरक्षण की वजह से शेख हसीना से नाराज थे तो फिर हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्या क्यों की गई? क्यों हिंदू अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों में आग लगाई गई? क्यों तोड़फोड़ और लूटपाट की गई? क्यों हिंदु अल्पसंख्यकों से जबरन नौकरी से त्याग-पत्र लिखवाए गए। कट्टरपंथी सरकारी विभागों को हिंदू विहीन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हो या बाकी मानवाधिकार संगठन, बांग्लादेश के कट्टरपंथी किसी की नहीं सुन रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद है बांग्लादेश को हिंदू विहीन करना। शरिया कानून लागू करना। ऐसे में सवाल यही है कि क्या वाकई में बांग्लादेश की जनता शेख हसीना से नाराज थी? क्योंकि शेख हसीना के पीएम पद से इस्तीफा देने और बांग्लादेश छोड़ने के बाद तो बांग्लादेश में शांति स्थापित हो जानी चाहिए थी।

- **30 मार्च 2024 को ईडी ने अब्दुल खादर पुत्तूर, अंशद बदरुद्दीन और फिरोज को गिरफ्तार किया, ये तीनों पीएफआई के लिए फिजिकल ट्रेनर के रूप में काम कर रहे थे, यानी गजवा-ए-हिंद के लिए युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे।**
- **बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने उग्रवादी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन और जमात-ए-इस्लामी को प्रतिबंधित किया था, लेकिन यही संगठन शेख हसीना के खिलाफ अंदरखाने साजिश रचते रहे और एक दिन तख्ता पलट कर दिया।**

लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई शेख हसीना की सरकार ने ये सोचा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान की राह पर चलकर बांग्लादेश में भी सेना के इशारे पर तख्तापलट की साजिश होगी और वह भी छात्र आंदोलन की आड़ में, जिसमें देश की आतंकी और कट्टरपंथी ताकतें भी शामिल होंगी। छात्रों का जो आंदोलन बांग्लादेश में देखने को मिला, यह सिर्फ बांग्लादेश तक ही सीमित है, ऐसा सोचना आत्मघाती हो सकता है। शेख हसीना लोकतांत्रिक तरीके से चुनावी प्रक्रिया के जरिए चौथी बार चुनकर सत्ता पर काबिज हुई थी। लेकिन पूर्व पीएम बेगम खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और बांग्लादेश के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन और जमात-ए-इस्लामी यह पचा नहीं पा रहे थे। यही प्रतिबंधित संगठन छात्रों के भेष में आरक्षण के खिलाफ आंदोलन में घुसे और बांग्लादेश में जो हुआ वो दुनिया ने देखा और देख रही है।

24 साल में 16 फीसदी बढ़े मुसलमान

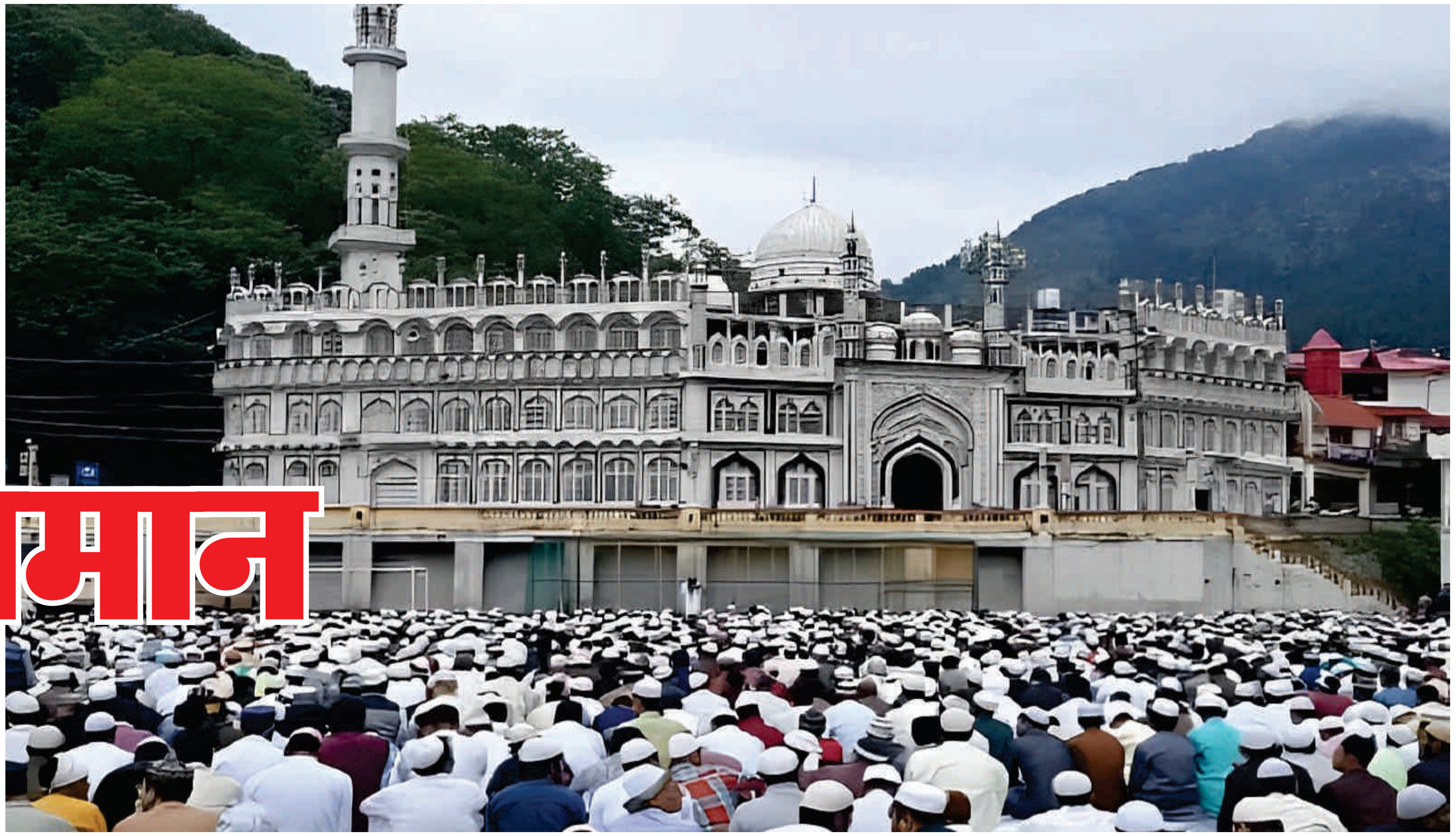

धर्म नगरी ऋषिकेश में कोई मुस्लिम नहीं था, पर अब शहर के चारों तरफ मुसलमान बस गए हैं, नैनीताल जिले के रामनगर व हल्द्वानी में मुस्लिम आबादी ने नदियों के किनारे सिंचाई, वन और रेलवे की जमीन पर घर बना लिए है, नैनीताल शहर में मुस्लिम करीब दसगुना बढ़ गए हैं।

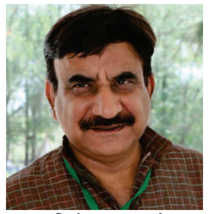

दिनेश मानसेरा
वरिष्ठ पत्रकार

देवभूमि उत्तराखंड में अगले कुछ बरसों में जनसंख्या असंतुलन सबसे बड़ी समस्या बन जाएगा। हालांकि उत्तराखंड की भाजपा की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने भी इस समस्या को गंभीरता से समझ लिया है, खबर है कि डेमोग्राफी चेंज होने से रोकने के लिए राज्य की धामी सरकार भविष्य में कुछ कड़े और बड़े फैसले ले सकती है। क्योंकि देवभूमि में डेमोग्राफी चेंज को नहीं रोका गया तो एक दिन शांत रहने वाले उत्तराखंड में भी हिजाब को लेकर बवाल होगा। लालच देकर, दबाव डालकर या दूसरे कारणों से धर्मान्तरण भी कराया जाएगा। लव जिहाद और लैंड जिहाद तो मैदानी जिलों से लेकर पहाड़ी जिलों तक में पता नही कब से चल रहा है। हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर बसने वालों में सबसे ज्यादा मुस्लिम है। इसलिए रेलवे को अपनी ही भूमि खाली कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हल्द्वानी में ही मलिक का बगीचा में पुलिस पर पथराव और आगजनी की घटना इसी साल जनवरी में देश और प्रदेश देख चुका है, ये एक तरह से बढ़ती मुस्लिम आबादी का ही नतीजा था। यह सब 2000 में राज्य गठन के बाद 24 साल में हुआ है। इस अवधि में उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी बढ़कर 16 प्रतिशत हो गई है। हैरानी की बात ये है कि उत्तराखंड के चार मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल में तो मुस्लिम आबादी 32 प्रतिशत से ज्यादा पहुंच गई है। मुस्लिम आबादी बढ़ने के साथ उत्तराखंड में 400 से अधिक अवैध मदरसे भी संचालित हो गए लेकिन सरकारें व सरकारी सिस्टम सोता रहा। मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा कांग्रेस के शासनकाल में बढ़ी है। हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते उत्तराखंड में मुस्लिमों के बीच ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी आकर बस गए। सरकारी आकंड़ों के मुताबिक 2000 में उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में मुस्लिम आबादी डेढ़ प्रतिशत के आसपास थी। जो लगातार बढ़ रही है। यहां तक कि मुस्लिम आबादी उत्तराखंड के सीमांत जिलों में भी फैल गई है। इसके विपरीत पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में 50 वर्षों में मुस्लिम आबादी सिर्फ 2 फीसदी के आसपास ही है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना उत्तराखंड से 26 साल पहले 1971 में हुई थी। तब से लेकर अब तक मुस्लिम आबादी दो प्रतिशत के आसपास इसलिए है क्योंकि हिमाचल में सख्त भू-कानून है। इसलिए मुस्लिम आबादी का विस्तार नहीं हो पाया। यही वजह है कि आज तक हिमाचल प्रदेश में कोई मुस्लिम विधायक विधानसभा में नहीं पहुंच पाया। इसके विपरीत उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी 16 प्रतिशत होने का अनुमान है।

हरिद्वार में 34 प्रतिशत मुस्लिम

असम के बाद उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ी है। इस बढ़ती आबादी को राज्य में जनसंख्या असंतुलन की समस्या माना जा रहा है। उत्तराखंड के मैदानी जिलों के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण ऐसे हो गए है कि यहां मुस्लिम वोट निर्णायक की भूमिका में आ गया है। लिहाजा अब मैदानी जिलों में भाजपा के लिए विधानसभा सीट निकालना स्वप्न जैसा हो गया है। उत्तराखंड के चार मैदानी जिलों में से हरिद्वार में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी हो गई है। यहां कुल आबादी का करीब 34 प्रतिशत हिस्सा मुस्लिम है। इसी तरह ऊधमसिंह नगर जिले में भी 32 फीसदी मुस्लिम आबादी हो गई है। नैनीताल और देहरादून जिलों में मुस्लिम आबादी तीस-तीस प्रतिशत है। अब पौड़ी जिले के मैदानी इलाके में भी मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ने लगी है।

देवभूमि में डेमोग्राफी चेंज को नहीं रोका गया तो एक दिन शांत रहने वाले उत्तराखंड में हिजाब को लेकर बवाल होगा, लालच देकर धर्मान्तरण भी कराया जाएगा, लव जिहाद और लैंड जिहाद तो मैदानी जिलों से लेकर पहाड़ी जिलों तक में पता नहीं कब से चल रहा है।

उल्लेखनीय है कि 2001 में राज्य के पहाड़ी जिलों में मुस्लिम आबादी डेढ़ प्रतिशत थी जो तेजी से बढ़ी है। हरिद्वार में तो सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी का विस्तार हुआ है। 2011 में उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी 13.9 प्रतिशत थी जो 2022 में 16 प्रतिशत से ज्यादा हो जाने का अनुमान है। यूपी से सटे हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर और देहरादून जिलों में यूपी, बिहार, झारखंड, असम, बंगाल के मुस्लिमों ने बसावट कर ली है। इसलिए उत्तराखंड भारत में असम के बाद सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी वाला राज्य बन गया है। मुस्लिम बहुल केरल और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर देवभूमि उत्तराखंड से भी कम है।

हिमाचल में सख्त भू-कानून

पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश जिसकी भगौलिक सरंचना उत्तराखंड से एकदम मेल खाती है, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हिमाचल को भी देवभूमि कहा जाता है और उत्तराखंड को तो देवभूमि का दर्जा प्राप्त है ही। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल हुआ था। तब यहां मुस्लिम आबादी कुल राज्य की आबादी का दो प्रतिशत से कुछ कम थी और आज ये आबादी 2.1 प्रतिशत है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह हिमाचल प्रदेश का सख्त भू-कानून है। इस कानून की वजह से राज्य से बाहर का कोई भी व्यक्ति यहां जमीन नहीं खरीद सकता अलबत्ता उसे लीज पर अवश्य ले सकता है। इस कानून की वजह से ही हिमाचल प्रदेश अभी तक हिंदू आबादी वाले राज्य के रूप में संरक्षित है। 2001 में हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम आबादी 1,19,512 थी। इसके दस साल बाद यानी 2011 में यह आबादी बढ़कर 1,49,881 हो गई थी। 2022 में इसके 1,63,820 होने का अनुमान लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश की तुलना में उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी ने भू-कानून नहीं होने की वजह से तेजी से पांव पसार लिए। यानी उत्तराखंड में औसतन हर दस साल में दो प्रतिशत मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर दर्ज हो रही है। जबकि असम में औसतन हर दस साल में 3.3 प्रतिशत मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। केरल में 1.9 और पश्चिमी बंगाल में मुस्लिम आबादी बढ़ने की दर 1.8 प्रतिशत है। मुस्लिम आबादी के ये वो आकंड़े हैं जो उत्तराखंड के जनसंख्या रजिस्टर में दर्ज हैं। लाखों की संख्या में बाहरी राज्यों से आए मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जो किराए पर रह रहे हैं, जो धीरे-धीरे यहां के स्थाई निवासी हो जाएंगे। क्योंकि उत्तराखंड में उनके बसने में हिमाचल प्रदेश की तरह कोई रोक-टोक नहीं है।

- **देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल में तो मुस्लिम आबादी 32 प्रतिशत से ज्यादा पहुंच गई है, मुस्लिम आबादी बढ़ने के साथ उत्तराखंड में 400 से अधिक अवैध मदरसे भी संचालित हो गए, लेकिन सरकारें व सरकारी सिस्टम सोता रहा।**
- **हिमाचल प्रदेश को जनवरी 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, तब यहां मुस्लिम आबादी कुल राज्य की आबादी का दो प्रतिशत से कुछ कम थी और आज ये आबादी 2.1 प्रतिशत है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह हिमाचल प्रदेश का सख्त भू-कानून है।**

सरकार के राजस्व विभाग की भ्रष्ट कार्यप्रणाली भी बढ़ती मुस्लिम आबादी की एक बड़ी वजह है। जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मुस्लिम आबादी को यहां बसने दे रही है। इसके उदाहरण देहरादून जिले में आसानी से मिल जाएंगे।

अवैध मदरसे और मस्जिद बनी

मुस्लिम आबादी में अवैध मदरसों, मस्जिदों और मजारों की भी भरमार हो गई है, सरकारी जमीनों पर कब्जे हो चुके है। यहां तक की जंगल की जमीन पर अंदर तक जाकर मुसलमानों ने अवैध कब्जा कर लिया है और जंगल में बहुमूल्य वन संपदा का दोहन कर रहे हैं। मुस्लिम आबादी में यूपी बिहार के लोग तो है ही। जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में बांग्लादेश और म्यांमार से आए रोहिंग्या भी बसते जा रहे है। ये लोग पहले असम, बंगाल, झारखंड से अपने आधार कार्ड बनवाते है, फिर उत्तराखंड आकर, यहां के मुस्लिम जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में बस जाते हैं। मुस्लिम जनप्रतिनिधियों को राजनीतिक संरक्षण मिला रहता है जिनके दम पर वो विधानसभा में पहुंचते रहे है। सबसे खतरनाक तो उत्तराखंड के सीमांत जिलों में मुस्लिम आबादी का बढ़ना है। एक जानकारी के मुताबिक कभी उत्तरकाशी में मुस्लिम वोटरों की संख्या 150 के आसपास हुआ करती थी और ये अब 5000 से भी ज्यादा हो गई है। देहरादून के विकास नगर में 6000 मुस्लिम वोटर हुआ करते थे जो अब 32 हजार हो गए है। हरिद्वार जिले में कुंभ क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो चारों तरफ मुस्लिम आबादी नजर आती है। ऊधमसिंह नगर जिले में यूपी से लगते सीमा क्षेत्र में मुस्लिम आबादी ने डेरा डाल दिया है। देहरादून में सेलाकुई, विकासनगर, सहसपुर क्षेत्र जो यूपी के सहारनपुर जिले से लगता है, मुस्लिम बाहुल्य हो चुका है। यहां तक की धर्म नगरी ऋषिकेश जहां कभी कोई मुस्लिम नहीं रहता था अब शहर के चारों तरफ यहीं समुदाय रह रहा है। नैनीताल जिले के रामनगर और हल्द्वानी शहर में मुस्लिम आबादी ने नदियों के किनारे सिंचाई, वन और रेलवे की जमीन पर कब्जे कर घर बना लिए है। नैनीताल शहर में ही मुस्लिम आबादी ने करीब दसगुना की वृद्धि कर ली है।

सख्त भू-कानून की जरूरत

उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित भू-कानून विशेषज्ञ समिति के सदस्य अजेंद्र अजय के मुताबिक देवभूमि का स्वरूप बचाए रखने के लिए और जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के लिए हिमाचल प्रदेश की तरह सख्त भू-कानून की जरूरत है अन्यथा ये उत्तराखंड राज्य सीमावर्ती राज्य होने की वजह से आंतरिक सुरक्षा जैसी समस्याओं से घिर जाएगा। राजनीति के जानकर विनय कोहली कहते हैं कि उत्तराखंड में अब बारह से पंद्रह विधानसभा सीट ऐसी है जहां भाजपा कभी चुनाव नहीं जीत पाएगी, इनमें हरिद्वार जिले की ज्वालापुर, उधम सिंह नगर की जसपुर, नैनीताल की हल्द्वानी सीट शामिल हैं। क्योंकि यहां धीरे धीरे मुस्लिम वोटर्स बढ़ रहे है जो कभी भी भाजपा को वोट नहीं देते है। यानी जनसंख्या असंतुलन से सबसे ज्यादा उत्तराखंड की राजनीति प्रभावित होने वाली है। राज्य की भाजपा सरकार को अब इस बात की चिंता सताने लगी है कि जल्दी ही कोई कानून नहीं बनाया गया तो राज्य का मूल देव स्वरूप कहीं बिगड़ न जाए। सरकार ने भू-कानून में सुधार के लिए एक समिति भी बनाई हुई है। जिसके द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार को अमल करना है। ●

सोच बदलने से थमेगी यौन हिंसा

पुलिस 50 फीसदी रेप केस दर्ज ही नहीं करती है, पुलिस पीड़िता को सामाजिक प्रतिष्ठा का डर दिखाकर समझोता करा देती है या टरका देती है, एक तरह से पुलिस केस दर्ज न करके दुष्कर्मियों का हौसला बढ़ाती है, पुलिस वही केस दर्ज करती है जहां पीड़िता दोषियों को सजा दिलाने पर अड़ जाती है।

पारस अमरोही
लखनऊ

हमारे शहरों-कस्बों और गांवों में यौन अपराधों के अलग-अलग रूप सामने आ रहे हैं। कई क्षेत्रों में ऐसे यौन अपराधों में सामंती पृष्ठभूमि के दबंग लोगों के अलावा राजनेता, सिरफिरे और पुलिस लोग भी शामिल दिखाई देते हैं। किंतु दुर्भाग्य से हाईलाइट वही केस होते हैं जो हाईप्रोफाइल होते हैं, बाकी गरीब और कमजोर तबके की पीड़ित महिलाओं और बच्चियों की आवाज उठाने वाले कहीं नजर नहीं आते। शहरों-कस्बों और गांवों में गरीब परिवारों के खास किस्म के बेरोजगार-बेहाल युवा लंपट इस तरह के अपराधों की तरफ तेजी से मुखातिब होते हैं। समय-समय पर मध्यवर्गीय सहकर्मी, अफसर, प्रॉपर्टी डीलर-नेता या बड़े बाबा-तांत्रिक भी आरोपी बनते रहे हैं। पर संपन्न या रौबदार पष्ठभूमि के लोगों पर यौन हिंसा के आरोप कम लगते हैं और लगते हैं, तो छानबीन के दौर उन्हें राहत मिलती रही है या फिर वे किसी न किसी तरह बरी होते रहे हैं। प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद 'एक बाबा' को हिरासत में लेने में दस दिन लग जाते हैं। फिर भारत की अदालतों में चलने वाले मुकदमों में सजा की दर बहुत कम है। यह भारत जैसे विकासशील देश और विकसित देशों के बीच एक बड़ा अंतर है। ऐसे में कड़े से कड़ा कानून भी क्या करेगा? सभाओं-जुलूसों या टीवी चैनलों पर लगने वाली 'फांसी दो, फांसी दो' के नारे खास किस्म के 'लोकप्रियतावाद' की अभिव्यक्ति हैं, समस्या का समाधान नहीं है। अपराध और अपराधियों को खुराक देने वाले सियासी दलों और राजनेताओं की सोच को बदलने की जरूरत है। क्योंकि एक दरिंदा कोलकाता की डाक्टर बेटी की रेप के बाद निर्ममता से हत्या कर देता है तो आक्रोशित देश भर में डाक्टरों के आंदोलन को केंद्र की सत्ताधारी पार्टी से जोड़ दिया जाता है। यहां तक कि डाक्टरों को भाजपा का सपोर्टर बता दिया जाता है।

असंवेदनशील महिला सीएम

16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में 23 साल की छात्रा निर्भया के साथ चलती बस में नाबालिग सहित 6 लोगों ने गैंगरेप किया था। इस गैंगरेप की घटना के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया था। उस समय दिल्ली में शीला दीक्षित और केंद्र में कांग्रेस के डा.मनमोहन सिंह की सरकार थी। कितने अफसोस की बात है कि तब एक टीवी इंटरव्यू में शिला दीक्षित ने कहा था कि मीडिया ने निर्भया केस को बहुत बढ़ाकर दिखाया। शीला दीक्षित ने इसके पीछे क्राइम रेट का तर्क देते हुए कहा था कि निर्भया जैसी तमाम घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन मीडिया में उन्हें बहुत कम जगह मिलती है। महिला मुख्यमंत्री की इसी सोच ने तब शायद उन्हें निर्भया को श्रद्धांजलि देने तक से रोक दिया गया था। कांग्रेस की इसी सोच ने पश्चिमी बंगाल के मामले में इंडिया गठबंधन के नेताओं के मुंह पर ताला लगा दिया है। यही नहीं जो राजनेता 2012 में निर्भया के बारे में तर्क दे रहे थे कि वह इतनी रात को बाहर निकली ही क्यों थी? तो क्या लड़कियां रात में बाहर निकलेंगी तो पुरुषों को यह अधिकार मिल जाएगा कि वो उनके साथ कुछ भी करें? क्या लड़कियों के साथ दुष्कर्म करके, मार डाला जाएगा? कोलकाता में भी कुछ ऐसे ही तर्क सत्ताधारी दल टीएमसी के नेताओं द्वारा दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वह लड़की सेमिनार रूम में उस वक्त क्या कर रही थी? सेमिनार रूम में गई ही क्यों थी? राजनेताओं के इन कुतर्को पर हैरानी होती है। कोलकाता में डाक्टर बेटी की रेप और हत्या के बाद पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बैकफुट पर हैं। सुप्रीम कोर्ट तक पश्चिमी बंगाल सरकार और पुलिस को फटकार लगा चुका है।

अपराध और अपराधियों को खुराक देने वाले सियासी दलों और राजनेताओं को सोच बदलनी होगी, एक दरिंदा कोलकाता की डाक्टर बेटी की रेप के बाद हत्या करता है तो देश भर में डाक्टरों के आंदोलन को केंद्र की सत्ताधारी पार्टी से जोड़ दिया जाता है।

रेप का सबूत मिटाने के लिए हत्या?

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए जघन्य रेप एंड हत्याकांड की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की पुलिस को अक्षम ठहराकर मामला सीबीआई को सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जघन्य कांड की गंभीरता को देखते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट की अपील पर देश भर के डॉक्टरों ने अपना आंदोलन भी स्थगित कर दिया। कोलकाता कांड के बाद देश भर के डाक्टर सुरक्षा की गारंटी मांग रहे थे। नकारा कोलकाता पुलिस पर अदालत को विश्वास नहीं था इसलिए आरजी कर अस्पताल की सुरक्षा में सीआईएसएफ लगाई गई है। किंतु जिस तरह से इस मामले को राजनीति का हथियार बनाया जा रहा है और ट्रेनी डाक्टर की बलात्कार के बाद हत्या की जांच में पुलिस की विफलता साबित हुई है उसके बाद देश को सीबीआई और कोर्ट से उम्मीद कि अपराधी शीघ्र ही पकड़े जाएंगे और मरीजों को अस्पतालों में समुचित चिकित्सा मिलेगी। डॉक्टर को भी बिना डरे अपना काम करने का माहौल मिलेगा। डाक्टरों को भी मरीजों के प्रति संवेदना दिखानी होगी। कोलकाता की डाक्टर बेटी के लिए न्याय मांगने वाले अपराधियों को कड़े से कड़ा दंड, फांसी, देने की मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से अपराधी को ऐसा दंड मिलना भी चाहिए जो शेष समाज को यह चेतावनी देने वाला हो कि किसी भी सभ्य समाज में ऐसी नृशंसता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां इस बात को भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि कड़ी से कड़ी सजा का एक परिणाम यह भी निकल रहा है कि अपराधी सबूत मिटाने के चक्कर में बलात्कार के बाद पीड़िता की हत्या का रास्ता अपना रहे हैं।

कहां हैं यौन प्रताड़ना निगरानी कमेटी

दिल्ली की 'निर्भया' से लेकर कोलकाता की 'निर्भया' तक की यह श्रृंखला यही बता रही है कि मानवता के खिलाफ किए जाने वाले बलात्कार के दोषी फांसी जैसे कड़े कानूनों से भी नहीं डर रहे हैं। जिस दिन कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में यह जघन्य कांड हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी बलात्कार की घटनाएं सामने आई। यह स्थिति निश्चित रूप से भयावह है। महिलाओं के प्रति अपराध कहीं भी हों, प्रदेश में किसी भी दल की सरकार हो, वह निंदनीय है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दफ्तरों में यौन प्रताड़ना की निगरानी करने वाली कमेटियां महिला सुरक्षा के लिए ही बनाई गई थीं। सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों में ये निगरानी कमेटियां कहां हैं और क्या कर रही हैं? क्या कोलकाता की डाक्टर के साथ हुआ अपराध इस श्रेणी में आता? पूछताछ निरगानी कमेटी से भी होनी चाहिए। दिल्ली में जब एक महिला की घर से कुछ दूर रात में हत्या कर दी गई थी, तब एक कानून बनाया गया था कि रात में जो कैब महिला को छोड़ने जाएगी, वहां उसके साथ दफ्तर का कोई आदमी होगा, जो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यही नहीं जब तक महिला अपने घर के अंदर नहीं चली जाएगी, तब तक कैब वहां से नहीं जाएगी। किंतु डाक्टर जो लगातार 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं, उन्हें सड़क पर तो छोड़िए, अपने काम-काज के स्थान पर सुरक्षा न मिले तो यह कितनी खतरनाक बात है। इस तरह के महिला डाक्टरों के बयान पढ़े जा सकते हैं, उनमें यही चिंता थी, लेकिन कुछ राजनीतिक दल और उनके समर्थकों को इससे क्या? वे इन महिला डाक्टरों के बयानों से आंखें मूंदकर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को ही धमका रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण होता है तो फिर उन्हें कानून का कोई डर नहीं रहता। कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर जघन्य अपराध को राजनीतिक दल नफे-नुकसान की दृष्टि से देखकर विकसित भारत नहीं बना पाएंगे। यह बात राजनेताओं को अच्छे से समझनी होगी। तभी समाज का स्वास्थ्य सुधरेगा।

- **शहरों-कस्बों और गांवों में गरीब परिवारों के खास किस्म के बेरोजगार-बेहाल युवा लंपट इस तरह के अपराधों की तरफ तेजी से मुखातिब होते हैं, समय-समय पर मध्यवर्गीय सहकर्मी, अफसर, प्रॉपर्टी डीलर-नेता या बड़े बाबा-तांत्रिक भी रेप के आरोपी बनते रहे हैं।**
- **नारी को पुरुष के सहारे की नहीं, बराबर के सहयोग की जरूरत है, पुरुष को समझना होगा कि वह नारी के बिना अधूरा है, इसलिए कड़ा कानून बनाने के साथ समाज की सोच को भी बदलना होगा, क्योंकि सख्त कानून बनने के बाद भी जघन्य अपराध थम नहीं रहे हैं।**

ममता के राज में दर्ज नहीं होते रेप केस

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े बताते हैं कि देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में बलात्कार चौथा सबसे गंभीर अपराध है। आंकड़े बताते हैं कि 2021 में देश में बलात्कार के 31,677 मामले दर्ज हुए थे, यानी हर रोज 86 मामले, हर घंटे में चार दुष्कर्म। इसके पहले 2020 में 28,046 रेप के केस दर्ज हुए थे। जबकि 2019 में बलात्कार की घटनाएं 2021 से भी अधिक 32,033 रिकार्ड हुई थी। यह आंकड़े तो उन अपराधों के हैं, जो थानों में दर्ज हुए। सच तो ये है कि पुलिस 50 फीसदी रेप केस दर्ज ही नहीं करती है। पुलिस पीड़िता को सामाजिक प्रतिष्ठा का वास्ता देकर आरोपी से समझोता करा देती है या फिर थाने से टरका देती है। एक तरह से पुलिस केस दर्ज न करके दुष्कर्मियों का हौसला बढ़ाती है। पुलिस वही केस दर्ज करती है जहां पीड़िता और उसका परिवार दोषियों को सजा दिलाने पर अड़ जाते हैं। बहुत से रेप केस में पीड़िता और उनके परिवार वाले समाज के 'डर' से पुलिस के पास जाने में हिचकिचाते हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो मान लेते हैं कि रेप करने वाला दबंग या राजनीतिक रसूख वाला है इसलिए उसे सजा नहीं मिलगी। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि कोलकाता में तो बलात्कार के सबसे कम मामले दर्ज होते हैं। अब सवाल उठता है कि रेप पीड़ित महिला का भला क्या दोष है। उसके साथ अपराध करने वाला तो पुरुष है, इसलिए आत्मग्लानी पुरुष को होनी चाहिए, लेकिन समाज ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि पीड़िता को संदेह की नजर से देखा जाता है, उसे पीड़ित नहीं अपराधी की समझा जाता है। दोष पुरुष का नहीं स्त्री का माना जाता है। इसलिए समाज को भी सोच बदलनी होगी। रेप करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिले, यह सब चाहते हैं, लेकिन यह बात कोई नहीं समझना चाहता कि महिला अबला और भोग की वस्तु है। ईमानदारी से इस गलत नजरिये को बदलने की कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि अब जीवन के हर क्षेत्र में स्त्री-पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। कई क्षेत्रों में तो वो पुरुषों से आगे भी है। इसके बावजूद उन्हें कमजोर क्यों समझा जाता है? नारी को पुरुष के सहारे की नहीं, बराबर के सहयोग की जरूरत है। पुरुष को समझना होगा कि वह भी नारी के बिना अधूरा है। इसलिए कड़ा कानून बनाने के साथ समाज की सोच को भी बदलना होगा। क्योंकि सख्त कानून बनने के बाद भी जघन्य अपराध थम नहीं रहे हैं।

प्रतिभा

अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन लक्ष्य से चूके

लक्ष्य सेन ने 9 साल की उम्र में बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण की एकेडमी में प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था, लक्ष्य सेन की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैडमिंटन करियर के साथ उन्होंने उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित बीरशेबा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की है।

शालिनी चौहान
नई दिल्ली

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक जीतने चूक गए। भारतीय टीम के स्टार बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक-2024 में हाथ में दर्द के बावजूद मेडल जीतने के लिए संघर्ष करते दिखाई दिए, लेकिन 5 अगस्त को मलेशिया के ली.जी. जिया से 21-13, 16-21, 11-21 से हार गए। लेकिन उत्तरखंड के निवासियों को लक्ष्य सेन पर गर्व है। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बार न सही अगली बार लक्ष्य सेन भारत को पदक अवश्य दिलाएंगे। क्योंकि बैडमिंटन का खेल उन्हें विरासत में मिला है। सेन परिवार में वो तीसरी पीढ़ी के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन्मे लक्ष्य सेन के दादा चंद्र लाल सेन अल्मोड़ा में बैडमिंटन के पितामह भीष्म के नाम से पहचाने जाते थे। लक्ष्य के पिता डीके सेन राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन खेल चुके हैं और राष्ट्रीय स्तर के कोच होने के साथ लक्ष्य सेन के भी कोच हैं। उनके भाई चिराग सेन इंटरनेशनल बैडमिंटन में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लक्ष्य सेन 6 साल की उम्र से ही बैडमिंटन खेल रहे हैं। 9 साल की उम्र में बैडमिंटन खिलाड़ी दीपिका पादुकोण के पिता प्रकाश पादुकोण की एकेडमी में प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। लक्ष्य सेन की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैडमिंटन करियर के साथ उन्होंने उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित बीरशेबा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए लक्ष्य सेन ने टाप-16 में जगह बनाकर क्वालीफाई किया था।

पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के स्टार खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने सिंगल बैडमिंटन के ग्रुप मैच में बेल्जियम के जूलियन कैरेगी को हराया। सेन ने पहला मैच 21-19 तो दूसरा मैच 21-14 से जीता। इस तरह लक्ष्य सेन ने दुनिया के 52वें नंबर के खिलाड़ी जूलियन कैरेगी को 43 मिनट में शिकस्त दे दी थी। उनके आक्रामक खेल को देखकर लग रहा था कि लक्ष्य का लक्ष्य गोल्ड मेडल पर है, लेकिन हाथ में दर्द के कारण वो सैमीफाइनल में हार गए। हालांकि इससे पहले लक्ष्य सेन ने कहा था कि जब हम किसी के साथ मैच खेलते हैं, तो कोर्ट में एडजस्ट करने में समय लगता है। फिर भी उन्हें उम्मीद है कि वह पदक जरूर जीतेंगे।

दादा जी ने घर बनाया बैडमिंटन कोर्ट

लक्ष्य सेन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कई पदक जीत चुके हैं। लक्ष्य सेन ने बर्मिंघम में कामनवेल्थ गेम्स-2022 में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। इसके लिए उन्हें वर्ष 2022 में ही अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 73 साल बाद भारत को पहली बार थॉमस कप दिलाने वाली भारतीय बैडमिंटन टीम के सदस्य रहे लक्ष्य सेन का तब हल्द्वानी, भवाली और अल्मोड़ा में जोरदार स्वागत हुआ था। लक्ष्य सेन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में उनके आवास पर मिले तब अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई पीएम मोदी को भेंट की थी। इसके लिए प्रधानमंत्री ने लक्ष्य का आभार जताते हुए कहा था कि मैंने जीत के बाद फोन पर लक्ष्य से कहा था कि बाल मिठाई तो बनती है और लक्ष्य को उनके कहे ये शब्द याद रहे। लक्ष्य सेन मूल रूप से अल्मोड़ा जिले की सोमेश्वर तहसील के रस्यारा गांव के रहने वाले हैं। अल्मोड़ा के तिलकपुर मोहल्ले में भी उनका घर है और घर में ही बना बैडमिंटन का कोर्ट लक्ष्य सेन के दादाजी की निशानी है। इसी बैडमिंटन कोर्ट में दिन-रात मेहनत कर लक्ष्य सेन ने आज यह मुकाम हासिल किया है। 2018 में लक्ष्य ने जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप अपने नाम की थी। उसके बाद से लगातार बड़े टूर्नामेंट में जीत हासिल कर रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक अपने नाम किया था। अल्मोड़ा के इस युवा प्रतिभा का बैडमिंटन की दुनिया में उदय स्थिर रहा है। वह थॉमस कप जीतने वाली टीम का हिस्सा भी रहे हैं। ऑल-इंग्लैंड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले चौथे भारतीय हैं। लक्ष्य सेन जिस तरह से ओलंपिक 2024 में खेल रहे थे उसे देखकर बैडमिंटन खिलाड़ी गायत्री ने कहा था कि वो लक्ष्य भैया के मैच देख रही हैं और उनका बेहतरीन प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। निश्चित ही लक्ष्य सेन भारत को पदक दिलाएंगे। यदि लक्ष्य के हाथ में दर्द नहीं होता तो निश्चित ही भारत को पदक अवश्य मिलता।

लक्ष्य सेन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कई पदक जीत चुके हैं, लक्ष्य सेन ने बर्मिंघम में कामनवेल्थ गेम्स-2022 में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था, इसके लिए उन्हें वर्ष 2022 में ही अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

लक्ष्य ने दादा से सीखा बैडमिंटन

कहानी बहुत पहले चंद्र लाल सेन के समय से शुरू होती है। चंद्र लाल सेन का जन्म 7 जून 1931 को अल्मोड़ा में हुआ था। चंद्र लाल सेन छात्र जीवन में एक अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी थे। अंग्रेजों को खेलते देखकर उन्होंने 20 साल की उम्र में रामसे इंटर कॉलेज में आउटडोर बैडमिंटन खेलना शुरू किया, जहां से उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। सेन उत्तर प्रदेश सरकार में सेवा में भी रहे हैं। चंद्र लाल सेन ने ही अल्मोड़ा शहर में बैडमिंटन की आधारशिला रखी थी। उनकी दूरदर्शिता, धैर्य, दृढ़ता, कड़ी मेहनत और बैडमिंटन के प्रति जुनून ने अल्मोड़ा की प्रतिभाओं को निखारने और हर साल चैंपियन बनाने वाली नर्सरी बनाई। जिसमें लक्ष्य सेन सबसे आगे रहा है। 1970 के दशक तक चंद्र लाल सेन ने एक खिलाड़ी के रूप में अपना नाम कमाया था। 1973 से 1989 तक पूरे देश में अखिल भारतीय सिविल सेवा टूर्नामेंट में यूपी सिविल सेवा बैडमिंटन टीम का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें वे एक बार विजेता और तीन बार उपविजेता रहे।

पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के स्टार खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने सिंगल बैडमिंटन के ग्रुप मैच में बेल्जियम के जूलियन कैरेगी को पहला मैच 21-19 तो दूसरा मैच 21-14 से हराया, इस तरह लक्ष्य सेन ने दुनिया के 52वें नंबर के खिलाड़ी जूलियन कैरेगी को 43 मिनट में शिकस्त दे दी थी।

लेकिन उनका दिल अल्मोड़ा में था, क्योंकि वे वहां सुविधाएं विकसित करने का सपना देखते थे। बाद में उनकी पोस्टिंग अल्मोड़ा में हुई और उन्होंने यूपी सरकार के खेल विभाग से नियमित पत्राचार शुरू किया। उनकी कोशिशे तब रंग लाईं जब अल्मोड़ा में 1993 में एक बैडमिंटन हॉल बनाया गया। प्रतिभा को निखारने के उत्साह ने उन्हें पूरी तरह से कोचिंग में शामिल कर दिया। उनके एनआईएस प्रशिक्षित बेटे धीरेंद्र कुमार सेन (डीके सेन) याद करते हैं कि उनके पिता खुद ही कोर्ट मार्किंग करते थे और उनके पास दो लकड़ी के खंभे थे, जिससे वे लगभग कहीं भी कोर्ट बना सकते थे, लेकिन खास तौर पर रामसे इंटर कॉलेज के मैदान में वो कोर्ट बनाते थे।

लक्ष्य से पदक की उम्मीद थी

खेल के प्रति उनका लगाव इतना था कि जब उन्होंने तिलकपुर बगीचा इलाके में अपना घर बनाया, तो उसके परिसर में बैडमिंटन कोर्ट बनवाया। अल्मोड़ा के लिए यह एक दुर्लभ बात है। उनके बच्चे और बाद में उनके दो पोते चिराग और लक्ष्य उनके साथ उनके घर के कोर्ट में अभ्यास करते थे। सुबह जल्दी उठ कर वह खिलाड़ियों के साथ स्टेडियम में काफी समय बिताते थे। हर सुबह और शाम उन्हें देखते और उनका मार्गदर्शन करते थे। कौशल, गति और सहनशक्ति इस खेल की विशेषता है। यह उन बहुत कम खेलों में से एक है जो गेंद से नहीं खेले जाते। केवल कड़ी मेहनत ही सफलता दिला सकती है। बैडमिंटन में तो और भी अधिक मेहनत की जरूरत होती है। सीमित संसाधनों के बावजूद अल्मोड़ा में कई टूर्नामेंट आयोजित किए गए, जिसमें अल्मोड़ा के अन्य बैडमिंटन प्रेमियों ने अपना योगदान दिया। इन सबने उत्कृष्टता की संस्कृति को जन्म दिया, जिसका प्रमाण तब मिला जब खिलाड़ी अन्य जगह पर टूर्नामेंट में भाग लेने गए। प्रतिस्पर्धी खेल की उम्र से आगे निकल चुके कई खिलाड़ी अब कोच और खेल प्रशिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। डीके सेन के नेतृत्व में 2001 में गोरखपुर में आयोजित यूपी-स्टेट बैडमिंटन टूर्नामेंट में अल्मोड़ा के बच्चों ने अलग-अलग श्रेणियों के सभी 12 फाइनल मैच जीते थे। तब अल्मोड़ा बैडमिंटन वाकई अपने चरम पर था। इसलिए भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन से पेरिस ओलंपिक में उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश को पदक की उम्मीद थी।

बैडमिंटन खिलाड़ियों को नौकरी में आरक्षण

हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन खेला है। वर्तमान में लक्ष्य सेन जैसे कई बच्चे हैं, जो लगातार इस स्टेडियम में प्रशिक्षण ले रहे हैं। 50 बच्चे रोजना सुबह और शाम प्रैक्टिस करते हैं। यहां बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए शानदार करियर भी है, यदि बच्चे सही से प्रैक्टिस करते हैं, तो वह बहुत आगे तक जा सकते हैं। बैडमिंटन के खिलाड़ी किस तरह से अपना आगे का करियर बना सकते हैं? इसे लेकर अल्मोड़ा के बैडमिंटन कोच अरुण बनग्याल कहते हैं कि यदि खिलाड़ी सही से प्रैक्टिस करें तो बैडमिंटन से बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि कोई भी बच्चा नेशनल या फिर इंटरनेशनल पदक अर्जित करता है, तो उसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी मिल जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट बैडमिंटन के खिलाड़ियों को ऑडिट, इनकम टैक्स, रेलवे, ओएनजीसी के अलावा कई अन्य विभागों में नौकरी देती है। उत्तराखंड सरकार ने भी बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए नौकरी के रास्ते खोल दिए हैं। उत्तराखंड सरकार के हर विभाग में 4 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अगर कोई बैडमिंटन कोच बनना चाहता है, तो वह नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्पोर्ट्स से कोर्स कर सकता है। यदि कोई बैडमिंटन के क्षेत्र में और भी आगे जाना चाहता है, तो वह लक्ष्य की तरह मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंच सकता है।

आपदा

हिमालय में बादल फटने से तबाही

मौसम विज्ञान विभाग कहता है कि किसी एक दायरे में एक घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश होती है तो उसे बादल फटना कहते हैं, यानी किसी एक जगह पर थोड़े ही समय में सैकड़ों गैलन पानी बरसना बादल फटना कहलाता है, ऐसी ही मूसलाधार बारिश इन दिनों पहाड़ी जिलों में ज्यादा दिखाई दे रही है।

डा.वीरेंद्र पुष्पक
वरिष्ठ पत्रकार

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, केरल सहित हिमालयी राज्य दो महीने तक प्रकृति का प्रकोप झेलने के लिए विवश रहे हैं। जून में मॉनसून आने के बाद से अगस्त तक पहाड़ी राज्यों में बादल फाड़ बारिश से भूस्खलन हुआ तो पत्थरों की बरसात होने लगी। यानी प्राकृतिक आपदा सब कुछ खत्म करने पर आमादा रही। बादल फाड़ बारिश के पानी के सामने बड़े-बड़े पुल, सड़कें, घर, होटल, प्रतिष्ठान और वाहन टिक नहीं पाए। सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखरते रहे। भूस्खलन के कारण जिंदा लोग और मवेशी मलवे में दफन हो गए। मॉनसून के सीजन में केरल के वायानाड जिले के चार गांव, चूरलमाला, मुंडक्कई, अट्टमाला और नूलपुझा में 30 जुलाई की रात बादल फटने और भूस्खलन होने से 387 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई जबकि 200 लोग लापता बताए गए। चलियार नदी के आसपास के चार गांवों में 31 जुलाई की सुबह जिंदा लोग नहीं बल्कि लाशें नदी के पानी में तैरती मिली। चलियार नदी से एक दिन में 83 तैरती हुई लाशों को एनडीआरएफ व स्थानीय प्रशासन ने बाहर निकलवाया था। आधिकारिक रूप से 387 लोगों की पुष्टि की गई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और भूस्खलन से 41 लोगों की मौत की खबर है। उत्तराखंड में आई आपदा में 37 लोगों की मौत होना बताया जा गया। मौत के ये आकंड़े अभी बढ़ सकते हैं। इस मॉनसून में हिमालयी राज्यों में बादल फटने की खबरें अचानक बढ़ी हैं। टीवी, अखबार जहां देखों बादल ब्लास्ट की खबरें ही देखने को मिली। जिससे जन-धन की हानि के साथ वन्यजीवों की जान भी खतरे में रही न जाने कितने जीव जंतु भूस्खलन और नदियों के उफान के कारण गायब हो गए। इनका न तो सरकार के पास कोई रिकार्ड है और न ही किसी निजी संस्था ने इसकी चिंता की है। सरकार लगातार बादल फटने की घटनाओं से चिंतित है तो वैज्ञानिक बादल फटने की वजह ढूंढने में लगे हैं। सरकार और वैज्ञानिकों की चिंता इस बात को लेकर ज्यादा है कि कुछ पहाड़ी क्षेत्र में बार-बार या एक ही क्षेत्र के आसपास बादल फटने की ज्यादा घटनाएं क्यों हो रही हैं? बादल फटने की घटनाओं से कई बार कुछ स्थानों पर होने वाला नुकसान चिंता बढ़ाता है। इसलिए वैज्ञानिकों की टीम कुछ चिह्नित क्षेत्रों में बार-बार बादल फटने की घटनाओं की वजह जानना चाहती है।

कैसे पटता है बादल?

बादल कैसे फटता है? बादल फटना क्या होता है? बादल क्यों फटते हैं? मॉनसून में बादल क्यों फटते हैं? हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं अचानक क्यों बढ़ रही हैं? इन सवालों के जवाब विज्ञान से समझे जा सकते हैं। विज्ञान के मुताबिक बादल तब फटता है, जब नमी के साथ चलने वाली हवा एक पहाड़ी इलाके तक जाती है, जिससे बादलों का ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनता है।

पहाड़ी क्षेत्र में बादल फटने की खबरें ज्यादा आई, जिससे जन-धन की हानि के साथ वन्यजीवों की जान भी खतरे में रही, न जाने कितने जीव जंतु भूस्खलन और नदियों के उफान के कारण गायब हो गए, इनका सरकार या किसी संस्था के पास कोई रिकार्ड नहीं है।

इसे क्यूमुलोनिम्बस के बादलों के तौर पर भी पहचाना जाता है। इस तरह के बादल भारी बारिश, गड़गड़ाहट और बिजली गिरने का कारण भी बनते हैं। बादलों की ऊपर की ओर गति को 'ऑरोग्राफिक लिफ्ट' भी कहा जाता है। इन अस्थिर बादलों के कारण एक छोटे से क्षेत्र में भारी बारिश होती है। इसके बाद ये बादल पहाड़ियों के बीच मौजूद दरारों और घाटियों में बंद हो जाते हैं। बादल फटने के लिए आवश्यक ऊर्जा वायु की उर्ध्व गति से आती है। क्लाउडबर्स्ट ज्यादातर समुद्र तल से 1,000 मीटर से लेकर 2,500 मीटर की ऊंचाई तक होता है। आसान भाषा में इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि तापमान बढ़ने से भारी मात्रा में नमी वाले बादल एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और गर्म हवा के संपर्क में आते हैं तो पानी की बूंदें आपस में मिल जाती हैं। इससे बूंदों का भार इतना ज्यादा हो जाता है कि बादल का घनत्व बढ़ जाता है और एक सीमित दायरे में अचानक तेज बारिश होने लगती है। अब सवाल ये उठता है कि पहाड़ों पर आफत बनकर बरसने वाले इन बादलों को इतना पानी कहां से मिलता है? इन बादलों को नमी आमतौर पर पूर्व से बहने वाली निम्न स्तर की हवाओं से जुड़े गंगा के मैदानों पर कम दबाव प्रणाली से मिलता है। कभी-कभी उत्तर पश्चिम से बहने वाली हवाएं भी बादल फटने की घटना में मदद करती हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहता है कि अगर किसी एक दायरे में एक घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश होती है तो उसे बादल फटना कहा जाता है। यानी किसी एक जगह पर थोड़े ही समय में सैकड़ों गैलन पानी बरसना बादल फटना कहलाता है। ऐसी ही मूसलाधार बारिश इन दिनों पहाड़ी जिलों में ज्यादा दिखाई दे रही है। इससे बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं और भूस्खलन होने लगता है। चिंताजनक बात यह है कि बादल फटने की घटनाओं में इजाफा होने के साथ कुछ ऐसे क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, जहां बार-बार बादल फटने की घटनाएं हो रही थीं। जिससे चिंतित उत्तराखंड सरकार ने ऐसे स्थानों को चिह्नित कर वैज्ञानिकों को अध्ययन और शोध करने के निर्देश दिए। बादल ब्लास्ट का कारण जानने में जुटे वैज्ञानिकों ने आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े अधिकारी और वैज्ञानिकों के साथ वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक को भी बादल फटने की इन घटनाओं की मॉनिटरिंग करने के साथ अध्ययन शुरू कर दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में ऐसी घटनाओं के मद्देनजर आपदा प्रबंधन अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की कोशिश में हैं। ताकि इस तरह की आपदा के पीछे की वजह को जानकर उचित प्रबंधन किए जा सकें। क्योंकि वैज्ञानिक मान रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले वर्षों में बादल फटने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। क्योंकि पहाड़ी राज्यों में जंगलों की आग, पेड़ों को अंधाधुंध काटान, कचरे को जलाना, पहाड़ों में ज्यादा वाहनों का आना और जंगलों में अवैध निर्माण भी इस तरह की आपदा के लिए जिम्मेदार हैं।

एसडीआरएफ, एनडीआरएफ व सेना ने किया रेस्क्यू

हिमालयी राज्यों में बादल फटने के साथ भूस्खलन और बाढ़ से होने वाली तबाही को देखकर स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए तथा बड़ी संख्या में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उत्तराखंड की केदारघाटी में भूस्खलन और बारिश की वजह से केदारनाथ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु फंस गए थे। स्थानीय प्रशासन के संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 10374 से ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। गौरीकुंड-सोनप्रयाग हाईवे पर 25 यात्रियों के फंसने की जानकारी मिलने पर वहां से सभी लोगों का रेस्क्यू किया गया। मॉनसून की मूसलाधार बारिश की वजह से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल सहित कई राज्यों में तबाही मची। जहां एक तरफ हिमालयी राज्यों में बादल फाड़ बारिश से आपदा के हालात बने, वहीं मैदानी राज्यों में बाढ़ सब कुछ बहाकर ले जाने को आमादा थी। इससे आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा बर्बादी हिमालयी राज्यों में देखने को मिली। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की केदारघाटी में तो आसमान से आफत बरसी जिसने चारों तरफ भारी तबाही मचाई। जगह-जगह रास्ते बंद हो गए। बहुत सी जगह सड़कों और पुलों का नाम निशान तक नहीं रहा है।

उत्तराखंड में बढ़ीं बादल फटने की घटना

उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में अक्सर बादल फटने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। कई बार मैदानी जिलों में भी मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की जाती है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के माल देवता क्षेत्र में बादल फटा। इस घटना के बाद न केवल सरकार बल्कि वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि यह कोई उच्च पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। इससे एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिर माल देवता क्षेत्र में बार-बार बादल फटने की घटनाएं क्यों हुई हैं? मैदानी जिलों में अक्सर मूसलाधार बारिश का प्रकोप क्यों दिखाई दे रहा है? इस सवाल का जवाब अध्ययन के तौर पर वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है, लेकिन पर्यावरणविद मानते हैं कि पिछले कुछ समय से यह रिकॉर्ड किया गया है कि उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में बादल फटने की घटनाएं बढ़ी हैं। बादल फटने का कारण ग्लोबल वार्मिंग भी मानी जा रही है। उनका मानना है कि बार-बार बादल फटने की घटनाएं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी हो रही हैं। पर्यावरण में बदलाव ने बादल ब्लास्ट की घटनाओं में इजाफा किया है। हालांकि वैज्ञानिकों के अध्ययन से यह भी पता चलता है कि आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा खतरनाक घटनाएं हो सकती हैं। पर्यावरणविद् मानते हैं कि बादल फटने की घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए इंसान भी जिम्मेदार है, जो विकास के नाम पर विनाश की तरफ बढ़ रहा है।

- **वैज्ञानिक मान रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले वर्षों में बादल फटने की घटनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में जंगलों की आग, पेड़ों का कटान, कचरे को जलाना, पहाड़ों में ज्यादा वाहनों का आना और जंगलों में अवैध निर्माण इसके लिए जिम्मेदार हैं।**
- **बादल फटने पर लोगों को जन-धन दोनों को क्षति होती है, नदी, नालों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ता है, पहाड़ों पर ढलान के कारण पानी तेजी से नीचे की ओर बहता है, ये पानी मिट्टी, कीचड़, पत्थर, मवेशी, इंसान, वाहन सभी को बहा ले जाता है।**

मुश्किल में फंस पर्यटक

मूसलाधार बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जगह-जगह भूस्खलन के कारण स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। खास कर उत्तराखंड के केदारनाथ में पर्यटकों के सामने जान बचाने का संकट पैदा हो गया। हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ वायुसेना ने पर्यटकों का रेस्क्यू कर खतरे से बाहर निकाला। केदारनाथ में बादल फटने से ही भूस्खलन हुआ जिससे पहाड़ से बड़े-बड़े बोल्डर और मलवा हाईवे पर आ गया। जिससे रास्ते बंद हो गए और पर्यटक जहां-तहां फंस गए। इस इलाके में कई जगह बादल फटने से मकानों को भारी नुकसान हुआ। कई जगह सड़कें बह गई, बारिश और भूस्खनल के कारण राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में बिजली का संकट भी पैदा हो गया। बादल फाड़ बारिश से फसले बर्बाद हो गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि पहाड़ी इलाकों में एक दशक में बादल फटने की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। एक अनुमान के मुताबिक अब उत्तराखंड और हिमाचल के उच्च पहाड़ी क्षेत्र में डेढ़ गुना से ज्यादा बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं मॉनसून की बारिश के दौरान ही होती हैं। हालांकि बादल फटने की घटनाएं पहले भी होती थीं। किंतु इसकी संख्या कम होती थी और जन-धन की हानि भी कम होती थी, लेकिन मैदान के मुकाबले पहाड़ी क्षेत्र में बादल फटने से ज्यादा नुकसान होता है। नदियों के किनारे और झरनों के आसपास अतिक्रमण होने के कारण भी आपदा के साथ नुकसान भी बढ़ता है। उत्तराखंड में 2020 में बादल फटने अथवा अतिवृष्टि की 14 घटनाएं हुईं थी जिसमें 19 लोगों की मौत हुई थी। इसमें करीब 250 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। 2021 में बादल फटने की घटनाएं बढ़ कर 50 हो गई। जिसमें 15 लोगों की मौत हुई और 70 जानवर मारे गए थे। करीब 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान प्रदेश को हुआ था। बादल फटने पर लोगों की जिंदगी और संपत्ति दोनों को क्षति पहुंचती है, नदी, नालों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ जाता है। पहाड़ों पर ढलान होने के कारण पानी रुक नहीं पाता, बल्कि तेजी से नीचे की ओर बहता है। ये पानी मिट्टी, कीचड़, पत्थर, मवेशी, इंसान, वाहन सभी को अपने साथ बहा ले जाता है। इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बादल फटने के दौरान ढलान पर नहीं रहना चाहिए। ●

संघर्ष से शिखर पर पहुंचे वेद जी

मुश्किलों भरे वक्त में इंसान किस्मत से लड़ने की ठान ले तो मुश्किलें आसानी से दूर हो जाती हैं, यही तो सिखाया है हमारे आदर्श वेद प्रकाश गुप्ता वेद जी ने उन्होंने किस्मत पर भरोसा करने के बजाये संघर्ष किया, नतीजा सामने आया, रास्ते बनते गए और कांरवा आगे बढ़ता गया।

कृष्ण कुमार चौहान

अमूमन मुसीबत के दिनों में हताश और निराश लोगों को टोने-टोटकों के साथ अघोरी और तांत्रिकों के चक्कर में फंसते देखा जा सकता है। बहुत से लोग मुश्किलों से मुकाबला करने के बजाये किस्मत को कोसने लगते हैं, अखबारों में किस्मत चमकाने वाले बाबाओं के चक्कर लगाने लगते हैं, जिसने जो उपाय बताए उस पर इस लालच में कि कल उसकी किस्मत बदल जाएगी खर्च करने लगते हैं, लेकिन मुश्किलों भरे वक्त में इंसान किस्मत से लड़ने की ठान ले तो मुश्किलें आसानी से दूर हो जाती हैं। किसी टोने टोटके और तांत्रिक की जरूरत नहीं पड़ती, यहीं तो सिखाया है हमारे आदर्श वेद प्रकाश गुप्ता वेद जी ने। जिन्होंने किस्मत पर भरोसा करने के बजाये संघर्ष किया। खुद को अनुशासित किया, कठिन परिश्रम किया और किसी काम में छोटे या बड़े का भेद नहीं किया, नतीजा सामने आया। रास्ते बनते गए, कांरवा आगे बढ़ता गया, एक वक्त वह भी आया जब जो उनके करीब आया उसे अपने अनुभवों से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, जो वेद जी के बताए रास्ते पर ईमानदारी से चल गया वह ऊंचाईयों पर पहुंच गया और जो भटका वह जहां का तहां रह गया। यानी संघर्ष ने वेद जी को एक तरह से पारस बना दिया था। अनुशासन के प्रहरी वेद जी बाहर से जितने सख्त दिखते थे भीतर से उससे कहीं ज्यादा भावुक, मस्त, सरल, धार्मिक और दयालु थे, उनके दरवाजे पर जो भी फरियाद लेकर पहुंचा उसकी हर संभव मदद करना उनके स्वभाव में शामिल था।

राजस्थान से हल्द्वानी तक का सफर

मूल रूप से राजस्थान के झुंझनू जिले के सिमला गांव निवासी बिहारी लाल गुप्ता जी जब हरियाणा के महेंद्रगढ़ में रहते थे तब 29 फरवरी 1944 को उनके परिवार में किलकारी गूंजी तो परिवार में खुशियां मनाई गई। नामकरण संस्कार हुआ तो नवजात को वेद प्रकाश गुप्ता के नाम से पहचान मिली। दो साल की बाल आयु में ही 1946 में वेद जी अपने पिता बिहारी लाल गुप्ता जी के साथ हल्द्वानी आ गए। यहीं उनकी प्रारंभिक शिक्षा-दीक्षा हुई। बाल अवस्था में 12 साल की उम्र में ही यानी 1956 में वेद जी जनसंघ से जुड़ गए, संघ की शाखा में हिस्सा लेने लगे। यहीं से उन्होंने अनुशासन का पाठ पढ़ा। ईमानदारी, कर्तव्य, निष्ठा, कठिन परिश्रम की दीक्षा मिली। वेद जी की बाल अवस्था थी तभी उनके पिता जी बिहारी लाल गुप्ता ने हल्द्वानी में राइस मिल लगाई, कारोबार चला, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब गुप्ता परिवार को कारोबार में घाटा हुआ और आर्थिक स्थिति डगमगा गई, परिवार की स्थिति को देखते हुए छोटी सी आयु में ही वेद जी ने परिवार की मदद की जिम्मेदारी उठाई और मुश्किलों के दिनों में सीतापुर जाकर पेट्रोल पंप पर सेल्समैन का काम किया। छोटी सी उम्र में परिवार का सहारा बने वेद जी घर के करीब ही काम की तलाश करने लगे। बुलंद हौंसले के साथ उन्होंने अपना मिशन जारी रखा और पंतनगर के गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय में उन्हें नौकरी मिल गई। वह नौकरी के साथ पार्टटाइम और भी काम करने लगे। परिवार के हालात बदलने लगे। इस बीच उन्होंने हल्द्वानी में ही रेल बाजार स्थित बाटा के शोरूम पर बतौर सहायक प्रबंधक काम किया। यहां उनकी दोस्ती सेल्समैन सुरेश पांडे के साथ हुई। पांडे बताते हैं कि काम के प्रति वेद जी का समर्पण उन्हें प्रेरणा देता था। आर्थिक स्थिति बेहतर हुई तो वेद जी ने हल्द्वानी में ठेकेदारी के काम में हाथ आजमाया, ठेकेदारी करते हुए ही उन्होंने हल्द्वानी में ही प्लास्टिक के जूते बनाने की फैक्टरी लगा ली। जूते के कारोबार में अपेक्षित मुनाफा न होने पर उन्होंने फैक्टरी बंद की और रियलस्टेट के काम में हाथ अजमाया। यहीं से वेद जी का उदय हुआ और आज इस मुकाम तक पहुंचे।

खाटूश्याम में अटूट आस्था

यह इत्तेफाक ही है कि फरवरी में वेद जी का जन्म हुआ और 1971 की 15 फरवरी को ही वह नैनीताल जिले के रामनगर निवासी कपड़ा व्यापारी मदनलाल जी की बेटी आदेश अग्रवाल के साथ दांपत्य सूत्र में बंधे। वेद जी की जितनी लेखन में रूचि थी उससे कहीं ज्यादा धार्मिक स्थलों के दर्शन करने और विदेश यात्रा में दिलचस्पी थी। उनकी करीबी रिश्तेदार कृष्णा अग्रवाल बताती हैं कि कुछ साल पहले वह परिवार के साथ नैमिषारण्य की यात्रा पर निकले थे। रास्ते में सीतापुर के एक पेट्रोल पंप पर उन्होंने गाड़ी रुकवाई और अपने अतीत में खो गए। वेद जी ने गाड़ी में सवार परिवार के सदस्यों को बताया कि यह वही पेट्रोल पंप है जहां कभी उन्होंने नौकरी की थी। पेट्रोल पंप को देखकर और परिवार से अपने अतीत की यादें ताजा करते हुए वेद जी भावुक हो गए थे। वेद जी ने खुद ही नहीं परिवार के साथ भारत दर्शन किया। हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं बचा, जहां वेद जी के कदम न पड़े हों, उन्होंने भारत दर्शन के साथ श्रीलंका, सिंगापुर, फुकेट आदि देशों की यात्रा भी की। धार्मिक स्वभाव के वेद जी अपने कुल देवता खाटूश्याम जी में इतनी आस्था रखते थे कि उनका मंदिर अपने घर के पास ही बना लिया था। 1992 में इस मंदिर को विशाल रूप दिया गया। उनकी दिनचर्या खाटुश्याम की पूजा के साथ ही शुरू होती थी। वह घर से निकलने से पहले अपने कुल देवता का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते थे। साल में एक बार नहीं अनेक दफा वह खाटूश्याम के दर्शन करने उनके प्राचीन मंदिर राजस्थान भी जाते थे। कुल देवता की उन पर असीम कृपा हुई और ईमानदारी, कड़ी मेहनत ने उन्हें अर्श पर पहुंचा दिया।

वेद जी 12 साल की बाल अवस्था में यानी 1956 में जनसंघ से जुड़ गए, संघ की शाखा में हिस्सा लेने लगे, यहीं से उन्होंने अनुशासन का पाठ पढ़ा, ईमानदारी, कर्तव्य, निष्ठा, कठिन परिश्रम की दीक्षा मिली।

अतीत का नहीं भूले वेद जी

वेद जी खासियत थी कि वह अपने, रिश्तेदारों, दोस्तों और करीबियों को तरक्की करते देखना चाहते थे। वंशीधर भगत न राजनीति में थे और न ही कारोबार में, लेकिन वेद जी के करीबी मित्र जरूर थे। एक दिन वेद जी ने ही उन्हें टेंट हाउस खोलने की सलाह दी, बंशीधर भगत ने उनकी सलाह मानी और टेंट हाउस खोल लिया। इसी टेंट हाउस के बाद बंशीधर भगत की किस्मत ने पलटी मारी और आज वह जिस मुकाम पर हैं वह उत्तराखंड के किसी व्यक्ति से छिपा नहीं है। वेद जी की एक और खासियत यह थी कि वे अच्छे दिनों में अपने अतीत को नहीं भूले, वह अजनबी से भी अपने अतीत के बारे में खुल कर बात करते थे। यही उन्हें तरक्की के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता था। उनके परिवार के सदस्य भी वेद जी के कठिन परिश्रम, ईमानदारी, अनुशासन और धार्मिक प्रवृत्ति के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वेद जी के असमय चला जाना परिवार के लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए गहरा आघात है जो उनकी सलाह की बदौलत आज ऊंचाइयों पर है। वेद जी की यादें उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता आज भी दिखाती रहती हैं।

भ्रष्ट व्यवस्था ने बनाया कलम का सिपाही

वेद जी चूंकि जनसंघ और संघ से जुड़े रहे, लिहाजा वह भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ थे। भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए उन्होंने पहले तरुण भारत अखबार में बतौर नैनीताल जिले के संवाददाता के रूप में काम किया, लेकिन खबरें छापना अखबार के संपादक पर निर्भर करता था, लिहाजा कई बार मायूस होना पड़ता था, वेद जी खुद नौकरी करते थे, लिहाजा अपने नाम से अखबार नहीं निकालना चाहते थे, इसलिए अपने अभिन्न मित्र मुन्ना बाबू राजपूत को अखबार निकालने की सलाह दी। वेद जी ने मुन्ना बाबू राजपूत के साथ मिलकर 1973 में उत्तरांचल दीप साप्ताहिक न्यूज पेपर की स्थापना की। निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता करने के लिए तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार साप्ताहिक उत्तरांचल दीप बंद भी हुआ, लेकिन कलम के सिपाही वेद जी ने मुन्ना बाबू राजपूत के सहयोग से मौका मिलते ही अखबार का पुनः प्रकाशन किया। 2009 में इसी उत्तरांचल दीप का सांध्य दैनिक अखबार के रूप में उदय हुआ। तब से निरंतर यह अखबार बुलंदियों को छू रहा है। आज के दौर की पत्रकारिता से अलग उत्तरांचल दीप की अपनी पहचान है। जब बड़े नाम वाले अखबारों पर बदनामी के दाग लगे तब उत्तरांचल दीप सांध्य दैनिक का दामन पूरी तरह पाक और साफ है। यही वेद जी का सपना था। उन्होंने इसी भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ कलम उठाई थी। उनकी विरासत को उनके पुत्र साकेत अग्रवाल ने संभाला और वेद जी के दिखाए रास्ते पर चलकर उत्तरांचल दीप के सफर को निरंतर ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया। दैनिक अखबार निकालना जितना आसान है, इसे नियमित चलाना उससे कहीं ज्यादा कठिन है, लेकिन कलम के सिपाही वेद जी की इस विरासत को बिना किसी विराम के आगे बढ़ाने का संकल्प साकेत जी ने लिया है। अब उत्तरांचल दीप मासिक मैगजीन के माध्यम से उत्तराखंड की सीमा लांघ कर देश के हिंदी भाषी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि में अपनी पहचान बना चुकी है। वेद जी के इस मिशन को ईमानदारी से आगे बढ़ाकर ही हम अपने आदर्श वेद जी को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं।

सियासी सफर

वेद प्रकाश गुप्ता वेद जी एक ऐसा नाम है जिसकी उत्तराखंड ही नहीं उत्तराखंड के बाहर भी अलग पहचान, अलग शोहरत है। इस पहचान के पीछे वेद जी की ईमानदारी, अनुशासन, कठिन परिश्रम, कार्य के प्रति निष्ठा व समर्पण और बुलंद हौसला रहा। इसी समर्पण की वजह से वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपेयी के करीब पहुंचे। भगत

वेद जी संघ से जुड़े रहे, लिहाजा वह भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ थे, भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए उन्होंने तरुण भारत अखबार में बतौर नैनीताल जिले के संवाददाता के रूप में काम किया, लेकिन कई बार खबरें न छपने से मायूस होना पड़ता था।

सिंह कोश्यारी हों या बीसी खंडूरी जैसे कद्दावर नेता वेद जी का सभी सम्मान करते थे। वेद जी भले ही कट्टर भाजपाई थे, लेकिन उनके रिश्ते कांग्रेसी नेता व पूर्व मंत्री इंदिरा हृदयेश, कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ आदि से भी अच्छे रहे। वह जीवनभर अपने अतीत को नहीं भूले। अलग राज्य बनने से पहले ही पार्टी ने उन्हें भाजपा की राज्य इकाई के कोषाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी सौंप दी थी। यह जिम्मेदारी एक दो साल नहीं बल्कि सालों तक वेद जी ने निभाई। भाजपा में उनका अपना अलग रुतबा और कद था। प्रदेश में उन्होंने भाजपा को हर तरह से मजबूत किया। वह भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में आजीवन कार्य करते रहे। उनकी सकारात्मक सोच ने उन्हें पार्टी में वह सम्मान दिया जो आम तौर पर किसी को नहीं मिलता। राजनीतिज्ञों पर जहां भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप लगते रहते हैं वहीं वेद जी का राजनीतिक जीवन पूरी तरह से बेदाग रहा है। पार्टी को हमेशा उन्होंने कुछ न कुछ दिया, यहां तक कि हल्द्वानी में भाजपा का कार्यालय उनके द्वारा दान में दी गई जमीन पर खड़ा है। जानकार बताते हैं कि हल्द्वानी में भाजपा कार्यकर्ताओं के बैठने का कहीं कोई ठिकाना नहीं था। कभी किसी कार्यकर्ता के घर तो कभी वेद जी के निवास पर भाजपा की टोली इकट्ठा होती और पार्टी को मजबूत बनाने पर चर्चा होती थी। एक दिन वेद जी के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही थी, बैठक में ही कार्यालय बनाने की आवाज उठी तो सबसे पहले वेद जी ने कार्यालय के लिए जमीन देने का ऐलान किया। साथ ही कार्यालय निर्माण में हर संभव मदद की। वेद जी का पार्टी के लिए समर्पण, निष्ठा, आस्था, ईमानदारी को देखते हुए 2007 में सरकार ने उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा देकर कुमाऊं मंडल विकास निगम के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी। राज्यमंत्री का दर्जा मिलने के बाद भी वेद जी ने कभी लालबत्ती का रुतबा नहीं दिखाया। वह जैसे लालबत्ती मिलने से पहले लोगों से मिलते थे वैसे ही राज्यमंत्री का दर्जा मिलने के बाद उपलब्ध रहते थे। सरकार ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी उसे निष्ठापूर्वक निभाया और हमेशा कुमाऊं मंडल विकास निगम की तरक्की का रास्ता खोजते रहे। उनके कार्यकाल में निगम में ऐसे भी कार्य हुए जो वेद जी की यादों को हमेशा तरोताजा रखेंगे। दयालु और धर्म के प्रति आस्थावान वेद जी बाहर से जितने सख्त मिजाज थे भीतर से उतने ही नरम थे। उन्होंने कभी किसी को निराश नहीं किया। उनके बारे में कहावत बन गई थी कि वेद जी अखरोट के जैसे हैं, यानी अखरोट ऊपर से जितना सख्त होता है खुलने के बाद अंदर से उतना ही नरम होता है। वेद जी वेद जी ने कभी किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाई, यदि कोई उनके पास कोई उम्मीद लेकर आया तो वह निराश नहीं हुआ। यही खासियतें वेद जी को हमारे ही नहीं उन्हें जानने वाले हर शख्स के बीच हमेशा जिंदा रखेंगी। वेद जी की पुण्यतिथि पर उत्तरांचल दीप परिवार उन्हें नमन करता है। ●

वन्यजीव

हाथियों को संरक्षण की जरूरत

केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2010 से 2020 के बीच लगभग 186 हाथियों की मौत ट्रेन से टकराने के कारण हुई है, यही नहीं रेलवे ट्रैक पर और उसके आस-पास हाथियों की मौत की संख्या लगातार बढ़ रही है।

डॉ. दीपक कोहली
गोमती नगर, लखनऊ

भारत में ट्रेन से टकराकर हाथियों की मौत की घटनाएं चिंताजनक हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले दस सालों में इस समस्या की गंभीरता स्पष्ट हुई है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 2010 से 2020 के बीच लगभग 186 हाथियों की मौत ट्रेन से टकराने के कारण हुई है। यही नहीं रेलवे ट्रैक पर और उसके आस-पास हाथियों की मौत की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाथियों को बचाने के प्रयासों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) एक मजबूत सहयोगी के रूप में तेजी से उभर रही है। हाथी भारत की एक मुख्य प्रजाति है और इसे भारत के प्राकृतिक धरोहर वन्यजीव के रूप में नामित किया गया है। भारत में हाथियों की संख्या 25,000 से 30,000 के बीच है, जिसके कारण इस प्रजाति को संकटग्रस्त घोषित किया गया है। आज इनका विचरण क्षेत्र पहले के मुकाबले घटकर सिर्फ 3.5 प्रतिशत रह गया है, जो अब हिमालय की तलहटी, उत्तर-पूर्व, मध्य भारत के कुछ जंगलों और पश्चिमी और पूर्वी घाटों के पहाड़ी जंगलों तक ही सीमित है। कर्नाटक देश में हाथियों की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य है। भारत में हाथियों की आबादी के लिए एक गंभीर और महत्वपूर्ण खतरा उनके आवास विखंडन का है। देश के विशाल वन क्षेत्रों को मानव बस्तियों, कृषि भूमि और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं द्वारा छोटे-छोटे व अलग-अलग टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया है। वन्यजीवों के ये खंडित आवास हाथियों के लिए कुछ भरण-पोषण प्रदान करते हुए, उनके आवागमन की स्वतंत्रता और महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच को प्रतिबंधित करते हैं। यह विखंडन हाथी प्रजाति के प्रजनन के विकल्पों को भी सीमित करता है, जिससे लंबे समय तक आनुवंशिक अड़चनें उत्पन्न होती हैं और झुंड की तंदुरुस्ती में कमी आती है।

फसलों पर हाथियों की निर्भता बढ़ी

हाथियों का अपने आवास क्षेत्रों के बीच बार-बार, आना-जाना उन्हें सड़कों और रेलवे लाइनों के करीब लाता है। एक मादा हाथी का विचरण क्षेत्र लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ होता है और विखंडित आवासों के युग में इतनी दूरी तय करने पर सड़क या रेलवे क्रॉसिंग अथवा रेल लाइन की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। सौभाग्य से सभी हाथियों के रास्ते में ये खतरे पैदा नहीं होते हैं। बांदीपुर, मुदुमलाई और वायनाड के हाथी मौसमी ग्रीष्मकालीन प्रवास पर जाते हैं। वे पानी और हरी घास दोनों के लिए काबिनी बांध के बैकवाटर की ओर जाते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि तमिलनाडु और केरल के बीच हाथियों के 18 रास्ते हैं। किंतु संसाधनों के लिहाज से मनुष्यों और हाथियों के बीच प्रतिस्पर्धा एक और महत्वपूर्ण चुनौती है। जलवायु परिवर्तन जैसे कारण इस प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करके बढ़ाते हैं। जैसे-जैसे संसाधन कम होते जाते हैं, हाथी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए फसलों को चारे के स्थान पर उपयोग करने लगते हैं, जिससे स्थानीय किसानों के लिए आर्थिक नुकसान होता है। यानी एलिफेंट रेंज के करीब रहने वाले किसानों को लाखों रुपये की फसल और संपत्ति का नुकसान होता ही है। इसके अलावा शिकार और आवास विनाश जैसी मानवीय गतिविधियों, पारिस्थितिक तंत्रों के भीतर शिकारी और शिकार के संतुलन को बाधित करती हैं। यह व्यवधान कुछ शिकार प्रजातियों के वन्यजीवों में जनसंख्या वृद्धि का कारण बन सकता है। हाथियों के साथ संसाधन प्रतिस्पर्धा को और तीव्र कर सकता है तथा संभावित रूप से फसलों पर हाथियों की निर्भरता और बढ़ सकती है।

उत्तराखंड में 23 वर्षों में 508 हाथियों की मौत हुई है, इनमें से 29 हाथी ट्रेन से कटकर मरे हैं, 184 हाथी प्राकृतिक मौत मरे, आपसी संघर्ष में 96 हाथी मारे गए, विभिन्न दुर्घटनाओं में 78 हाथियों की मौत हुई, करंट से 43 हाथी मारे गए, एक हाथी की जहर खाने से मौत हुई, 71 हाथियों की मौत का कारण पता नहीं चला।

उत्तराखंड में मोतीचूर-चिल्ला कॉरिडोर

भारत की प्राकृतिक धरोहर हाथियों की मौतों को कम करने के उपायों में वन्यजीव गलियारे एक प्रभावी समाधान साबित हो सकते हैं, जो प्रबंधित भूमि से न्यूनतम मानवीय संपर्क के साथ आवास की सुविधा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए उत्तराखंड में मोतीचूर-चिल्ला कॉरिडोर है, जो कॉर्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यानों के बीच हाथियों के आवागमन को सुगम बनाते हैं। यद्यपि मनुष्यों के साथ संघर्ष का हमेशा खतरा उन स्थानों पर हमेशा बना रहता है, जहां हाथी कभी-कभी फसलों को खा लेते हैं, या सड़क और रेल की पटरियों को पार करते हैं। रेल लाइन पार करते समय ट्रेन-वन्यजीव टक्कर की संभावनाएं बनी रहती है। हाथियों की मृत्यु का एक प्रमुख कारण ट्रेन से टकराना भी है। कनाडा में किए गए अध्ययनों से ट्रेन-चालित चेतावनी प्रणालियों की प्रभावशीलता का पता लगाया गया है, जो चमकती रोशनी और ध्वनियों का उपयोग करके ट्रेनों के करीब आने वाले जानवरों को सचेत करती हैं। कैमरों से एल्क और भालू जैसे बड़े जानवरों में सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्ज की गई , जिन्होंने चेतावनी प्रणाली सक्रिय होने के साथ ही पटरियों को जल्दी छोड़ दिया। हालांकि इन प्रणालियों की सीमाएं हैं, खासकर सीमित दृश्यता वाले क्षेत्रों जैसे घुमावदार पटरियों में। यहां श्रव्य चेतावनी महत्वपूर्ण हैं। इसके विपरीत उच्च ट्रेन गति जानवर को आने वाली ट्रेन को सुनने की क्षमता में बाधा डाल सकती है।

रेल लाइनों पर जियोफोनिक सेंसर

वन्यजीव क्षेत्र वाले जंगलों से गुजरते समय ट्रेन के चालक को कब गति कम करनी चाहिए? जंगल में जहां एलिफेंट रेंज है वहां कितनी गति रखनी चाहिए? यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय रेलवे के पास ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का एक विशाल नेटवर्क है। ये दूरसंचार का समर्थन करते हैं और डेटा प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से ट्रेन नियंत्रण के लिए संकेत संचारित करते हैं। हाल ही में शुरू की गई गजराज नामक प्रणाली में इन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स लाइनों पर जियोफोनिक सेंसर गुजरते हाथियों के गहरे और गुंजायमान कदमों के कंपन को लेने के लिए तैयार किए गए हैं। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित घुसपैठ का पता लगाने वाला सिस्टम सेंसर से डेटा का विश्लेषण करता है। प्रासंगिक विशेषताओं जैसे आवृत्ति घटकों और कंपन की अवधि को निकालता है। यदि हाथी की विशिष्ट कंपन का पता चलता है, तो क्षेत्र में लोकोमोटिव ड्राइवरों को तुरंत एक अलर्ट भेजता है और ट्रेन की गति कम हो जाती है। यह प्रणाली अब उत्तर पश्चिम बंगाल के अलीपुरदुआर क्षेत्र में कार्यशील है, जो अतीत में कई दुखद दुर्घटनाओं का स्थल रहा है। ऐसा नहीं है कि वन्यजीवों के ट्रेन से टकराने पर सिर्फ वन्यजीव को ही क्षति पहुंचती है, बल्कि रेलवे को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। रेलवे से आरटीआई द्वारा मिली एक जानकारी के मुताबिक अगर डीजल से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन से कोई वन्यजीव या पशु टकराता है और ट्रेन रुकती है तो प्रति एक मिनट रेलवे को 20,401 रुपये का नुकसान होता है। वहीं इलेक्ट्रिक ट्रेन के रुकने पर प्रति मिनट यह नुकसान 20,459 रुपये होता है। इसी तरह डीजल से चलने वाली गुड्स ट्रेन के एक मिनट रुकने पर 13,334 रुपये और इलेक्ट्रिक गुड्स ट्रेन के एक मिनट रुकने पर 13392 रुपये का नुकसान होता है। यह वो नुकसान है जो सीधे तौर पर रेलवे को होता है। एक दुर्घटना की वजह से जब कोई ट्रेन रुकती है तो पीछे से आने वाली पेसेंजर और गुड्स ट्रेन स्वभाविक रूप से लेट होती हैं, इससे रेलवे का ट्रेन संचालन कुछ घंटों के लिए लड़खड़ा जाता है। अब ट्रेन में बैठे यात्रियों को कितना नुकसान उठाना पड़ता होगा, इसका अनुमान भी आराम से लगाया जा सकता है।

एक मादा हाथी का विचरण क्षेत्र लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ होता है और विखंडित आवासों के युग में इतनी दूरी तय करने पर सड़क या रेलवे क्रॉसिंग अथवा रेल लाइन पड़ने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है।

जटिल निगरानी और शिकार-रोधी उपायों से लेकर मानव-हाथी द्वंद्व को कम करने तक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अभिनव समाधानों की एक श्रृंखला है। हालांकि सफल कार्यान्वयन के लिए डेटा की उपलब्धता, बुनियादी ढांचे की सीमाओं और नैतिक सवालों जैसी चुनौतियों से पार पाना आवश्यक है। हाथियों के संरक्षण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भविष्य आशाजनक है, जिसमें जाल-विरोधी उपाय, बीमारी का पता लगाना और अवैध हाथी दांत के व्यापार को रोकने जैसी संभावनाएं शामिल हैं। परंपरागत संरक्षण विधियों और मजबूत सामुदायिक सहयोग के साथ मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शक्ति का उपयोग करके, हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं, जहां हाथी सरीके शानदार जीवों की आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी पर स्वछंद विचरण करने की जगह बन सके।

उत्तराखंड में 508 हाथियों की मौत

उत्तराखंड वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड राज्य गठन के बाद 23 वर्षों में 508 हाथियों की मौत कई कारणों से हुई है, इनमें से 29 हाथी ट्रेन से कटकर मरे हैं। 184 हाथी प्राकृतिक मौत मरे। जबकि आपसी संघर्ष में 96 हाथी मारे गए, इसके अलावा विभिन्न दुर्घटनाओं में 78 हाथी मारे गए। करंट लगने से 43 हाथियों की मौत हुई जबकि एक हाथी की जहर खाने से मौत हुई। 71 हाथियों की मौत का कारण पता नहीं चल पाया है। 16 हाथी देहरादून-हरिद्वार रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आए हैं। जबकि लालकुआं-रुद्रपुर रेलमार्ग पर इस अवधि में 11 हाथियों की ट्रेन से टकराकर मौत हुई है। लालकुआं-बरेली रेल मार्ग पर भी दो हाथियों की ट्रेन की टक्कर से मौत हुई है। उत्तराखंड के लिए संतोषजनक बात यह है कि भले ही देश में हाथियों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही हो, लेकिन उत्तराखंड में हाथियों की संख्या में इजाफा हुआ है। 2020 की हाथी गणना के अनुसार, राज्य में कुल 2,026 हाथियों की मौजूदगी है। वयस्क नर और मादा हाथी का लैंगिक अनुपात 1:2.50 पाया गया, जो एशियन हाथियों की आबादी में बेहतर माना जाता है।

भविष्य की चिंता से ग्रस्त इंसान

कोई भी मांसाहारी वन्यजीव अथवा परिंदा बिना भूख के शिकार नहीं करता, पेट भरा होने पर कोई किसी दूसरे जानवर को नहीं मारता, एक बार शिकार करने के बाद जब तक उस पूरे शिकार को उदरस्थ नहीं कर लेता दूसरा शिकार हरगिज नहीं करता।

सीताराम गुप्ता
पीतमपुरा, दिल्ली

पिछले दिनों हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत की जन्मस्थली व गांधीजी के चौदह दिवसीय प्रवासस्थल अनासक्ति आश्रम को देखने की तीव्र इच्छा के वशीभूत कौसानी जाना तय हुआ। दिल्ली से ड्राइविंग करते हुए सीधे कौसानी जा पहुंचे। कौसानी से बागेश्वर व बागेश्वर से नैनीताल होते हुए दिल्ली वापसी की। नैनीताल से दिल्ली के लिए प्रमुख रूप से दो रास्ते हैं। एक काठगोदाम व हल्द्वानी होते हुए और दूसरा कालाढूंगी होते हुए। कालाढूंगी के रास्ते पर कालाढूंगी के पास छोटी हल्द्वानी नामक स्थान है जहां पर एक छोटा-सा अत्यंत व्यवस्थित संग्रहालय है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट संग्रहालय। इसमें जिम कॉर्बेट के जीवन से संबंधित घटनाओं और वस्तुओं को अक्षुण्ण रखने का प्रयास किया गया है। जिम कॉर्बेट एक कुशल शिकारी थे जंगल जिनके लिए दूसरा घर था। बाद में उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया और एक पर्यावरण व प्रकृति प्रेमी, वन संरक्षक तथा कुशल छायाकार बन गए। आज जिम कॉर्बेट के नाम से जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वह जिम कॉर्बेट के प्रयासों का ही परिणाम है। जिम कॉर्बेट के प्रयासों से ही 1935 में वन्य जीव जन्तुओं को बचाने के उद्देश्य से ये संरक्षित पार्क बनाया गया और फिर विकसित किया गया था।

जिम कॉर्बेट महान लेखक भी थे

शुरुआत में ब्रिटिश काल के तत्कालीन गवर्नर मालकम हेली के नाम पर इस पार्क का नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था। स्वतंत्रता के बाद इस पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। बाद में आजादी के बाद 1957 में इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट के सम्मान में जिम कार्बेट नेशनल टाइगर पार्क रख दिया गया। जिम कॉर्बेट एक महान शिकारी, पर्यावरण एवं प्रकृति प्रेमी, वन संरक्षक, कुशल छायाकार ही नहीं थे बल्कि एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। संग्रहालय में एक छोटी सी सुवनीर शॉप भी है जहां जिम कॉर्बेट की लिखी पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। मैंने वहां उपलब्ध जिम कॉर्बेट की सभी पांचों पुस्तकें खरीद लीं और घर आकर सभी पढ़ डालीं। जिम कॉर्बेट के बारे में जानने पर ऐसा लगा कि हिंदी भाषा और साहित्य में फादर कामिल बुल्के का जो स्थान व सम्मान है कुछ वैसा ही स्थान व सम्मान पर्यावरण, प्रकृति व वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में जिम कॉर्बेट का है।

'जिम कॉर्बेट अपनी पुस्तक 'जंगल लोर' में लिखते है, 'प्रकृति में न तो कोई दुख होता है और न ही कोई अफसोस, झुंड में से कोई पक्षी बाज का शिकार बन जाता है अथवा कोई चौपाया शेर या तेंदुए का शिकार हो जाता है तो बाकी बचे हुए पक्षी और वन्यजीव इस बात की खुशी मनाते हैं कि चलो आज हमारा वक्त नहीं आया, उन्हें आने वाले कल की कोई चिंता नहीं होती।' काश हम मनुष्यों को भी आने वाले कल की कोई चिंता नहीं होती।'

- **ब्रिटिश काल के गवर्नर मालकम हेली के नाम पर पहले इस पार्क का नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था, आजादी के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, 1957 में इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट के सम्मान में जिम कार्बेट नेशनल टाइगर रिजर्व पार्क रखा गया।**
- **जिम कॉर्बेट के नाम से जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वह जिम कॉर्बेट के प्रयासों का ही परिणाम है, जिम कॉर्बेट के प्रयासों से ही 1935 में वन्य जीव जन्तुओं को बचाने के उद्देश्य से ये संरक्षित पार्क बनाया गया और फिर विकसित किया गया।**

मनुष्य को भविष्य की चिंता

जिम कॉर्बेट अपनी पुस्तक 'जंगल लोर' में लिखते है, 'प्रकृति में न तो कोई दुख होता है और न ही कोई अफसोस। झुंड में से कोई पक्षी बाज का शिकार बन जाता है अथवा कोई चौपाया शेर या तेंदुए का शिकार हो जाता है तो बाकी बचे हुए पक्षी और जानवर इस बात की खुशी मनाते हैं कि चलो आज हमारा वक्त नहीं आया। उन्हें आने वाले कल का भी कोई एहसास नहीं होता...।' काश हम मनुष्यों को भी आने वाले कल का एहसास नहीं होता। यदि ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। हम भी आने वाले कल अथवा भविष्य की चिंता किए बिना निश्चिंत व निर्दवंद होकर मजे से वर्तमान में जीते। जानवरों को आने वाले कल की कोई चिंता नहीं होती इसलिए वे मजे से जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी स्वाभाविक मस्ती में कभी कोई कमी नहीं आती। भूख लगने पर ही भोजन के लिए हाथ-पैर मारते हैं। कोई भी मांसाहारी वन्यजीव अथवा परिंदा बिना भूख के शिकार नहीं करता। पेट भरा होने पर कोई किसी दूसरे जानवर को नहीं मारता। एक बार शिकार करने के बाद जब तक उस पूरे शिकार को उदरस्थ नहीं कर लेता दूसरा शिकार हरगिज नहीं करता। उनके जीवन में तनाव नामक तत्व होता ही नहीं। जहां तक भूख लगने पर शिकार करने का प्रश्न है, तो ये प्राकृतिक भोजन शृंखला का अंग है जो वन और वन्यजीवन में संतुलन के लिए अनिवार्य है। क्योंकि वन्यजीव, पक्षी, जीव-जंतु प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं और प्रकृति का संरक्षण भी करते हैं, स्वार्थी मनुष्य की भांति पशु-पक्षियों की आवश्यकताएं अनगिनत नहीं होती है। प्रत्येक वन्यजीव, पशु-पक्षी प्रकृति की समृद्धि के लिए कार्य करते है। पृथ्वी पर जीवन चक्र सुचारू रूप से चलाने में यह मुख्य कार्यवाहक होते है, वन्यजीवों और पक्षियों द्वारा ही वन और प्रकृति समृद्ध होती हैं और मानव जीवन को गति मिलती है। जहां प्रकृति समृद्ध है, वहां शुद्ध जल और शुद्ध ऑक्सीजन के स्रोत समृद्ध हैं, प्राणी, वनौषधी, जंगल समृद्ध हैं। मिट्टी उपजाऊ और फसल गुणवत्तापूर्ण तैयार होती है, ऐसी जगहों पर बीमारियां कम और इंसान का सेहतमंद आयुष्मान दीर्घ होता है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या कम होकर ओजोन परत की सुरक्षा बढ़ती है। सुखद वातावरण और पौष्टिक भोजन मिलता है, प्राकृतिक आपदाएं कम होकर मौसम का चक्र भी सुचारू रूप से चलता है, लेकिन मनुष्य, आज या वर्तमान की चिंता करने की बजाय आने वाले कल अथवा भविष्य की चिंता में अधिक डूबा रहता है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी में तनाव और डिप्रेशन बहुत बढ़ गया है। ये ठीक है कि मनुष्य अपने विकास की उस अवस्था में पहुंच गया है जहां उसके लिए भविष्य के बारे में विचार करना भी अनिवार्य है।

जंगलों में कुछ भी अव्यवस्थित नहीं

भविष्य की उचित प्लानिंग तो ठीक है, लेकिन चिंता किसी भी तरह से उचित नहीं मानी जा सकती। कल की चिंता में हम आज का जीवन जीना भूलते जा रहे हैं जिसके कारण हमेशा तनावयुक्त रहते हैं। ये तनाव भविष्य के सुख को भी, जो एक तरह से काल्पनिक है, चट कर जाता है। हम कई बार देश में कई स्थानों पर जंगल राज की बात करते हैं। शहरों में चाहे जो हो जंगलों में कुछ भी अव्यवस्थित नहीं है। कुछ भी काल्पनिक नहीं है। सब कुछ स्वाभाविक व प्राकृतिक रूप से चलता है। वहां परस्पर शोषण की प्रक्रिया भी नहीं है। वन्यजीवों के संसार में संग्रह की प्रवृत्ति भी नहीं पाई जाती। वहां कोई छोटा या बड़ा नहीं है। कोई प्रतिशोध की आग में नहीं सुलगता। कोई बदला लेने की फिराक में नहीं घूमता। वन्यजीवों की दुनिया में मान-अपमान जैसी काल्पनिक परिस्थितियां भी नहीं मिलतीं। अपनी पुस्तक 'जंगल लोर' में जिम कॉर्बेट आगे लिखते है, 'जब मैं नादान था तब नन्हें पक्षियों और हिरणशावकों को बाजों, चीलों व दूसरे जानवरों के पंजों से छुड़ाने की कोशिश करता था, लेकिन जल्दी ही मुझे पता चल गया कि एक की जान बचाने से दो की जान जाती है। शिकारी पक्षियों अथवा जानवरों के जहरीले पंजों की वजह से उनमें से एक प्रतिशत पक्षी अथवा दूसरे नन्हें जानवर ही जीवित रह पाते थे। दूसरी ओर शिकारी जानवर अपना अथवा अपने बच्चों का पेट भरने के लिए फौरन ही दूसरा शिकार कर लेता था। जंगल में कुछ पक्षियों और जानवरों का उत्तरदायित्व प्रकृति में संतुलन बनाए रखने का होता है जिसके लिए प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के साथ-साथ अपना पेट भरने के लिए शिकार करना भी अनिवार्य हो जाता है।' जहां तक संतुलन की बात है तो जीव-जंतुओं की जितनी भी गतिविधियां हैं वे सब प्रकृति के संतुलन को बनाए रखती हैं। उससे प्राकृतिक संतुलन को कोई हानि नहीं पहुंचती। मनुष्य को जंगली जीव-जंतुओं को बचाने की नहीं अपितु उनका आवास न छीनने पर आमादा है। आज मनुष्य न केवल प्रकृति के संतुलन को नष्ट करने पर आमादा है अपितु स्वयं की सुव्यवस्था को भी नष्ट कर रहा है। मनुष्य जीव-जंतुओं के प्राकृतिक आवास को नष्ट करके खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चला रहा है। हम चाहें तो इन जंगली जानवरों से न केवल चिंता व तनाव से मुक्त रहने का सूत्र सीख सकते हैं अपितु अपरिग्रह व सीमित उपभोग द्वारा प्रकृति व पर्यावरण को नष्ट होने से बचाने की कला भी सीख सकते हैं। क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का हद से ज्यादा दोहन, शहरीकरण, ईंधन, रसायनों का अति प्रयोग, प्रदूषण, ई-कचरा, औद्योगीकीकरण, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग अत्यधिक होने से पशु-पक्षी जंगली जानवर, वनौषधी, प्राकृतिक धरोहर तेजी से नष्ट हो रही है। बढ़ती जनसंख्या अपने साथ जरूरतों को बढ़ा रही है। जिससे सीमित संसाधनों में असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने का दबाव बढ़ रहा है। हम विज्ञान और तकनीकी संसाधनों के बिना रह सकते हैं लेकिन इस नैसर्गिक प्रकृति के बिना नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन, पानी, धूप, खाद्य उत्पादन श्रृंखला, प्राकृतिक संसाधन, तापमान का संतुलन यह प्रकृति का उपहार है और वन्य जीवों का संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। ●

आत्मकथा

पाक से भारत तक विधवा का चीरहरण

विधवा चम्पारानी अपने कमीने ससुर, दर्द, अपनी विधवा चचिया सास और विभाजन के साथ जमनादास के डेरे की कहानी को भूल चुकी थी, वह तो केवल वर्तमान में जी रही थी, जबकि जमनादास अपने अतीत को याद करता है तो सिहर जाता है।

नवीन चंद्र दुम्का
पूर्व विधायक

- विधवा के लिए तो घर, बगीचा, खेत-खलिहान, चारागाह में भी बचना मुश्किल था, लिहाजा वह बिना ची चपड़ के पहला शिकार अपने ही ससुर का ही हुई, ससुर के बारे में वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, कि घर में उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा।
- विभाजन के समय मारकाट ने वह पुरानी दुनिया खत्म कर दी, अब विधवा सयानी भी हो चुकी थी, अपने इस्तेमाल की वसूली भी समझ चुकी थी, लिहाजा जब जमनादास ने उसकी तरफ देखा तो उसने भी नजर में उसे समेट लिया और एक नया जोड़ा बन गया।

यह कहानी देश के विभाजन के समय की है, कि कैसे उस दौर में विधवाओं का शोषण किया जाता था। यह कहानी पीड़िता की जुबानी है, जो पहले पिता तुल्य ससुर की शिकार हुई। उसे उसके अपनों ने कैसे रौंदा और फिर समाज के लोगों की बुरी नजर उस पर कैसे पड़ी? बात तब की है जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था, लेकिन आजादी का आगाज हो गया था। यह अहसास हो गया था कि अंग्रेज अब चले जाएंगे। कई तरह के किस्से, कल्पनाएं गांवों और कस्बों में फैली हुई थी। सवाल हो रहे थे कि कैसे जाएंगे? क्या छोड़ जाएंगे? जाएंगे तो फिर कभी नहीं आएंगे क्या? कुछ लोग मानते थे कि इतने न्यायप्रिय शासक चले जाएंगे तो देश का क्या होगा? क्या हमें फिर जमीनदारों के थोकदारों, सरमायेदारों के हवाले कर जाएंगे? इससे थोड़ा हटकर गांव के सरमायेदार, अंग्रेजों का साथ देने वाले जमीनदारों के गुमाश्ते (एजेंट) आदि भी झकाझक सफेद कपड़े पहन कर गांव की चौपाल, शादी-विवाह व सुख-दुख में आसन जमाकर बैठते थे। हर छोटे बड़े गांव कस्बे में इस टाइप के लोगों का 4-6 का जत्था था, धार्मिक कार्यक्रम हो या सुख-दुख कमोवेश यह जत्था लोगों को घेर ही लेता था। किंतु कर्म ऐसे की किसी भी उम्र की महिला सामने पड़ जाए तो इनकी सूरत देखते ही महिला के मुंह से निकलता थू कीड़े पड़े, पाप का घड़ा है, जैसा आशीर्वाद जरूर देती थी। इन महिलाओं ने अपनी दादी, नानी, सास, मोसी, भाभी, ताई और चाची से इनके इतने किस्से सुन रखे थे कि उनको लगता था कि ये आदमी नहीं पूरे सांड हैं। इस श्रेणी के सफेद पोश भी खुद को यही मानते थे कि उनका जितना इलाका है उसके तो वो सांड ही हैं। लेकिन ढोंग व मीठी बातें, हाथ फेरने की कला ऐसी की घात लगाए बैठा वास्तविक बगुला भी शर्मा जाए।

रंगीन मिजाज जमनादास

ऐसे ही एक शख्स थे जमनादास, वो मूल रूप से पाकिस्तान वाले भू-भाग के निवासी थे, लेकिन ननिहाल से कुछ भूमि भारत वाले हिस्से में पहले से मिली ही हुई थी। उसमें खंडहर गौशाला, एक कुआं व कुछ पेड़ थे। आखिरकार मारकाट, लूटपाट, सामूहिक हिंसा, आगजनी, बलात्कार के साथ देश का विभाजन हुआ तो, लोग हिंदुस्तान के लिए निकल पड़े। ऐसे ही हिंदुस्तान पहुंचे 108 लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता था कि कौन कहां का है? इनमें जमनादास भी था, उसने कहा कि उसका डेरा यहां पास में ही है, तो लोगों ने एक स्वर में वहां जाने की हां कर दी। घायल, लुटे-पिटे, मन से मरे और थके लोगों ने कुछ समय बाद हिसाब लगाना शुरू किया कि कौन कहां का है, कौन बिछड़ गया है? इन्हीं में एक बाल विधवा थी जो इस मार-काट से पहले ही विधवा हो चुकी थी। जिसके लिए मार-काट वाले ये दुख, विधवा होने के दृश्य से कम नहीं थे। उसे विधवा हुए 14 साल हो चुके थे। यह समय परिवार के ताने, रोने, बिलखने, कलंकित शब्द सुनते तथा बुजुर्गो के ताने झेलते हुए बीता था, किंतु अब आगे जो होने वाला था वो इस सबसे भी खतरनाक था। ससुर अधेड़ व सास टीबी की रोगी थी। लोगों की नीयत में खोट वह समझ सके इतनी चतुराई उसमें नहीं थी। उसने अपने मायके में इस तरह के संबंधों के मकड़ जाल को न कभी देखा था, न समझा था। उसके लिए तो घर, बगीचा, खेत-खलिहान, चारागाह में भी बचना मुश्किल था, लिहाजा वह बिना ची चपड़ के पहला शिकार तो अपने ससुर का ही हुई। ससुर के बारे में वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, कि घर में उसके साथ ऐसा हो जाएगा। कुछ दिन बाद निरपेक्ष भाव से उसने हल्का सा इशारा घर में ही रहने वाली चचिया सास से किया, तो उसने जो बताया वो दुनिया का पूर्ण सत्य उसकी समझ में आ गया। यानी सास ने उसे अपनी जवानी का अहसास कराया कि कैसे एक दिन जब उसका देवर उसे नोच रहा था तो नशे में धुत उसके चचिया ससुर ने कोठरी का दरवाजा खटखटाया। चाचा न केवल पंच थे बल्कि रसूखदार भी थे। लेकिन चाचा अपने भतीजे से डरता था। फिर उसे कोठरी में देखा तो कहा तेरा यहां क्या काम? इस पर भतीजा खाट के नीचे छिप गया। नशे में धुत चाचा अपना काम करके चला गया। फिर खाट के नीचे से भतीजा निकला और उसने भी अपना अधूरा काम पूरा कर लिया।

विधवा का नया बसेरा

विभाजन के समय मारकाट ने वह पुरानी दुनिया खत्म कर दी, अब वह सयानी भी हो चुकी है। अपने इस्तेमाल की वसूली भी समझ चुकी थी। सो जब जमनादास ने उसकी तरफ देखा तो उसने भी नजर में समेट लिया और एक नया जोड़ा बन गया। तभी डेरे में एक खबर आई कि इस डेरे को यूपी में जमीन एलाट हो गई है। सो वे उस गांव की तरफ चल दिए। बहेड़ी रेलवे स्टेशन से बैलगाड़ी में 10 मील का सफर कर तोको गांव पहुंचे जो पहले कभी आबाद था, लेकिन 30-40 साल पहले किसी महामारी से लोग मर गए या गांव छोड़ कर चले गए थे। तोको गांव में अपना एक जंगल, एक चारागाह था, गांव के एक ओर बरसाती नदी बहती थी। 50 साल के जमनादास व 30 साल की विधवा चम्पारानी ने भी अपने नए अनुभवों के साथ बाकि सब कुछ भूलकर नया बसेरा शुरू किया। 8-10 मील के दायरे में शरणार्थियों की एक और बस्ती थी। धीरे-धीरे एक गांव की चर्चा दूसरे गांव, दूसरे की तीसरे गांव में होने लगी। कभी किसी गांव के तीन-चार पुरुष जत्थे के रूप में पड़ोस के गांव जाते और हाल-चाल पूछते। यानी इनमें कोई अपना या आसपास का तो नहीं है? इसकी भी छानबीन कर लेते, इस तरह एक जत्था 15 दिनों में लौटता था। इनमें से कुछ के बिछड़े परिजन मिले तो कुछ को गांव के या जान पहचान लोग मिलने लगे। इस तरह एक नए समाज की नींव पड़ने लगी। इसी तरह घूमते हुए जमनादास को भी अपनी एक पुरानी संबंधी इमरती मिली। जमनादास में बदलाव आने लगा था। पहले इस तरह की यात्रा दो-तीन माह में एक बार होती थी, लेकिन अब महीने में दो बार होने लगी। वह भी जत्थे के बजाये अकेले। एक दिन जमनादास ने पुरानी संबंधी इमरती की बेटी पर हाथ डालने की कोशिश की, महिला के विरोध से उसकी बेटी जमनादास का शिकार होने से बच गई। हालांकि जमनादास ने महिला को धमकी दी। लेकिन महिला ने बड़ी सरलता से कहा कि यह उचित अवसर नहीं है। फिर कभी मौका देखकर आना, लिहाजा जमनादास लौट गया।

विधवा के बदले तेवर

पाकिस्तान के मूल गांव से यहां तक के लम्बे सफर में इमरती की बेटी उससे बिछड़ भी गई थी, इसलिए वो मानती थी कि जब बेटी बिछड़ी थी तब वो मर्दों का शिकार अवश्य हुई होगी? लेकिन अब वो उसे व्यवस्थित जीवन देना चाहती थी। एक दिन जमनादास अपने डेरे से दो-तीन दिन बाद लौटने की बात कह कर इमरती के गांव पहुंच गया। इमरती भी जमनादास की आदत से परिचित थी। उसने यहां के नए माहौल और संभावित घटना का जिक्र करते हुए पति तथा डेरे के अन्य लोगों से मदद मांगी। सब जमनादास को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गए। जमनादास स्वभाव से जिस कुकर्म के लिए इमरती के गांव पहुंचा था, उसका नतीजा क्या होगा यह उसने सोचा भी नहीं था। उधर पहले से ही जमनादास का इलाज करने के लिए तैयार बैठे लोगों ने उसका ऐसा इलाज किया कि वो भविष्य में शारीरिक सुख लेने लायक भी नहीं रहा। उसका न केलव जानवरों की तरह से बध्याकरण किया बल्कि मलहम पट्टी कर तीन-चार दिन बाद छोड़ भी दिया। घर पहुंचने पर चम्पारानी ने उससे कोई खास पूछताछ नहीं की। लेकिन उसे अहसास पूरा हो गया था। इसलिए गांव में एक अच्छी बैलों की जोड़ी वाले हलिया और 10 मील दूर के पुराने गांव के वासिदें की झोपड़ी चम्पारानी ने अपने डेरे का पास बनवा दी। हलिया खेती में अब चम्पारानी की मदद करने लगा। इससे कुछ लोगों को तकलीफ तो हुई परंतु माहौल को देखकर कोई टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं हुई। सभी लोग महौल के मुताबिक व्यवस्थित होना चाहते थे। इस बीच चम्पारानी गर्भवती हो गई, उसके अब बच्चा होने वाला था। सामान्य सी बात थी, लेकिन एक दिन जमनादास ने उससे पूछा यह क्या है? चम्पारानी ने कहा चुप रहो, यह बच्चा तुम्हारा नहीं है, केवल तुम जानते हो और मैं, लेकिन सारा गांव जानता है कि बच्चा तुम्हारा ही है, इसलिए चुप रहो, अपने कर्मो का पूरा मजा अकेले लो जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। फिर मैं उसका शारीरिक या मानसिक नुकसान क्यों उठाऊं? समय के साथ चम्पारानी ने तीन बच्चों को जन्म दिया। इसी बीच उसने हलिया का घर भी बसा दिया।

विस्थापितों के जीवन में बदलाव

कुछ साल बाद गांव का स्वरूप बदल गया। सरकार ने कुछ पक्के मकान बनवा दिए। नए फलदार पेड़ों पर फल आने लगे। सामूहिक पंपिग सैट लगा दिए गए। घर की दीवारों पर मिट्टी का लेप हो गया था। पशुओं के जत्थे भी हो गए। गांव में किसी तरह की बीमारी न फैले इसलिए डीडीटी का छिड़काव भी कराया गया। छिड़काव करने वाले जत्थे में 15 लोग गांव आए थे लिहाजा वो कहां रुकें। यह सवाल आया तो चम्पारानी ने अपने गोठ में जगह दे दी। खाना बनाने के बर्तन, आटा, चावल भी दे दिया। यह जत्था दो दिन रुका और इसके बाद जहां भी गया वहां चम्पारानी के व्यवहार का यशगान किया। अगले साल फिर जत्थे के दो-चार लोग चम्पारानी के यहां ठहरे और छिड़काव कर चले गए। आसपास में फिर चम्पारानी का गुणगान होने लगा। धीरे-धीरे चम्पारानी के घर और पेड़ों का झुरमुट एक सराय सा हो गया। साथ ही पटवारी, हैडमास्टर, ग्राम सेवक की बैठक भी यहीं होने लगी, सीजन में मजदूरों का जत्था खेतों में काम करने आता चम्पारानी के यहां डेरा जमाता और काम पूरा होने पर चला जाता। कुछ लोग बकरी, भैंस, गाय लेकर आते चम्पारानी के यहां टिकते और जानवार बेचकर चले जाते। अब यह वो पुराना गांव नहीं रहा था। गांव के लोग छोटा-मोटा लोहारी, बढ़ई, टोकरी बुनने काम, दस गांवों में करने लगे। कुछ नए काश्तकार बन गए कुल मिलाकर गांव आबाद व कालाहल पूर्ण हो गया। गांव में बिस्कुट बनाने की भट्टी, चाय की दुकान, परचून की दुकान भी खुल गई। चम्पारानी प्रौढ़ हाने लगी, जमनादास बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगा था, लेकिन सभी कामों में जमनादस की सहमति होती थी, कभी भी उसकी उपेक्षा नहीं होती थी, पर बेबाक निर्णय चम्पारानी के ही होते थे। चम्पारानी का सबसे बड़ा संबल उस पर हुआ सबसे बड़ा अत्याचार ही था। उसकी दृढ़ धारणा थी कि उसके योवनकाल में जो अत्याचार उस पर हुआ वो भी सुरक्षित जगह ससुराल में, वो भी पिता तुल्य ससुर द्वारा ऐसा विभत्स समय दोबारा कभी नहीं आना था। जब वो इस घृणित हादसे को झेल गई, मारपीट और लूटपाट के अंधकारमय समय से निकल आई तो समाज में अब उसके लिए कोई खतरा नहीं बचा था। धीरे-धीरे चम्पारानी सयानी और गांव समाज की पंच बन गई। वास्तव में गांव में इतने बेवाक व असरदार तरीके से राय देने वाला कोई नहीं था, कोई पुरुष भी नहीं क्योंकि किसी को अपनी अतीत की छूटी हुई संपत्ति का गम खाये जा रहा था तो कुछ को बिछड़ने का, कुछ पड़ोसी की तरक्की से परेशान थे, तो कुछ को घरेलू कलह का गम था।

गांव का कायाकल्प

अब गांव में जनगणना के लिए टीमें, नए तरीके से खेती, अच्छे बीज, रसायन, खाद, जानवरों की नस्ल सुधार का प्रचार करने वाले आते तो चम्पारानी के यहां पेड़ों की छाव में बैठते गांव वालों के साथ गोष्ठी करते और चले जाते। क्योंकि तब ग्राम पंचायत में कोई पक्की चौपाल, सामुदायित भवन नहीं होते थे। ग्राम पंचायत तोको 4-5 मील के दायरे में फैली हुई थी। जिसमें बंदोबस्ती गांवों के लोगों का दबदबा था। इस बीच 25 साल निकल गए, चम्पारानी ने दो बच्चों की शादी कर दी। गांव की आबादी में पीढ़ी का परिवर्तन हो गया। नई आबादी और पुरानी आबादी के बीच संबंध बनने लगे। गांव सड़क से जुड़ गए खेती के लिए ट्रेक्टर आ गए। और चम्पारानी ने अपने गांव के 54 किसान तथा 26 अन्य परिवारों को सुझाव दिया कि नई जिंदगी के 25 साल हो गए वैसे तो हम बुढ़ापे की ओर हैं, लेकिन यहां के हिसाब से तो हम भी 25 साल के ही हैं। यह हमारी नई जिंदगी है। गांव वालों ने सुझाव मान लिया और तय किया कि जिस तारीख को इस तोको गांव में पैर रखा था उसे जन्मदिन के रूप में मनाया जाए। बात ऐसी फैली कि कहां 25वां जन्मदिन मन रहा है? अरे वो चम्पारानी है न उसके गांव तोको में कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम में सबने अपने अनुभव सुनाए, लेकिन चम्पारानी ने बेबाक कहा कि वो अपना देश व अपना घर था, लेकिन मेरे लिए वो नरक था, नरक का उसने इशारा भी किया, पर यह गांव मेर लिए स्वर्ग है। इस तरह धीरे-धीरे इस गांव का नाम ही चम्पानगर पड़ गया। चम्पारानी अब अपने कमीने ससुर, अथाह दर्द, अपनी विधवा चचिया सास और विभाजन के साथ जमनादास के डेरे की कहानी को भूल चुकी थी। वह तो केवल वर्तमान में जी रही थी। जबकि जमनादास अपने अतीत को याद करता है तो सिहर जाता है। लेकिन तभी उसे अहसास होता है कि तोको गांव का नाम अब चम्पानगर हो चुका है। जब चम्पारानी नरक में थी तब वो स्वर्ग में था। कभी बिछड़े नहीं फिर भी स्वर्ग-नरक की अदला बदली कैसे हो गई। अब चम्पारानी की बीमारी के बाद मृत्यु हो गई, लेकिन जिसने भी सुना वो उसके दर्शन करने पहुंच गया यह सिलसिला 12वीं तक चला। ब्रह्मभोज के बाद एक बुजुर्ग ने जमनादास के कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना दी कि कोई बात नहीं चम्पारानी नहीं रही लेकिन चम्पानगर तो हमेशा रहेगा। ●

समीक्षा

खेती में विज्ञान एवं तकनीकी

उत्तराखंड की भाषा में साग-सब्जी उगाने के लिए तय भूमि को सग्वाडा कहते हैं, शहरी क्षेत्रों में इन्हें किचन गार्डन कहा जाता है, किंतु चिंतनीय बात यह है कि सग्वाडों की यह जीवनीय परंपरा पहाड़ी गांवों में तेजी से सिमटती जा रही है।

सर्वविदित है कि संपूर्ण मानवीय आहार में एक प्रमुख और अनिवार्य हिस्सा साग-सब्जियों का भी होता है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषकर गांवों में घर के चारों ओर की भूमि सग्वाडे से घिरी होती है। ग्रामीणों के घर-परिवार की संपन्नता और खुशहाली के स्तर को प्रथमतया सग्वाडे ही दृष्टिगौचर करते हैं। उत्तराखंड की भाषा में साग-सब्जी उत्पादन के लिए निर्धारित भूमि क्षेत्र को सग्वाडा कहते हैं। शहरी क्षेत्रों में सामान्यतः इन्हें किचन गार्डन कहा जाता है। किंतु चिंतनीय बात यह है कि सग्वाडों की यह जीवनीय परंपरा पहाड़ी गांवों में तेजी से सिमटती जा रही है। दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में जमीन की अनुउपलब्धता के कारण किचन गार्डन अब बीते दिनों की बात हो गए हैं। लेकिन ये बात दीगर है कि मानव के नैसर्गिक, संतुलित और सस्ते आहार एवं पोषण के रूप में साग-सब्जियों की आवश्यकता हमेशा रहेगी। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि एक स्वस्थ्य व्यक्ति को प्रतिदिन 280 ग्राम सब्जी का सेवन अवश्य करना चाहिए। चिंतनीय बात यह है कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति रोज के भोजन में सब्जी की यह मात्रा औसतन 130 ग्राम और उत्तराखंड में तो इससे भी कम हो गई है। अतः यह एक गंभीर चिंतन-मनन का सवाल है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के दृष्टिगत साग-सब्जियों की उपलब्धता कैसे बढ़ाई जाए? इसका सीधा और सरल समाधान यही है कि वर्तमान मानवीय जीवन शैली में साग-सब्जी उत्पादन की परंपरा को संरक्षित और संवर्धित करने के सरल, सहज और सस्ती वैज्ञानिक तकनीक और तरीकों को खोजा तथा अपनाया जाए। उक्त समसामायिक संदर्भ में, 'भलु लगद-फील गुड' चेरीटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित नवीनतम पुस्तक 'विज्ञान एवं तकनीकी से कम लागत पर साग-सब्जी उत्पादन' एक संदर्भ एवं मार्गदर्शी पुस्तक के रूप में सार्वजनिक हुई है। इस पुस्तक के लेखक उद्यान विशेषज्ञ डॉ. राजेंद्र कुकसाल एवं डॉ. स्मृति कुकसाल हैं।

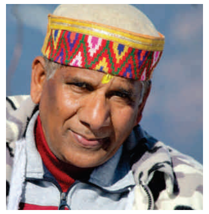

अरुण कुकसाल
चामी, पौड़ी

ग्रामीणों में बढ़ी जागरूकता

'कैरी की सब कुछ हूंद, इले लग्यां छौं।' अर्थात निरंतर कर्म करने से ही सब कुछ संभव है, इसलिए समाज हित में सक्रिय हैं। 'भलु लगद-फील गुड' चेरीटेबल ट्रस्ट का यह ध्येय वाक्य है। इसी सूत्र वाक्य को अपने मन-मस्तिष्क में जागृत कर उससे जीवंत हुए आत्म-बल को लिए 'भलु लगद-फील गुड' चेरीटेबल ट्रस्ट के माध्यम से सुधीर सुंदरियाल एवं हेमलता सुंदरियाल विगत 10 वर्षों से अपने पैतृक गांव डबरा, पौड़ी (गढ़वाल) में रहकर अपने हिस्से की सामाजिक दायित्वशीलता को बखूबी निभा रहे हैं। जीवन का एक लम्बा समय महानगरों में गुजारने के बाद सुंदरियाल दंपति जानते और मानते हैं कि पर्वतीय किसानी जीवन का स्वयं मजबूत हिस्सा बनकर ही किसानों की समस्याओं को जाना-समझा जा सकता है। अतः गांवों में आने से नहीं वहीं निरंतर कर्मशील रहकर हम सुखद सामाजिक बदलाव की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। परिणामतया सुधीर और हेमलता की विगत 10 वर्षीय निरंतर उद्यमशीलता का ही कमाल है कि खेती-किसानी से विमुख हो रहे चौबट्टाखाल क्षेत्र के कई ग्रामीणों में इस ओर सकारात्मकता जगी है। इस क्षेत्र के अधिकांश बंजर खेत अपनी बहुउपयोगिता को प्रदर्शित कर रहे हैं। कृषि, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, जल संरक्षण, वैज्ञानिक चेतना और सामाजिक जागरूकता में उल्लेखनीय उपलब्धियां फील गुड के रूप में उन्होंने प्राप्त की हैं। फीलगुड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, गवाणी, चौबट्टाखाल के माध्यम से वे बहुआयामी रचनात्मक गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इसी कड़ी में 'भलु लगद-फील गुड' द्वारा प्रकाशित 'विज्ञान एवं तकनीकी से कम लागत पर साग-सब्जी उत्पादन' पुस्तक एक अभिनव वैज्ञानिक पहल एवं प्रयोग के तौर पर सामने आई है। लेखक डॉ. राजेंद्र कुकसाल एवं डॉ. स्मृति कुकसाल ने हिमालयी पारिस्थिकीय के केंद्र में बागवानी के दृष्टिगत नवीन वैज्ञानिक चेतना का विस्तार इस किताब की विषय-सामाग्री में किया गया है।

एक स्वस्थ्य व्यक्ति को प्रतिदिन 280 ग्राम सब्जी का सेवन अवश्य करना चाहिए, पर चिंतनीय बात यह है कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति रोज के भोजन में सब्जी की यह मात्रा औसतन 130 ग्राम और उत्तराखंड में तो इससे भी कम हो गई है।

महत्वपूर्ण जानकारियां

लेखकद्वय डॉ. स्मृति कुकसाल ने मुख्यतः पर्वतीय किसानी कार्यों में नवीन वैज्ञानिक तकनीकी को अपनाए जाने की मंशा जाहिर की है। दूसरी ओर अनुभवजनित परंपरागत पद्धतियों की प्रासंगिकता और उपादेयता को भी सार्थकता प्रदान की है। यह पुस्तक दस अध्यायों के फैलाव में समग्रता से साग-सब्जी उत्पादन की हर स्तर की महत्वपूर्ण जानकारियां बताती है। ये अध्याय यथा-पर्वतीय क्षेत्र में सब्जी उत्पादन का महत्व, सब्जी पौध उत्पादन तकनीक, मृदा परीक्षण, जैविक व प्राकृतिक खेती, कीट व्याधि नियंत्रण, विविध सब्जियों की उत्पादन तकनीकी, पॉली हाउस में सब्जी उत्पादन, पाले एवं शीतलहर से फसलों को कैसे बचाएं? मल्चिंग तथा ड्रिप सिंचाई प्रणाली का विस्तार है। सब जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियां यहां पैदा होने वाली फसल को अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाती हैं। यही कारण है कि पहाड़ी अनाज, फल-फूल और साग-सब्जियों की मांग देश-दुनिया में सर्वाधिक रहती है। इस पर भी उल्लेखनीय ये है कि पहाड़ों में अनाज के मुकाबले सब्जियां कम समय और क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन एवं आय देती हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्ष भर साग-सब्जी का उत्पादन होता है। ऐसे मौसम में जबकि मैदानी इलाकों में अधिकांश सब्जियों का उत्पादन नहीं होता है। उन साग-सब्जी का उत्पादन पर्वतीय क्षेत्र में सर्वसुलभ और अधिक लाभकारी व्यवसाय है। पुस्तक में लेखकद्वय ने पर्वतीय अंचलों की ऐसी अनुकूल परिस्थितियों को विश्लेषित करते हुए साग-सब्जी उत्पादन की व्यवहारिक वैज्ञानिक तकनीकियों और तौर-तरीकों का उल्लेख किया है। वैज्ञानिक तरीकों में यथा साग-सब्जी के उत्पादन में उसके आनुवांशिक गुणों, वातावरण, तापमान, रखरखाव, प्रबंधन, उन्नत बीजों की पहचान, मृदा परीक्षण, मृदा को उपजाऊ बनाने के तरीके, क्यारी की तैयारी, बीज बुवाई, पौध रोपण, निराई-गुड़ाई, पौध संरक्षण, भूमि एवं पौध उपचार, खाद, पाले एवं शीत लहर से बचाव, मल्चिंग, कीट व्याधि प्रबंधन, रोगों की पहचान, रोकथाम एवं उपचार, सब्जी को तोड़ने का युक्ति संगत तरीका, जैविक खेती, पैकिंग, परिवहन, भंडारण तथा बेहतर रोजगार सृजन को समझाया है।

ड्रिप सिंचाई के लाभ व प्रकार

लेखकद्वय डॉ. स्मृति कुकसाल ने पुस्तक में पर्वतीय क्षेत्र में प्रमुखता से उत्पादित उन साग-सब्जियों को जिनकी सभी बाजारों में अधिक कीमत पर वर्ष भर मांग रहती है की विस्तृत रूप में चर्चा की है। ऐसी साग-सब्जियों में टमाटर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, फूल गोभी, मटर, फ्रासबीन, भिंडी, कद्दू वर्गीय सब्जियां, खीरा, मूली, आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, अदरक, हल्दी तथा विदेशी सब्जियां-ब्रोकली, एसपैरागस (शतावरी), ब्रशसैल्स स्प्राउट, लैटयूस आदि शामिल हैं। इन सब्जियों की वैज्ञानिक व्याख्या, निहित गुणों, बीज एवं पौध का रखरखाव, खेत की तैयारी और उसको बोने व रोपने की विधियों से लेकर उसके भंडारण की वैज्ञानिक विधियां और बाजार में बेचने के लाभकारी तरीकों को पुस्तक में सुझाया है। पुस्तक को अधिक कारगर स्वरूप देते हुए लेखकद्वय ने पॉली हाउस में सब्जी उत्पादन और ड्रिप सिंचाई प्रणाली को पृथक अध्यायों में उल्लेखित किया है। पॉली हाउस और ड्रिप सिंचाई के लाभ, प्रकार, तरीके, तकनीक, देखभाल एवं प्रबंधन आदि को विस्तार से बताया है। पॉली हाउस और ड्रिप सिंचाई की संचालित योजनाएं एवं प्रक्रियाओं को इन अध्यायों से जाना सकता है। 'भलु लगद फील गुड' चेरीटेबल ट्रस्ट का ध्येय वाक्य 'कैरी की सब कुछ हूंद, इले लग्यां छौं।' (अर्थात निरंतर कर्म करने से ही सब कुछ संभव है, इसलिए समाज हित में सक्रिय हैं।)

पंचतंत्र के चिरकाल संदेश 'उद्यमेन हि सिद्धंते कार्याणि, न मनोरथे।

सुप्तस्य सिंहस्य नहिं प्रवेशंति मुखे मृगा।।'

(अर्थात जिस प्रकार निंद्रा में तल्लीन शेर के मुख में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार उद्यम से ही कार्य पूर्ण होते हैं, न कि मात्र मन की इच्छाओं से, का ही गढ़वाली रूपांतरण है।) इतिहास गवाह है कि उक्त प्रेरक संदेश के मर्म और अर्थ को 1949 में चीनी क्रांति के बाद वहां के युवाओं ने स्वयं अपने जीवन व्यवहार में अपनाया था। जब लाखों चीनी क्रांतिकारी युवाओं ने अपने अर्जित ज्ञान और हुनर का उपयोग शहरों के बजाय दूर-दराज के गांवों में जीवकोपार्जन के अवसरों को तलाश करते हुए उन्हें साकार किया था। मुझे इस पुस्तक को पढ़ते हुए गढ़वाल के इतिहास में दर्ज विक्रम संवत् 1852 (सन 1795) 'बावनी अकाल' और '1920 की स्पैनिश फ्लू महामारी' का ध्यान आया। 'बावनी अकाल' में गढ़वाली लोग कई दिनों तक भूख से बेहाल रहे परंतु उन्होंने अपनी खेती के परंपरागत बीजों को नहीं खाया था। इसी तरह 1920 की स्पैनिश फ्लू महामारी की वजह से उत्तराखंड की जनसंख्या जो 1911 में 22 लाख थी घटकर 1921 में 21 लाख यानी 10 सालों में 1 लाख कम हो गई थी, के समय भी पहाड़ के लोग जान बचाने जगंलों की ओर भागते समय अपने मूल्यवान धन के साथ तोमड़ियों (बीजों) को ले साथ जाना नहीं भूले थे। जीवन के उस कठिन समय में भी उन्हें विश्वास था कि जब तक उनकी खेती-किसानी और ये परंपरागत बीज उनके पास उपलब्ध है, उन पर जीवनीय संकट नहीं आ सकता है। उनका विश्वास सही साबित हुआ उन्हीं बीजों और खेती-किसानी के बदौलत बाद में उनके जीवन में फिर से खुशहाली आ गई थी। इतिहास की ये घटनाएं एक सबक के बतौर हमें याद दिला रही कि आज कोरी बातों से ज्यादा जीवनीय व्यवहार में उद्यमीय अभिवृति अपनाया जाना होगा। तभी परंपरागत ज्ञान, हुनर, अनुभव, वैज्ञानिक शोध और तकनीक की सार्थकता फलीभूत हो पाएगी। प्रस्तुत पुस्तक का सार भी यही है। ●

- **सब्जियों की वैज्ञानिक व्याख्या, निहित गुणों, बीज एवं पौध का रखरखाव, खेत की तैयारी और उसको बोने व रोपने की विधियों से लेकर भंडारण की वैज्ञानिक विधियां और बाजार में बेचने के लाभकारी तरीकों को पुस्तक में सुझाया है।**
- **किताब में पर्वतीय क्षेत्र में सब्जी उत्पादन का महत्व, सब्जी पौध उत्पादन तकनीक, मृदा परीक्षण, कीट व्याधि नियंत्रण, विविध सब्जियों के उत्पादन की तकनीकी, पॉली हाउस में सब्जी उत्पादन, पाले एवं शीतलहर से फसलों को कैसे बचाएं? मल्चिंग तथा ड्रिप सिंचाई प्रणाली का विस्तार है।**

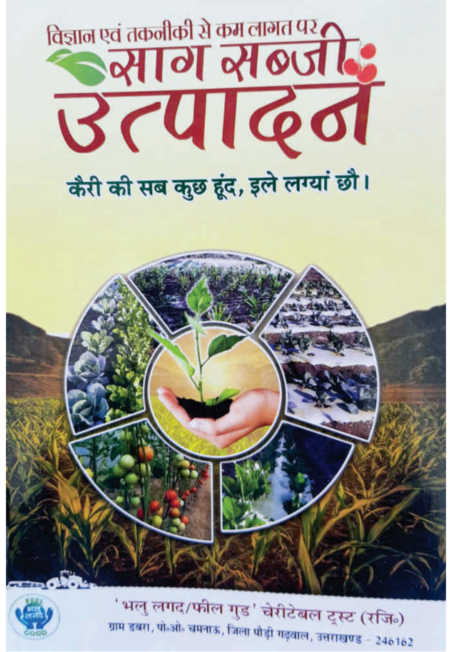

जैविक उत्पादों को ब्रांड नाम मिलेगा

उत्तराखंड में जैविक खेती के लिए अलग से एक्ट पारित हो चुका है, इससे किसानों को उनके जैविक उत्पादों की कीमत तो मिलेगी ही साथ में उत्तराखंड के जैविक उत्पादों को ब्रांड नाम भी मिलेगा, उत्तराखंड में फिलहाल 500 के करीब क्लस्टर हैं जिनमें 50 हजार किसान जैविक खेती से जुड़े हैं।

डॉ.हरीश चंद्र अंडोला
दून यूनिवर्सिटी

उत्तराखंड ने जैविक क्षेत्र में विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बनाई है। उत्तराखंड की जैविक कृषि और यहां के जैविक उत्पाद की न केवल देश में, बल्कि विदेशों में भी अच्छी खासी डिमांड है। उत्तराखंड के मिलेट्स और परंपरागत अनाज देश भर में पाए जाने वाले मिलेट्स व अनाज से बेहद खास माने जाते हैं, क्योंकि इनमें हाय न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज पाई गई है। यह सब उत्तराखंड में हिमालय इकोलॉजी की वजह से रिच डाइवर्सिटी और हाई मिनरल्स युक्त भूमि को वजह से पाया जाता है। संजीवनी बूटी वाला उत्तराखंड अपने हिमालय उत्पादों के लिए आदिकाल से ही खास माना जाता है, लेकिन अब उत्तराखंड ऑर्गेनिक बोर्ड ने इसे विश्व पटल पर लाने का काम किया है। उत्तराखंड जैविक कृषि क्षेत्र में हमेशा आगे रहा है उत्तराखंड के परंपरागत अनाज ना सिर्फ भारत बल्कि विदेशो में भी जाने जाते है। कुछ समय से सरकार भी उत्तराखंड के परंपरागत अनाजों को बचाने के लिए हर ठोस कदम उठा रही है। अब सरकार ने परंपरागत व जैविक कृषि के बचाव के लिए एक्ट भी पारित कर दिया है। एक्ट के मुताबिक उत्तराखंड की जमीन में जैविक खेती की जाएगी। अभी उत्तराखंड में परंपरागत कृषि दो लाख एकड़ भूमि में की जा रही है अब उत्तराखंड में जैविक खेती के लिए अलग से एक्ट पारित हो चुका है। इससे किसानों को उनके जैविक उत्पादों की कीमत तो मिलेगी ही साथ में उत्तराखंड के जैविक उत्पादों को ब्रांड नाम भी मिलेगा। उत्तराखंड में फिलहाल 500 के करीब क्लस्टर हैं जिनमें 50 हजार किसान जैविक खेती से जुड़े हैं। जो एक लाख अस्सी हजार कुंतल जैविक कृषि उत्पादों की पैदावार कर रहे हैं। इनमें गहत, मंडुआ, मक्का, सरसों, भट्ट, राजमा, गेहूं, चावल, मसाले व सब्जी मुख्य हैं। जैविक उत्पादन परिषद के समूहों के साथ अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, चमोली टिहरी, उत्तरकाशी व देहरादून में जैविक खेती की जा रही है। अलग एक्ट में ऐसा प्रावधान भी है की बंजर व अनुपयोगी भूमि को भू-स्वामी लीज पर दे सकता है। इस एक्ट के तहत उत्तराखंड में जैविक खेती के न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी तय किया जाना है। मंडी परिषद भी जैविक उत्पाद खरीदने के लिए रिवाल्विंग फंड स्थापित करेंगी। इस एक्ट से जैविक पदार्थो का क्रय-विक्रय तो होगा ही साथ में प्रोसेसिंग करने वाली एजेंसी पर भी निगरानी रखना संभव होगा। इनमें एनजीओ भी शामिल किए जाएंगे। जैविक खेती एक्ट में यह भी संकेत दिए गए हैं कि जैविक खेती करने वाले किसानों व खरीदारों द्वारा बेईमानी या धोखाधड़ी करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा।

रसायन से भूमि होती है बंजर

जैविक खेती को लेकर बनाए गए एक्ट के बाद उत्तराखंड में ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती में इजाफा देखा जा रहा है। लोग अपने खान पान में बदलाव कर जैविक उत्पादों को तवज्जों दे रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना काल के बाद जैविक क्षेत्र में तेजी से उछाल आया है। कोविड-19 संक्रमण काल में गांव लौटे प्रवासियों ने ऑर्गेनिक खेती में रुचि दिखाई है। जिससे उत्तराखंड में 34 फीसदी जैविक खेती हो रही है। ये रिवर्स पलायन में तो मदद कर ही रहा इसके साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंडके पारंपरिक जैविक उत्पादों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। जैविक खेती से होने वाले फायदे और नुकसान एक बार फिर से चर्चा में है। रासायनिकछिड़काव और पेस्टीसाइड से भले ही किसानों को अधिक पैदावार मिल जाती है, लेकिन इसमें लाभ से कहीं ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि इससे जहां मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म होती है वहीं ये रसायन भू-जल में मिलकर प्राकृतिक जल स्त्रोतों को दूषित करते हैं। दोनों ही सूरत में खामियाजा इंसानी जिंदगी को गंभीर बीमारी के रूप में चुकाना पड़ता है। जैविक खेती से भले ही लाभ कम हो, लेकिन धीरे-धीरे इसे फायदे का सौदा माना जाने लगाहै।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीकिसानों कोरसायनऔरपेस्टीसाइड के कम से कमप्रयोग की सलाह दे चुके हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से अपील की थी, कि हमें धरती मां को बीमार बनाने का हक नहीं है। सरकार इस दिशा में किसी ठोस परिणाम के लिए गंभीर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी 2024-25 के बजट में जैविक खेती को बढ़ावा देने की सरकार मंशा को साफ कर चुकी हैं।

रासायनिकखाद और पेस्टीसाइड से भले ही अधिक पैदावार मिल जाए, लेकिन इसमें लाभ से कहीं ज्यादा नुकसान है, क्योंकि इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म होती है, रसायन भू-जल में मिलकर प्राकृतिक जल स्रोतों को दूषित करते हैं, दोनों ही सूरत में खामियाजा इंसान को गंभीर बीमारी के रूप में चुकाना पड़ता है।

जैविक खेती पर केंद्र सरकार का जोर

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेकों प्रयास कर रही है। जिसमेंपरंपरागत कृषि विकास योजना शामिल है। इसके तहत सरकार किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर दे रही है। इस योजना के तहत तीन साल के लिए प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये की मदद दी जाएगी। देश के किसानों का ध्यान जैविक खेती की तरफ आकर्षित करने के लिए 2004-05 में राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत की गई थी। नेशनल सेंटर ऑफ आर्गेनिक फार्मिंग के मुताबिक 2003-04 में भारत में जैविक खेती सिर्फ 76,000 हेक्टेयर में हो रही थी जो 2009-10 में बढ़कर 10,85,648 हेक्टेयर हो गई। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अब देश में कुल27.70 लाख हेक्टेयर भूमि में जैविक खेती की जा रही है। केंद्र सरकार अगले तीन वर्षो में एक करोड़ किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाएगी। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का प्रावधान भी किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की धनराशि 8000 रुपये करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इससे पहले अंतरिम बजट में की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए भी बजट में एक बड़ा हिस्सा रखा गया था। कृषि-जलवायु क्षेत्र में नैनो-डीएपी के इस्तेमाल के विस्तार का ऐलान किया गया है। डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। इससे उत्तराखंड में खेती करने वालों के अच्छे दिनों की उम्मीद की जा सकती है। कृषि क्षेत्र में आधारभूत ढांचे की कमी झेल रहे इस पहाड़ी राज्य में अब गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, कलेक्शन सेंटर के साथ ही वेल्यू एडीशन को-प्रोसेसिंग यूनिट, शर्टिंग-ग्रेडिंग यूनिट लगने से किसानों को लाभ मिलेगा तो कृषि उत्पादों के बेहतर दाम भी मिलेंगे। मंडुवा, झंगोरा, राजमा जैसे अन्य जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग बड़े स्तर पर हो सकेगी। हर्बल और संगध खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। यही नहीं, गंगा के उद्गम स्थल गोमुख से लेकर हरिद्वार तक गंगा किनारे हर्बल कॉरीडोर विकसित होने से नए आयाम मिलने की उम्मीद परवान चढ़ेगी।

रासायनिक खाद पर प्रतिबंध

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में अधिसूचित क्षेत्र के दस विकास खंडों में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों को प्रतिबंधित व पशु चिकित्सा में प्रयुक्त दवाओं के साथ पशु चारे की बिक्री को विनियमित किया जाएगा। पशु पालन आधारित खेती से ही जैविक खेती संभव है। पहाड़ के किसान दूध-दन्याली के लिए पशुपालन करते रहे हैं। जैविक कृषि एक्ट के पहले क्रम में चिह्नित ब्लॉकों में रासायनिक खाद व खेती में प्रयोग होने वाले अन्य रासायनिक पदार्थ के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके बाद भी अधिसूचित क्षेत्र में प्रतिबंधित रासायनिक पदार्थों की बिक्री होती है तो कानूनी कार्रवाई होगी। इसमें एक लाख रुपये का जुर्माना व एक साल की कैद अथवा दोनों सजा हो सकती है। जैविक खेती करने वाले किसानों को बीज, प्रशिक्षण, बिक्री के साथ प्रमाणीकरण की सुविधा दी जाएगी। अभी जो भी किसान जैविक खेती कर रहे हैं, उन्हें इन पदार्थों की वाजिब कीमत नहीं मिलती। बाजार में मार्केटिंग का मायाजाल है जो शुद्ध व जैविक के नाम पर मोटा मुनाफा वसूल करते रहे हैं। साथ ही नकली व मिलावटी पदार्थ बेचकर उपभोक्ताओं के साथ ठगी करते हैं।

- **जैविक उत्पादन परिषद के समूहों के साथ अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, चमोली टिहरी, उत्तरकाशी व देहरादून में गहत, मंडुआ, मक्का, सरसों, भट्ट, राजमा, गेहूं, चावल, मसाले व सब्जी आदि की जैविक खेती की जा रही है।**
- **जंगलों में पाई जाने वाली वनौषधियों, भेषजों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिल सकता है, इससे न केवल उत्तराखंड के किसान खुशहाल होंगे, बल्कि युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, साथ ही बंजर हो रही कृषि भूमि का सही उपयोग हो सकेगा।**

उत्तराखंड के किसान खुशहाल होंगे

सरकार ने बागवानी को सुरक्षित रखने के लिए भी प्राविधान किया है। अब सरकारी नर्सरी को नर्सरी एक्ट में रखा गया है। यदि कोई नर्सरी गुणवत्ता के मानकों पर खरी नहीं उतरती तब पचास हजार रुपये का जुर्माना नर्सरी को देना होगा। अभी अधिकांश पौध राज्य के बाहर से आती है। अब इनकी गुणवत्ता की बिक्री के लिए कड़े नियम बनेंगे। नई पौध नर्सरी खोलने के प्राविधान भी होंगे। पौध गुणवत्ता के लिए संचालक जिम्मेदार होगा। नए फलदार पौधों का पेटेंट भी कराया जाएगा। उत्तराखंड के दस विकास खंडों से शुरू की जा रही यह योजना वनवासियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए उत्प्रेरक का काम करेगी। वैसे सच ये भी है कि किसान अपने खेत खलिहान को समझने वाला एक वैज्ञानिक भी है, लेकिन वो अपने ज्ञान को भूल रहा है। जबकि वो जानता है कि उसे अपने खेत में क्या इस्तेमाल करना है और क्या नहीं । अपने अनुभवों से वह यह भी सीख गया है कि कुछ अधिक उगा लेने के फेर में उसकी कैसी दुर्गति हुई है। किसान को वाजिब कीमत मिलने वाला बाजार मिल जाए तो जैविक उत्पाद व जंगलों में पाई जाने वाली वनौषधियों, भेषजों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिल सकता है। इससे न केवल उत्तराखंड के किसान खुशहाल होंगे, बल्कि युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। साथ ही बंजर हो रही कृषि भूमि का सही उपयोग हो सकेगा। जमीन की उत्पादन क्षमता कामय रहेगी। सबसे बड़ा लाभ पर्यावरण को होगा। क्योंकि पर्यावरण प्रदूषित होने से ही आपदाएं जन्म लेती है। जिसका खामियाजा उत्तराखंड के रहने वालों को ही उठाना पड़ता है। उत्तराखंड के किसान गर्व से कह सकेंगे कि वो जैविक उत्पादन करने वाले प्रदेश के वासी हैं।

हिंदी की है आस बनेगी 1 दिन खास

आज का युवा अंग्रेजी के साथ हिंदी को भी महत्व देने लगा है उसे पता है कि विकास का पहिया केवल अंग्रेजी या प्रांतीय भाषा के सहारे नहीं घूम सकता, पिछले कुछ वर्षों में देश में ही नहीं विदेशों में भी हिंदी और संस्कृत भाषा सीखने की होड़ सी मची हुई है।

प्रदीप देवीशरण भट्ट
लेखक, मेरठ

14 सितंबर को 'हिंदी दिवस' मनाया जाएगा। मुझे उम्मीद है कुछ मंत्रालयों में इस विषय में पत्रावलियां अंग्रेजी में ही प्रस्तुत की जाएंगी। हम जैसे हिंदी प्रेमियों को इससे कितना कष्ट होता है उनकी बला से। किंतु कहीं न कहीं दिल में ये आस अवश्य है कि एक न एक दिन हमारी हिंदी भाषा भी 'लिंग्वा फ्रांका' (प्रयोग में ली जाने वाली वह प्रभावशाली भाषा जो प्रयोग में लेने वालों की मातृ भाषा न हो) बनेगी

मैं हिंदवी की हिंदी हूं, राष्ट्र भाल की बिंदी हूं।
अंग्रेजी भाषा के समक्ष मैं, मात्र अब भी किंचित हूं, हां मैं हिन्दी हूं ...

विश्व परिदृश्य पर पिछले 3000 वर्ष के इतिहास में देखें तो ग्रीक, लैटिन, पॉर्चयुगीज, स्पैनिश, फ्रेंच और अंग्रेजी एथेंस की ग्रीक भाषा विभिन्न दौर में प्रभावशाली रही हैं। 18वीं सदी के मध्य में फ्रांस के विद्वान वॉल्टेयर ने 'फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री' लिखी। इसका विषय संपूर्ण मानव जाति का इतिहास था। अध्ययन में यह तथ्य निकलकर आया कि ईसा पूर्व 9वीं सदी से लेकर चौथी सदी तक यूरोप, शहर रूपी कई साम्राज्यों में बंटा हुआ था। इनमें से एथेंस व्यापार व सैन्य ताकत बनकर उभरा। इसलिए प्रभावशाली एथेंस की ग्रीक भाषा यूरोप की लिंग्वा फ्रांका बनी। ईसा पूर्व 201 से आने वाले 600 वर्षों तक एथेंस यूरोप का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य रहा। लिहाजा कैथोलिक चर्च की ताकत बढ़ी और रोमन भाषा लैटिन लिंग्वा फ्रांका बन गई। लैटिन लिंग्वा फ्रांका इसलिए बनी रही क्योंकि आने वाले 1000 साल तक कोई नई वैश्विक शक्ति नहीं उभरी। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और छह वर्ष बाद वास्कोडिगामा ने भारत में कदम रखा। ये दोनों यात्राएं पुर्तगाल के खर्चे पर हुई और इस तरह से पुर्तगाल साम्राज्य शक्तिशाली होने लगा। पुर्तगाल की देखा-देखी स्पेन और फ्रांस भी उपनिवेशवाद में कूदे। इस दौरान पॉर्चयुगीज, स्पेनिश और फ्रेंच भाषा लिंग्वा फ्रांका की दौड़ में रहीं। इंग्लैंड में स्थिति ऐसी थी कि राजघराने में जो शिक्षा ली जाती थी उसका माध्यम फ्रेंच भाषा होती थी ना कि अंग्रेजी। उस समय के सभ्य समाज में अंग्रेजी गरीबों की भाषा और दरिद्रता की निशानी मानी जाती थी। वर्तमान में अंग्रेजी भाषा को 'लिंग्वा फ्रांका' का दर्जा प्राप्त है। ऐसा इसलिए कि पिछले लगभग 600 वर्षो से ब्रिटेन आर्थिक, सामजिक, राजनीतिक बाजारी कारण व सैनिक शक्ति के लिहाज से विश्व के उन 5 देशों में स्थान रखता है जो सीधे-सीधे शेष विश्व पर अपना प्रभाव रखते हैं। चूंकि अमेरिका के अलावा विश्व में प्रमुख 7 देशों में अंग्रेजी ही बोली जाती है इसलिए वर्तमान में अंग्रेजी ही लिंग्वा फ्रांका बनी हुई है। जहां तक अंग्रेजी का ताल्लुक है इसे प्रथम अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। ये एक पश्चिम जर्मेनिक भाषा है जिसकी उत्पती एंग्लो-सेक्सन इंग्लैंड में हुई। ब्रिटिश हुकूमत कई देशों पर रही है अतः जैसे-जैसे अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ा ये उन देशों में भी ज्यादा बोली जाने लगी जहां उस देश की अपनी भाषा पहले से ही मौजूद थी। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने 18,19 एवं 20वीं शताब्दी में सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं संस्कृति पर पकड़ बनाने के लिए अंग्रेजी भाषा पर अधिक बल दिया जिससे इसे छठीं भाषा के रूप में लिंग्वा फ्रांका होने का गौरव प्राप्त हुआ।

अंग्रेजी बोलने वाले लगभग 53 प्रमुख देश हैं जिनमें संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन संघ, राष्ट्रमंडल, नाटो देश व नाफ्टा के देश शामिल हैं, एक सर्वे के अनुसार पूरे विश्व में अंग्रेजी बोलने वाले देशों के क्रम में अमेरिका पहले, भारत दूसरे व नाइजिरिया तीसरे स्थान पर है।

अंग्रेजी भाषा चौथी या 5वीं शताब्दी में शुरू हुई

कुछ देश ऐसे भी रहे जिन्होंने इसे अपनी मातृ भाषा के बाद दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी। अगर मैं इसे इस तरह पारिभाषित करूं या कहूं कि अंग्रेजी भाषा का उत्थान चौथी या 5वीं शताब्दी के मध्य इंग्लैंड में एंग्लो-सेक्सन लोगों द्वारा शुरू किया गया, तो ज्यादा बेहतर होगा। एंग्लो सेक्सन लोग कई तरह की भाषाओं को बोलते थे, यहां यह कथन स्प्ष्ट है कि वाइकिंग हमलावरों द्वारा अपनाई गई प्राचीन नोर्स भाषा का प्रभाव वर्तमान अंग्रेजी भाषा पर ज्यादा है। ये विषय अलग है कि अंग्रेजी भाषा लगातार अपना विकास करती रही और अन्य देशों में बोले जाने वाली भाषा के शब्दों को स्वंय में समाहित करती रही, जिससे इसकी ताकत में ज्यादा वृद्धि हुई। वर्तमान में हम जो अंग्रेजी बोलते हैं उसमें नोर्मन शब्दावली और वर्तनी के नियमों का भारी संख्या में उपयोग हुआ है। अंग्रेजी भाषा में प्राचीन ग्रीक और लैटिन का अत्याधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। अंग्रेजी बोलने वाले लगभग 53 प्रमुख देश हैं जिनमें संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन संघ, राष्ट्रमंडल, नाटो देश व नाफ्टा के देश शामिल हैं। एक सर्वे के अनुसार पूरे विश्व में अंग्रेजी बोलने वाले देशों के क्रम में अमेरिका पहले, भारत दूसरे व नाइजिरिया तीसरे स्थान पर है। आश्चर्यजनक रूप से ब्रिटेन चौथे स्थान पर है। इसके बाद फिलिपिंस, कनाडा और आस्ट्रेलिया का नंबर आता है। मतलब जिस अंग्रेजी भाषा की उतपत्ती ब्रिटेन में हुई वही देश अंग्रेजी बोलने वाले देशों में चौथे नंबर पर है मतलब उसने अपना आधिपत्य जमाने के उद्देश्य से अंग्रेजी भाषा को इतना ताकतवर बना दिया कि समूचा विश्व बिना अंग्रेजी भाषा के चल नहीं सकता। किंतु हर जगह अपवाद होते हैं, जो यहां भी है। चीन में मंदारिन भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है किंतु चीन के बाहर न के बराबर किंतु चीन ने आज जो मुकाम हासिल किया है वह मंदारिन की बदौलत ही किया है। अंग्रेजी का उपयोग उतना ही किया गया जितना आवश्यक था।

विश्व में टाप थ्री में हिंदी भाषा

जहां तक हिंदी भाषा का प्रश्न है तो विश्व में अंग्रेजी व मंदारिन के बाद इसका स्थान तीसरा है। भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक बंगाली भाषा बोली जाती है। जिस प्रकार आज अंग्रेजी वैश्विक भाषा के रूप में विश्व में प्रतिष्ठित है उसी तरह आने वाले समय में हिंदी भी वैश्विक भाषा के रूप में अपना स्थान बनाएगी। हिंदी भारत के अतिरिक्त नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तिब्बत, अफगानिस्तान, श्रीलंका आदि देशों में बोली और समझी जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में अपना स्थान बनाती जा रही है। भारत में इस समय 6 कास्मोपोटिन शहर हैं जिनमें चेन्नई को छोड़कर आपको हिंदी भाषा बोलने वाले समझने वाले दिल्ली, मुम्बई, बंगलौर, कोलकाता और हैदराबाद में आसानी से मिल जाएंगे। चेन्नई में भी हिंदी बोलने वाले मिलेंगे लेकिन वे तमिलियन न होकर हिंदी बेल्ट से आकर बसे हिंदी भाषी लोग हैं। एक सत्य और है कि व्यापार के सिलसिले में राजस्थान से बाहर निकले लोग भले ही घर में मारवाड़ी में बातचीत करते हैं किंतु अपनी व्यापारिक गतिविधियों में वे हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। इसका अनुभव मुझे अगस्त, 2022 में अपने तीन दिवसीय साहित्यिक कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला। एक कहावत प्रसिद्ध है 'जहां न पहुंचे बैलगाडी वहां पहुंचे मारवाड़ी' ये सुखद अनुभव मुझे नेपाल पश्चिम बंगाल और भूटान के साथ नोर्थ ईस्ट के आठ राज्यों में भी देखने को मिला। भारत की संविधान सभा द्वारा 14 सितम्बर, 1949 को इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया जिससे इसका प्रयोग और चौतरफा विकास हुआ। बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि को राजभाषा (मुख्य प्रांतीय भाषा) बनाया गया है। ऐसा करने से किसी भाषा का महत्व कम नहीं हुआ। बल्कि इससे उन सभी भाषाओं का उत्तरदायित्व और प्रयोग क्षेत्र पहले से बढ़ गया है। जहां पहले सिर्फ परस्पर बोलचाल में ही इनका प्रयोग होता था या उसमें साहित्य की रचना होती थी, वहीं अब प्रशासनिक कार्य भी हो रहे हैं। यही स्थिति हिंदी की भी है। इस प्रकार हिंदी संपर्क और राष्ट्रभाषा तो है ही, राजभाषा बनाकर इसे अतिरिक्त सम्मान दिया गया। द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई तब उसकी आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी, रशियन, फ्रेंच एवं मंदारिन भाषा को ही मान्यता मिली थी। हम भारतीयों के लिए 1991 में संयुक्त राष्ट्र में स्व. अटल बिहारी बाजपयी द्वारा दिया गया भाषण एक मात्र गौरव का क्षण रहा है अन्यथा आज तक किसी अन्य नेता ने कभी यूएन में हिंदी में भाषण देना तो दूर 'नमस्ते' भी कहना उचित नहीं समझा। फिर हिंदी को यूएन की भाषा में सम्मलित कराने की बात तो दूर की कौड़ी है। बिना किसी संकोच के कहा जा सकता है कि 2014 के बाद से स्थिति बहुत तेजी से बदली और 2018 में भारत सरकार की ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक संचार विभाग के साथ साझेदारी की गई। आज भारत यूएन के समाचार और मल्टी मीडिया के लिए फंड भी दे रहा है और परिणाम सामने है। जून-2022 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा जारी होने वाले सभी कागजातों को अन्य मान्य भाषाओं के अलावा हिंदी में जारी करने की घोषणा की गई। भारत के लिए ये गर्व का विषय है। हिंदी के अलावा बांग्ला एवं उर्दू को भी यूएन ने सहमती दी है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी कुछ माह पूर्व घोषणा की है कि उसके द्वारा दिए गए सभी निर्णयों का अनुवाद हिंदी भाषा में किया जाएगा ताकि वादी को समझने में आसानी हो।

भारत का संविधान 22 भारतीय भाषाओं को अधिकारिक भाषा का दर्जा देता है, इनमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, असमिया, बोडो, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, डोगरी, संथाली, मैथिली, नेपाली, कोंकणी एवं उर्दू शामिल हैं।

सात कोस पर पानी बदले चार कोस पर भाषा जी।
विश्व पटल पर छा जाएगी इक दिन हिंदी भाषा जी।।

आज का युवा अंग्रेजी के साथ हिंदी को भी महत्व देने लगा है उसे अच्छी तरह से पता है कि विकास का पहिया केवल अंग्रेजी या प्रांतीय भाषा के सहारे नहीं घूम सकता। पिछले कुछ वर्षों में देश में ही नहीं विदेशों में भी हिंदी और संस्कृत भाषा सीखने की होड़ सी मची हुई है। मल्टीनेशनल कंपनियां अच्छी तरह जानती है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, अगर उन्हें अपना माल बेचना है तो उन्हें भारत की भाषा हिंदी स्वीकारनी होगा, साथ ही इसी बहाने प्रांतीय भाषाओं का भी विकास हो रहा है। कुछ वर्ष पूर्व एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि दक्षिण कोरिया की कंपनी जब किसी को भारत में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजती हैं तो वे एक शार्ट टर्म हिंदी सेशन रखती हैं ताकि वे हिंदी भाषा के कुछ वाक्य समझ व बोल सके। कंपनी को भारत में प्रतिनिधि के तौर पर यहां की बोल चाल को समझने में आसानी हो, लोगों से घुलने मिलने में आसानी हो, उनका उद्देश्य सिर्फ भारत में माल बेचने का ही नहीं है वरन उनका उद्देश्य भारतीय समाज से जुड़ने का रहता है। भारत का संविधान 22 भारतीय भाषाओं को अधिकारिक भाषा का दर्जा देता है। इनमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, असमिया, बोडो, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, डोगरी, संथाली, मैथिली, नेपाली, कोंकणी एवं उर्दू शामिल हैं। किंतु हिंदी लगभग सब जगह बोली व समझी जाती है और यह तेजी से बढ़ भी रही है। पढ़ाई का माध्यम भी हिंदी, अंग्रेजी व प्रांतीय भाषा के इर्द-गिर्द सिमटता जा रहा है जो एक अच्छा संकेत है। केंद्र सरकार विभिन्न स्तरों पर प्रोत्साहन दे रही हैं। नई शिक्षा नीति भी इसमें एक कारगर भूमिका निभा रही है। पिछले दिनों विज्ञान पत्रिका करंट साइंस में प्रकाशित एक अनुसंधान में मस्तिष्क विशेषज्ञों का कहना है कि अंग्रेजी पढ़ते समय दिमाग का केवल बांया हिस्सा ही सक्रिय रहता है जबकि हिंदी या संस्कृत पढ़ते समय मस्तिष्क का दायां और बांया दोनों हिस्से सक्रिय हो जाते हैं। इससे दिमाग की कसरत ज्यादा होती है और दिमाग ज्यादा तरोताजा रहता है। अध्ययन के दौरान छात्रों को पहले चरण में जोर-जोर से अंग्रेजी भाषा पढ़ने के लिए कहा गया उसके बाद हिंदी भाषा को। इस समूची प्रक्रिया में दिमाग का एमआरआई किया गया तब यह नतीजा सामने आया। एक और अच्छी पहल हुई है वो ये कि इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी माध्यम से कराई जाने लगी है जो भारतीय शिक्षा के लिए एक शुभ संदेश है। मुझे यकीन है कि 2040 तक हिंदी अगली (सातवीं) लिंग्वा फ्रांका होने का दर्जा अवश्य पा लेगी।

खतलिंग ग्लेशियर जन-जागरण यात्रा

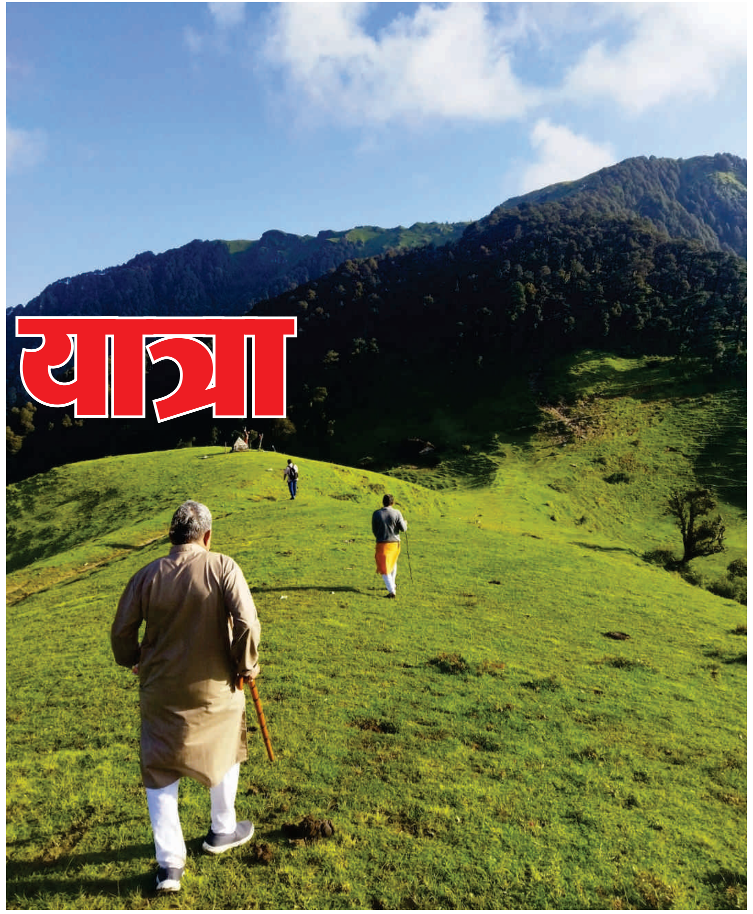

प्रचलित पांडवों की भ्रमण कथाओं के बहाने 'उत्तराखंड के गांधी' कहलाने वाले स्वप्न द्रष्टा इंद्रमणि बडोनी ने खतलिंग क्षेत्र में अमरनाथ तीर्थयात्रा जैसी परंपरा का सपना देखा, इसके पीछे उनका उद्देश्य टिहरी के इस अति पिछडे भिलंग क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना था।

व्योमेश चंद्र जुगरान
वरिष्ठ पत्रकार, देहरादून

टिहरी जिले का एक छोटा सा कस्बा घुत्तू हर वर्ष 2 सितंबर को एक अनूठे आयोजन का गवाह बनता है। कस्बे के बीचो-बीच बहती भिलंगना नदी बरसात को आत्मसात कर कुछ ज्यादा ही मचल रही होती है। मानो इस बात पर जश्न मना रही हो कि बड़ी संख्या में लोग ढोल-नगाड़ों के साथ उसके मायके खतलिंग की यात्रा पर निकल रहे हैं। इस बार इस महायात्रा की चालीसवीं सालगिरह है। करीब 13हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित खतलिंग ग्लेशियर को एक धाम का माहात्म्य प्राप्त है और स्थानीय लोग इसे पांचवां धाम कहते हैं। यात्रा का मुख्य प्रयोजन इसी माहात्म्य का संदेश देना है। हालांकि ऐसी यात्राओं का एक पारिस्थितिक महत्व भी होता है। लोगों को पता चलता है कि जीवन दायिनी नदियों के उद्गम स्थल प्राकृतिक हलचलों से कितने प्रभावित हो रहे हैं और उच्च हिमालय में परिवर्तनों की गति कितनी तीव्र है। ऐसे मालुमातों के मद्देनजर खतलिंग ग्लेशियर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह भिलंगना नदी का उद्गम है और हिमालय के प्रमुख ग्लेशियरों में गिना जाता है। स्थानीय लोग खतलिंग को पांडवों की भ्रमण कथाओं से जोड़ कर देखते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन ने यहां तप किया था और शिव ने दर्शन देकर अर्जुन को खाती नाम दिया था। जब अर्जुन ने वहां एक शिवलिंग की स्थापना की इच्छा प्रकट की तो भगवान शिव ने कहा- हे खाती अर्जुन,इस हिम क्षेत्र में मिट्टी इत्यादि के शिवलिंग का स्थिर रह पाना अत्यंत कठिन है। परंतु आसपास जो हिमानियां तुम देख रहे हो,उनके दर्शन मात्र से ही मेरी पूजा पूर्ण हो जाएगी। जो भी मनुष्य यहां आकर इन हिमानियों के दर्शन करेगा,मैं उनकी मनोकामना पूरी करूंगा। सृष्टि इस क्षेत्र को तुम्हारे नाम से खतलिंग के रूप में जानेगी। इलाके में प्रचलित पांडवों की इन्हीं भ्रमण कथाओं के बहाने 'उत्तराखंड के गांधी' कहलाने वाले स्वप्न द्रष्टा इंद्रमणि बडोनी ने खतलिंग क्षेत्र में अमरनाथ तीर्थयात्रा जैसी परंपरा का सपना देखा। इसके पीछे उनका उद्देश्य टिहरी के इस अति पिछडे भिलंग क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना था।

जागरण महायात्रा में ठहराव

1983 में इंद्रमणि बडोनी ने पहली बार खतलिंग जन जागरण महायात्रा प्रारंभ की। वह गढ़वाल के तत्कालीन मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह पांगती को भी साथ ले गए। इस यात्रा में स्थानीय देवी-देवताओं के विग्रह लेकर 3200 स्त्री-पुरुष भी चले। इसके बाद तो हर साल इंद्रमणि बडोनी और सुरेंद्र सिंह पांगती की अगुआई में आसपास के इलाकों से श्रद्धालुओं का मेला उमड़ पड़ता। लोग करीब 45 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर 13 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित खतलिंग की हिमानियों के दर्शन कर धन्य होते और पुण्य का लाभ कमाते। बाद के वर्षों में इस यात्रा की परंपरा में बड़ा ठहराव आ गया। 1999 में इंद्रमणि बडोनी के निधन के बाद तो यह महायात्रा लगभग ठप सी हो गई। 2015 में क्षेत्र के कुछ उत्साही नौजवानों ने इसे पुनर्जीवित किया और एक यात्री दल खतलिंग पहुंचा। यात्रा के इस पुनरोंद्धार में दिल्ली स्थित पर्वतीय लोक विकास समिति,भिलंगना क्षेत्र विकास समिति,खतलिंग-देवलंग भिलंग समिति और व्यापार मंडल घुत्तू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पर्वतीय लोक विकास समिति के संयोजक सूर्यप्रकाश सेमवाल और उपाध्यक्ष वीर सिंह राणा ने बताया कि 2017 में यात्रा के अवसर पर घुत्तू से आयोजित समारोह में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने खतलिंग क्षेत्र को पांचवें धाम के रूप में विकसित करने और इस क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन के शैव सर्किट से जोड़ने की घोषणा की थी। दुर्भाग्य से घोषणा पर तो अमल नहीं हुआ। लेकिन इंद्रमणि बडोनी की महायात्रा की परंपरा को जारी रखने के लिए घुत्तू के नौजवानों की जिजीविषा में कोई ठहराव नहीं आया और खतलिंग जागरण महायात्रा कोविड काल को छोड़कर हर साल 2 सितंबर को घुत्तू से अनवरत जारी रही।

खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का उद्गम है और हिमालय के प्रमुख ग्लेशियरों में गिना जाता है, स्थानीय लोग खतलिंग को पांडवों की भ्रमण कथाओं से जोड़ कर देखते हैं, मान्यता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन ने यहां तप किया था और शिव ने दर्शन देकर अर्जुन को खाती नाम दिया था।

150 परिवारों का गांव महायात्रा का पड़ाव

सूर्यप्रकाश सेमवाल के मुताबिक,राज्य पर्यटन निदेशालय ने खतलिंग ट्रैक को 2017 के लिए 'ट्रैक ऑफ द ईयर' घोषित किया,मगर बाद में पता चला कि यह सुविधा अल्मोड़ा के एक ट्रैक के नाम कर दी गई। खतलिंग जनजागरण महायात्रा की अंतर्निहित सोच का ही परिणाम है कि भिलंगना घाटी में अलग-थलग पड़े गंगी क्षेत्र का जनजातीय समाज आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मोटर मार्ग से जुड़ गया है और प्रगति की नई इबारत लिख रहा है। गंगी खतलिंग, महायात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। करीब डेढ़ सौ मैती परिवारों का यह गांव हिमालयी लोकजीवन की एक दिलचस्प और अनूठी कहानी है। मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर यहां का जीवन पलायन के दंश से फिलहाल अछूता है। ये लोग मौसम के हिसाब से इन खूबसूरत ढलानों पर अपनी रिहायश बदलते रहते हैं। यानी बर्फवारी के दिनों में यहां के परिवार नीचे चले जाते हैं और फिर मौसम बदलते ही लौट आते हैं। पूरे टिहरी क्षेत्र में गंगी वासियों की संपन्नता के खूब चर्चे होते हैं। इसका कारण उनका वह मेहनतकश स्वभाव है जिसके बूते वे अत्यधिक विषम परिस्थिति को भी परास्त करने का माद्दा रखते हैं। विडंबना देखिए कि इन वनवासियों के आंगन में बहने वाली भिलंगना नदी ने देश-दुनिया को टिहरी जैसा बांध दिया,पर योजनाकारों ने भिलंगना के इन्हीं मैतियों को रोशनी से महरूम रखा।

2016 में देखी सड़क और बिजली

मैती वनवासियों के गांव गंगी में 2016 में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा था जो इस दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में आजादी के बाद पहली बार घटी घटना थी। इसके बाद ही यहां सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के बारे में सोचा जा सका। पिछले वर्ष खतलिंग महायात्रा का यात्री दल दो समूह में बंटकर खतलिंग और पंवालीकांठा पहुंचा था। पंवाली कांठा यात्री दल को महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने रवाना किया था। पंवालीकांठा टिहरी के घुत्तू क्षेत्र में ही पड़ता है। इसकी गिनती गढ़वाली हिमालय के प्रमुख बुग्यालों में होती है। बुग्याल करीब 10 से 12 हजार फीट की ऊंचाई पर वृक्ष रेखा की समाप्ति के बाद नजर आने वाले हरी मखमली घास के खूबसूरत ढलाऊदार मैदान को कहते हैं। ये हिमालय की जैव विविधता के रखवारे कहे जाते हैं और जुलाई-अगस्त आते-आते कुदरती फूलों और बेलबूटों की खूबसूरत फुलवारी में बदल जाते हैं। बुग्यालों के बारे में कहा जाता था कि यहां की हरितिमा कभी खत्म नहीं होती। इसलिए ये पशुचारण के सबसे उपयुक्त ठिकाने होते हैं। पशुचारक चैत्र मास आरंभ होते ही अपने-अपने मवेशियों के साथ यहां पहुंचते हैं और अश्विन मास तक यहीं ठिकाना बना लेते हैं। पशुओं के साथ सहजीवन की निमित्त उनकी परंपरागत छानियां इस दौरान पशुचारण से जुड़ी पारिवारिक और आर्थिक गतिविधियों का भी केंद्र बन जाती है।ये लोग अक्टूबर के अंत तक अपना पशुधन लेकर वापस नीचे उतरते हैं।

बुग्यालों के वानस्पितिक संसार को हानि

गढ़वाल क्षेत्र के हिमालय में ज्यादातर बुग्याल मानवीय दखलंदाजी,अतिशय पशुचारण,जड़ी-बूटी संग्रहण,अपशिष्टों और काफी हद तक जलवायु परिवर्तन के कारण भारी दबाव में हैं। बुग्याली वनस्पितियां उगना कम हो गई हैं,भू-कटाव बढ़ गया है और कई जगह घास मिट्टी में समा रही है। सबसे अधिक चिंता घोड़े-खच्चर जैसे बड़े जानवरों,बांझ गायों और बैल जैसे अनुपयोगी मवेशियों के झुंडों को लेकर है जिन्हें चरान और चुगान के लिए बुग्यालों में ठेल दिया जाता है। इससे बुग्यालों के वानस्पितिक संसार को तो हानि पहुंचती ही है,बड़े जानवरों के भारी-भरकम खुर बुग्यालों की संवेदनशील मिट्टी के क्षरण को भी बढ़ावा देते हैं। पंवाली कांठा बुग्याल में भी यह भू-क्षरण बड़ी-बड़ी दरारों की शक्ल में दिखता है जिसे रोकने के लिए वन विभाग ने जगह-जगह खास तरह की नेटिंग (जालियां) की हुई है। हिमालय को लेकर की जा रही चिन्ताओं में यह विषय तो शामिल करना ही पड़ेगा कि हिमालय और इसकी जैव विविधता के रखवारे इन बुग्यालों में पशुचारण व अन्य गतिविधियों का स्वरूप क्या हो?खतलिंग महायात्रा जैसे अनुशासित आयोजन उच्च हिमालय में पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य कर सकते हैं।

- **1983 में इंद्रमणि बडोनी ने पहली बार खतलिंग जन जागरण महायात्रा प्रारंभ की, वह गढ़वाल के तत्कालीन मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह पांगती को भी साथ ले गए, इस यात्रा में स्थानीय देवी-देवताओं के विग्रह लेकर 3200 स्त्री-पुरुष भी चले थे।**
- **वनवासियों के गांव गंगी में 2016 में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा था जो इस दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में आजादी के बाद पहली बार घटी घटना थी। इसके बाद ही यहां सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के बारे में सोचा जा सका।**

इसमें बड़ी संख्या में विविध क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले लोग शामिल होते आए हैं। उच्च हिमालय में पग यात्राएं भले ही परंपरागत धार्मिक मान्यताओं और रीति-रिवाजों के वशीभूत होती आई हों मगर एक गूढ़ विचार के रूप में ये समाज और प्रकृति के अंतर संबंध एवं सामंजस्य का प्रतीक रही हैं। इनमें हिमालयी जनजीवन और इसके सरोकारों को जानने की जुगुप्सा,पारंपरिक ज्ञान,जैव विविधता और पर्यावरण संबंधी अनुभवों के अलावा साहसिक पर्यटन का भी पुट शामिल रहा है।

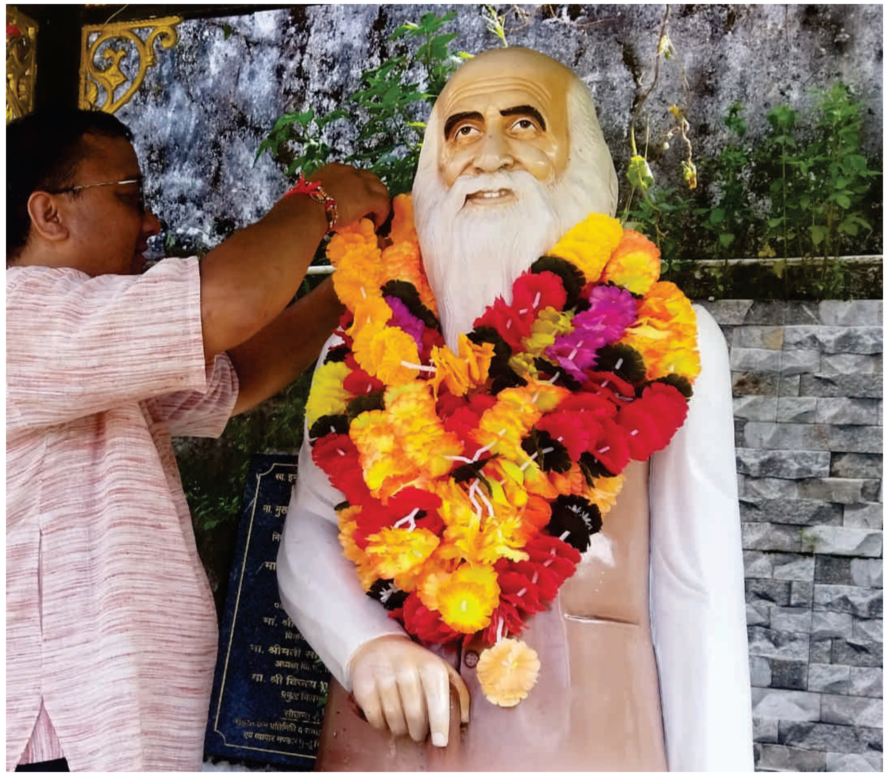

महासू देवता मंदिर का रहस्य

महासू देवता का मंदिर कई रहस्य छिपाए हुए है, मंदिर के गर्भगृह में एक अखंड ज्योति जलती है, गर्भगृह में यह दिव्य ज्योत पुजारी के अलावा किसी ने नहीं देखी, मंदिर के अंदर एक जल धारा भी निकलती है, जिसका जल बाहर नहीं दिखता, पर इसी जल धारा से महासू देवता का जलाभिषेक होता है।

कमल कपूर
वरिष्ठ पत्रकार, अल्मोड़ा

श्रावण मास है और शिव को यह माह प्रिय है। शिव भक्त शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए गंगा का पवित्र जल लेकर आए। शिव भक्तों का मानना है कि देवों के देव भोले भंडारी संकटों से उबारने वाले हैं, मुश्किल घड़ी में राह दिखाने वाले हैं, तभी तो भक्त ही क्या देवता भी अपने दुखों के निवारण के लिए भोले भंडारी की शरण में जाते हैं। ऐसा ही एक शिव धाम देवभूमि उत्तराखंड में देहरादून के जौनसार बावर क्षेत्र में है, जहां स्वयं प्रकृति गंगाधर का श्रृंगार करती है।
जनजातिय जौनसार क्षेत्र के शिव को श्रद्धालु महासू देवता के रूप में पूजते हैं। इस क्षेत्र के लोग महासू देवता को अपना ईष्टदेव भी मानते हैं। देहरादून के जनजातीय क्षेत्र जौनसार-बावर स्थित महासू देवता मंदिर चकराता के पास हनोल गांव में टोंस नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। लोगों की आस्था उन्हें इस पवित्र धाम तक खींच लाती है। मंदिर की दिव्यता के बारे में सुनकर ही देश के अन्य प्रांतों से भारी संख्या में श्रद्धालु यहां शीश नवाने आते हैं। मंदिर की बेजोड़ वास्तु और स्थापत्यकला लोगों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करती है। महासू देवता को महादेव शिव का स्वरूप माना गया है। उत्तराखंड के साथ महासू देवता की पूजा हिमाचल प्रदेश में भी की जाती है। उत्तराखंड के इस मंदिर की खास बात ये है कि यहां हर साल राष्ट्रपति भवन से नमक का चढ़ावा भेजा जाता है। महासू देवता के बारे में एक किंवदंती प्रचलित है। कहा जाता है कि किसी जमाने में जौनसार बावर क्षेत्र में एक राक्षस किरमिक ने खूब आतंक मचाया था। किरमिक को हर बार आपसी समझौते से गांव वाले एक इंसान की बलि देते थे, हर साल बलि देने से यहां के निवासी काफी परेशान हो गए। इसी क्षेत्र में हूणाभाट नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। जिसके सात पुत्र थे और उनमें से छह की राक्षस किरमिक बलि ले चुका था। एक बार ब्राह्मण हूणाभाट की पत्नी नदी से पानी भर रही थी तभी वहां किरमिक राक्षस आ धमका और हूणाभाट की पत्नी पर झपटने लगा। किसी तरह हूणाभाट की पत्नी किरमिक के चंगुल से बच निकली। तभी हूणाभाट की पत्नी के पानी से आधे भरे बर्तन में से भविष्यवाणी हुई, 'अगर तुम अपने पुत्र और इस क्षेत्र को किरमिक के आतंक से बचाना चाहती हो तो अपने पति को कश्मीर जाने को कहो। वहां के शक्तिशाली देवता महासू ही किरमिक का वध कर सकते हैं।' हूणाभाट ने जब ये बात सुनी तो वो तुरंत ही कश्मीर के लिए निकल पड़ा।

किरमिक राक्षस के आतंक से मुक्ति

कश्मीर पहुंचकर उसने चारों महासू भाईयों को अपनी आप बीती सुनाई और उनसे प्रार्थना की कि वो चारों जौनसार आकर किरमिक के आतंक से उन्हें मुक्ति दिलाएं। हूणाभाट की भक्तिभाव देखकर महासू जौनसार आने के लिए राजी हो गए। जिसके बाद हनोल में चार महासू भाईयों की उत्पत्ति हुई। इनमें एक बासक, दूसरे पिबासक, तीसरे बौठा और चौथे चालदा थे। इन्होंने किरमिक का वध कर जौनसार के बावर क्षेत्र को उस राक्षस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। उसके बाद से ही ये चारों महासू भाई जौनसार क्षेत्र में कुल देवता के रूप में पूजे जाने लगे। स्थानीय भाषा में महासू शब्द का अर्थ भगवान शिव से है। सबसे छोटे भाई चालदा महासू देवता हमेशा चलायमान रहते हैं, जो प्रवास के दौरान पूरे जौनसार बावर, उत्तराखंड, हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में 1 साल, 6 महीने, 2 साल, ढाई साल, अलग-अलग समय पर प्रवास के लिए निकलते हैं। अपने नए प्रवास स्थल के लिए जब महासू देवता निकलते हैं तो उनके आगमन पर जौनसार बावर में विशाल पूजा अर्चना का आयोजन होता है।

- **महासू देवता की कीर्ति सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह दूर-दूर तक फैली है, न्याय के देवता और उनके न्यायालय का सीधा कनेक्शन दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से भी है, महासू देवता के इस न्यायालय में दिल्ली के राष्ट्रपति भवन की ओर से हर साल नमक भेंट किया जाता है।**
- **महासू देवता का मंदिर देवभूमि उत्तराखंड में देहरादून के जौनसार बावर क्षेत्र में है, जहां स्वयं प्रकृति गंगाधर का श्रृंगार करती है, जनजातिय जौनसार क्षेत्र के शिव को ही श्रद्धालु महासू देवता के रूप में पूजते हैं, इस क्षेत्र के लोग महासू देवता को अपना ईष्टदेव भी मानते हैं।**

मिहिरकुल ने कराया मंदिर का निर्माण

बौठा महासू हनोल में स्थित मुख्य मंदिर में पूजे जाते हैं। लोक मान्यता है कि हनोल में स्थित महासू के मुख्य मंदिर का निर्माण हूण राजवंश के पंडित मिहिरकुल हूण ने करवाया था। मिहिरकुल हूण के बारे में मंदसोर अभिलेख में लिखा हुआ है की 'यशोधर्मन से युद्ध होने से पहले तक मिहिरकुल हूण ने शिव के अलावा किसी और के सामने अपना सर नहीं झुकाया था'। मिहिरकुल की शिव भक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां एक तरफ हर राजा अपने राज्य में छपने वाले सिक्कों पर अपनी उपाधि या अपना नाम लिखवाते थे वहीं मिहिरकुल के राज्य में छपने वाले सिक्कों पर जयतु वृष लिखा रहता था जिसका मतलब है जय नंदी। हनोल का ये महासू मंदिर हूण शैली में बना है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के मुताबिक ये मंदिर 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में बना है। बौठा महासू के अलावा बासक महासू मेंड्रथ गांव में, पिबासक महासू ठडियार गांव में पूजे जाते हैं और इन सबके छोटे भाई चालदा महासू को घुम्मकड़ देवता कहा जाता है। चालदा महासू की पूजा हर साल अलग-अलग जगहों पर की जाती है। लोक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि चालदा महासू 12 साल उत्तरकाशी और 12 साल देहरादून में घूमते हैं।

मंदिर के अंदर छिपा है रहस्य

महासू देवता का मंदिर अपने अंदर कई रहस्य छिपाए हुए है। कहा जाता है कि इस मंदिर के गर्भगृह में एक अखंड ज्योति जलती रहती है, पर इसके गर्भगृह में जाने की अनुमति मंदिर के मुख्य पुजारी के अलावा किसी को भी नहीं है। लोकमान्यता है कि गर्भगृह में यह दिव्य ज्योत पुजारी के अलावा किसी ने नहीं देखी है। ये भी कहा जाता है की मंदिर के अंदर ही एक जल की धारा भी निकलती है, जिसका जल बाहर नहीं दिखता। यही जल धारा महासू देवता का जलाभिषेक करती है। इस जल धारा का ना आदि का पता है, ना ही अंत का। यह जल की धारा मंदिर के अंदर से बहते हुए ही अदृश्य भी हो जाती है। किंतु यही जल यहां प्रसाद के रूप में दिया जाता है। महासू देवता को न्याय के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। महासू की कीर्ति सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह दूर-दूर तक फैली है। न्याय के देवता और उनके न्यायालय का सीधा कनेक्शन दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से भी है। महासू देवता के इस न्यायालय में दिल्ली के राष्ट्रपति भवन की ओर से हर साल नमक भेंट किया जाता है। लोक मान्यता है कि एक बार महासू देवता का डोरिया (प्रतीक चिह्न) टोंस नदी में गिर गया था, जो बहते हुए यमुना नदी के साथ दिल्ली पहुंच गया। वहां ये डोरिया किसी मछुआरे को मिला जिसने इसे डोरिया के राजा को दे दिया। राजा इस डोरिया का इस्तेमाल नमक रखने के लिए करने लगा। समय बीता राजा के साथ अनहोनी होने लगी। जिसके बाद राज पुरोहितों ने राजा को इसका कारण महासू देवता का नाराज होना बताया। राजा ने तुरंत अपने कृत्य के लिए महासू देवता से माफी मांगी और इस दोष के निवारण तथा महासू देवता को खुश करने के लिए राजा के दरबार से हर साल महासू देवता को नमक भेंट किया जाने लगा। जो समय के साथ रीत बन गई और आज के आधुनिक दौर में भी राष्ट्रपति भवन इस रीत को निभा रहा है। अब महासू देवता मंदिर को उत्तराखंड के पांचवें धाम के रूप में मान्यता देने की मांग की जा रही है।

मंदिर के चौथे द्वार से गर्भ गृह में सिर्फ पुजारी को ही जाने की अनुमति है और वह भी पूजा के समय ही जा सकते हैं, किवदंतियां हैं कि पांडवों ने घाटा पहाड़ के पत्थरों को तोड़कर विश्वकर्मा जी से हनोल मंदिर का निर्माण कराया था।

विशाल जागड़ा मेला

महासू देवता के मंदिर में भाद्रपद की शुक्ल पक्ष में हरतालिका तीज के दिन बड़े धूमधाम से विशाल जागड़ा मेले का आयोजन किया जाता है। जागड़ा का शाब्दिक अर्थ होता है रात का जागरण। जागड़ा उत्सव के दिन न्याय के देवता महासू की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रख कर रात भर महासू देवता के न्यायालय में जागरण करते हैं और सुबह होते ही महासू देवता की प्रतिमा को देवडोली में बैठा कर लोकवाद्यों की मधुर ध्वनि के साथ यमुना और भद्रीगाड़ में स्नान के लिए ले जाते हैं। श्रद्धालु देवडोली को एक बार मंदिर से उठाने के बाद रास्ते में कहीं भी नहीं उतारते। इसलिए श्रद्धालु बारी-बारी से कंधे बदलते हुए डोली को मंदिर से ले जाकर स्नान कराते हैं और वापस मंदिर पहुंचने पर ही देव डोली कंधे से उतारी जाती है। मंदिर में फिर से स्थापित होने के बाद महासू देवता की पूजा की जाती है जिसके बाद व्रत भी पूर्ण मान लिया जाता है।

मंदिर के चार द्वार

महासू मंदिर में प्रवेश के लिए चार दरवाजे हैं। प्रवेश द्वार की छत पर नव ग्रह सूर्य, चंद्रमा, गुरू, बुध, शुक्र, शनि, मंगल, केतु व राहु की कलाकृति बनी है। पहले और दूसरे द्वार पर विभिन्न देवी-देवताओं की आकृतियां उकेरी गई हैं। दूसरे द्वार पर ढोल नगाड़े के साथ पूजा-अर्चना होती है। तीसरे द्वार पर स्थानीय लोग, श्रद्धालु और सैलानी माथा टेकते हैं। अंतिम द्वार से गर्भ गृह में सिर्फ पुजारी को ही जाने की अनुमति है और वह भी पूजा के समय ही जा सकते हैं। किवदंतियां हैं कि पांडवों ने घाटा पहाड़ के पत्थरों को ढोकर विश्वकर्मा जी से हनोल मंदिर का निर्माण कराया था।

न्याय के देवता महासू

महासू देवता को न्याय प्रिय देवता मानते हैं। वैसे भी विश्व में जो भी शक्तिशाली होता है उससे ही हर कोई न्याय की उम्मीद करता है। इसी प्रकार से जौनसार बावर के आराध्य महासू देवता पर हिमाचल, जौनपुर, टिहरी गढ़वाल के लोग अटूट श्रद्धा रखते हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, सोलन, शिमला, बिशैहर और जुब्बल तक महासू देवता को इष्ट देव (कुल देवता) के रूप में पूजा जाता है। इन क्षेत्रों में महासू देवता को न्याय के देवता और मंदिर को न्यायालय के रूप में मान्यता मिली हुई है। महासू देवता का मुख्य मंदिर हनोल गांव में स्थित हैं जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शनार्थ पहुंचते हैं और संकट में न्याय की गुहार लगाते हैं। हनोल महासू मंदिर के पुजारी राय दत्त जोशी का कहना है कि दिल्ली से गूगल धूप डाक द्वारा हर साल मंदिर को मिलती है, लेकिन यह नहीं पता कि कौन इसे भेजता है। उनका कहना है कि जो लोग कोर्ट-कचहरी से थक जाते हैं वह हनोल मंदिर में अपनी सच्ची आस्था से न्याय पाने और कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना करते हैं। सच्चे मन से की गई प्रार्थना महासू देवता अवश्य सुनते हैं और सभी मनोकामना पूरी करते हैं।

नजरिया

विवादों में हुड़किया बौल

कुछ लोग पहाड़ में खेती के काम में सदियों से चली आ रही पलटा प्रथा को ही 'हुड़किया बौल' समझने की गलती कर रहे हैं, पलटा प्रथा में आप अदला-बदली कर एक दूसरे के काम में हाथ बटाते हैं, यानी आज हमने आपकी मदद की कल आप हमारी मदद को आएंगे, यह प्रथा आज भी पहाड़ के गावों में जीवंत है।

उदयभान सिंह
लेखक

- देवभूमि उत्तराखंड में लोकगीत और श्रम का अटूट रिश्ता है, घस्यारियों (घास काटने वाली महिलाए) और ग्वालों (पशु चराने वाले) के गीत जंगल को भी रंगीला बना देते हैं। पहाड़ के रहने वालों का मानना है कि गीत न केवल काम की गति बढ़ाते हैं, बल्कि थकान भी महसूस नहीं होते देते।
- हुड़के की थाप पर गीतों के साथ हुड़किया बौल का आयोजन होता है तो पता ही नहीं चलता कि रोपाई और गुड़ाई कब पूरी हो गई, खेती के काम को फटाफट निपटाने के लिए ही शायद हुड़किया बौल की शुरुआत हुई होगी।

देवभूमि उत्तराखंड अपनी लोक संस्कृति और रीति रिवाजों को लेकर देश-दुनिया में अलग पहचान रखता है। यहां कई परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं, हालांकि आधुनिकता की इस दौड़ में कुछ परंपराएं ही नहीं बल्कि लोक संस्कृति भी पीछे छूट गई है। फिर भी कुछ गांव के लोगों ने आज भी पुरानी परंपराओं को जिंदा रखा हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड में लोकगीत और श्रम का अटूट रिश्ता है। घस्यारियों (घास काटने वाली महिलाएं) और ग्वालों (पशु चराने वाले) के गीत जंगल को भी रंगीला बना देते हैं। पहाड़ के रहने वालों का मानना है कि गीत न केवल काम की गति बढ़ाते हैं, बल्कि थकान भी महसूस नहीं होते देते। हुड़किया बौल भी इसी परंपरा का एक हिस्सा है। हुड़किया बौल का अर्थ सामूहिक रूप से किए जाने वाले कृषि कार्य के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है। हुड़किया बौल का आयोजन मुख्यतः बरसात के मौसम में धान की रोपाई, मडुवे की गुड़ाई के समय होता है। इस आयोजन में पूरे गांव की भागीदारी होती है। बरसात के मौसम में कभी बारिश तो कभी तेज धूप में काम करना थकान भरा और उबाऊ होता है। हुड़के की थाप पर गीतों के साथ हुड़किया बौल का आयोजन होता है तो पता ही नहीं चलता कि रोपाई और गुड़ाई कब पूरी हो गई। खेती के काम को फटाफट निपटाने के लिए ही शायद हुड़किया बौल की शुरुआत हुई होगी। यानी हुड़का वादक गीत शुरू करता है और धान की रोपाई में लगे स्त्री पुरुष उन्हीं पंक्तियों को दोहराते हुए काम करते हैं। लोक गीतों में प्रेम गाथाएं, व्यथा गाथाएं या वीर गाथाएं होती हैं। इसमें कुमाऊं क्षेत्र में भीमा कठैत, मालूशाही, कलबिष्ट आदि की लोकगाथाएं प्रमुख हैं। इनके साथ कत्यूरी शासक राजा बिरमदेव (ब्रह्मदेव) की कहानी भी प्रमुख है। बौल को शुरू करने से पहले रोपाई या गुड़ाई करने आए लोग कृषि यंत्र और बैलों को अक्षत रोली का टीका लगाते हैं। इसके बाद हुड़किया (श्रमगीत गाने वाला) हुड़के की थाप पर देवी-देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और लोकदेवता भूमिया, ग्वल, हरु और सैम का आह्वान करके कार्य सिद्धि की प्रार्थना करता है। इसके साथ ही हुड़किया बौल शुरू हो जाता है।

हुड़किया बौल या श्रमिकों का शोषण

हुड़किया बौल के चार रूप होते हैं। पहला आह्वान, दूसरा प्रार्थना-शुभकामना, तीसरा गीत का विषय कथात्मकता और चौथा मंगलकामना होता है। हुड़किया गीत की शुरुआत करता है और कृषि कार्य करने वाले स्त्री-पुरुष उन स्वरों को संयुक्त रूप से दोहराते हैं। गीतों की मधुर धुनों में वे इतना खो जाते हैं कि उन्हें थकान का पता ही नहीं चलता और गीत गाते-गाते काम भी निपट जाता है। अंत में हुड़किया दिन ढ़लने का संकेत देते हुए बार-बार आते रहने की कामना करता है। कृषकों और बैलों के जीवन की मंगल कामना के साथ गीत समाप्त करता है। हुड़किया बौल की परंपरा अब या तो कम हो गई है या फिर नाम मात्र की रह गई है। इसकी एक वजह खेती के प्रति घटना रुझान भी है तो दूसरी तरफ समाज में सामूहिकता के भाव की कमी है। आम तौर पर हुड़किया बौल का अर्थ सामूहिक रूप से किए जाने वाले कृषि कार्य के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है। लेकिन अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव पुरुषोत्तम शर्मा ने अपने एक लेख में इसकी जो व्याख्या की है उससे हुड़किया बौल का अर्थ ही बदल जाता है। पुरुषोत्तम शर्मा अपने लेख में लिखते हैं कि बहुत से लोग पहाड़ में हुड़किया बौल को पहाड़ की संस्कृति के रूप में प्रचारित करते हैं। जबकि हुड़किया बौल का अर्थ श्रमिकों से हुड़के की थाप पर खेतों में बिना मजदूरी काम कराने से है। इसे पहाड़ की संस्कृति के रूप में प्रचारित नहीं करना चाहिए। इसकी वजह भी बताते हैं यानी यह आम जन का कोई सामूहिक जुड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, जैसा अब प्रचारित किया जाता है। यह तो वास्तव में पहाड़ के जमींदारों, मालगुजारों, थोकदारों या बड़ी जमीनों के मालिकों द्वारा अपने खेतों में ग्रामीणों, गरीबों से कराई जाने वाली बेगार प्रथा (बिना मजदूरी के श्रम) का हिस्सा थी। उनके पास एक ही जगह में काफी जमीन होती थी, इसलिए अपने प्रभाव व अपनी ताकत के बल पर हुड़किया बौल आयोजित किया जाता था। जो मनोरंजन के साथ श्रमिकों के शोषण का एक सामंती प्रभुत्व जताने वाला आयोजन होता था। पुरुषोत्तम शर्मा लिखते हैं कि मैंने बचपन में ऐसे बहुत से आयोजन देखे हैं। कहीं भी सामूहिक खेती या गरीब व छोटे किसानों के खेतों में किसी बड़े काश्तकार को काम करते कभी नहीं देखा। छोटे किसान के खेत में कभी हुड़किया बौल का आयोजन नहीं होता था। पुरुषोत्तम शर्मा का तर्क है सामूहिक श्रम के लिए 'पलटा' शब्द सही है जबकि 'हुड़किया बौल' का अर्थ श्रम के शोषण से है।

हुड़किया बौल का अर्थ श्रमिकों से हुड़के की थाप पर खेतों में बिना मजदूरी काम कराने से है, यानी यह आम जन का कोई सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, यह तो वास्तव में पहाड़ के जमींदारों, मालगुजारों, थोकदारों या बड़ी जमीनों के मालिकों द्वारा खेतों में ग्रामीणों, गरीबों से कराई जाने वाली बेगार प्रथा का हिस्सा थी।

दम तोड़ने लगी प्रथा

उत्तराखंड के लोगों का कहना है कि बौल का मतलब सामूहिक श्रम अथवा श्रम है। किंतु मेरी नजर में 'बौल' का मतलब सामूहिक श्रम या श्रम नहीं है। न ही 'बौल' शब्द का लोक जीवन में वो अर्थ है, जैसा समझाने का प्रयास हो रहा है। 'बौल' का अर्थ लोकोक्तियों में बिना मजदूरी भुगतान के या बल पूर्वक कराए जाने वाले श्रम से है। जैसे 'मैं किलै करूं, मैं क्वे त्यार बौली छुं रे?' यानी मैं क्यों करूं, मैं कोई तेरा बौल करने वाला हूं रे? 'बौली नि छुं मि त्यर' यानी मैं तेरा बौल करने वाला नहीं हूं। मतलब साफ है, आज भी पहाड़ की आम बोलचाल में बौल का अर्थ सामूहिक श्रम या श्रम माना जाता है। 'बौल' करने वाली श्रेणी मानव समाज में कृषि व पशुपालन पर आधारित मानव जीवन के शुरुआती जनजातीय संघों में नहीं थी। वहां सामूहिक स्वामित्व और सामूहिक श्रम का बोलबाला था। यह तो उन जनजातीय संघों के विघटन से पैदा वर्ग, विभाजित समाज बनने के साथ अस्तित्व में आई श्रेणी है। यानी दास समाज और सामंती समाज से उत्पन्न संबंधों के दौरान यह श्रेणी पूरी तरह वजूद में रही है, लेकिन जमींदारी विनास कानून के लागू होने के बाद, ग्रामीण जीवन में आधुनिक पूंजीवादी संबंधों के प्रवेश ने इस श्रेणी को स्वतंत्र मजदूर की श्रेणी में बदल दिया। जो अपने श्रम के मूल्य का मोलभाव भी कर सकता है। इसलिए पहाड़ में जमींदारी विनाश कानून के क्रियान्वयन के बाद ही यह 'हुड़किया बौल' की प्रथा दम तोड़ने लगी थी।

हुड़किया बौल नहीं पलटा प्रथा

पुरुषोत्तम शर्मा लिखते हैं कि 'हुड़किया बौल' के साथ गाये जाने वाले गीतों की बात करें तो ये ज्यादातर गीत पहाड़ के पुराने कृषि एवं पशुपालन पर आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाले जीवन से जुड़े होते हैं। इनका शुरुआती वैदिक काल के उस लोक जीवन से ज्यादा जुड़ाव दिखता है, जहां अपनी सामूहिक समृद्धि के लिए अन्न की बेहतर पैदावार और पशुधन वृद्धि के लिए ऋतु यानी प्रकृति का आह्वान किया जाता था। बाद में इसमें नए देवता और नई भाववादी स्तुति जोड़ी गई। पर ज्यादातर प्रकृति से ही जुड़ी हैं। जिनमें अच्छी वर्षा, काम के दौरान आसमानी छांव, अच्छा पानी, अच्छी फसल के लिए भूमि देवता, इंद्र देवता, वरुण देवता, सूर्य देवता आदि का आह्वान होता है। पर इसमें सब इहलौकिक है। लोगों की इच्छा भी और देवता भी। कुछ भी परलौकिक नहीं है। हुड़किया बौल और गुड़ौल गीत दोनों एक ही तरह के हैं। ये गीत ऐसे नहीं हैं जो सिर्फ हुड़के की थाप पर ही गाय जाते हों। अकेले खेतों में काम कर रही महिलाएं या जंगल में घास काट रही महिलाएं भी इनकी अलग-अलग लाइनों को गाते हुए गीत पूरे करती हैं। इन गीतों में मेहनतकश जीवन जीने वाली ये कृषक महिलाएं जमींदारों और राजाओं की कोमल शरीर वाली रानियों की भी चर्चा करती थी। उदाहरण के लिए-

कुस्यारु क ड्वक जसि, सुरज कि जोति,
छोलियां हल्द जसि, पालङ कि काति
सितो भरि भात खायोत उखालि मरन्यां
चूल भरि पॉणि खायोत नडछोलि मरन्या

यानी जेठ में आडू से लदे डोके जैसी, सूर्य की ज्योति जैसी, कच्ची हल्दी जैसी, पालक की कली जैसी, हियां रानी इतनी नाजुक है कि सीते भर भात (चावल का एक पका हुआ दाना) भी खा ले तो उल्टी कर देती है अंजुली भर पानी पी ले तो उसे जुकाम हो जाता है) कुछ लोग पहाड़ में खेती के काम में सदियों से चली आ रही पलटा प्रथा को ही 'हुड़किया बौल' समझने की गलती कर रहे हैं। पलटा प्रथा में आप अदला-बदली कर एक दूसरे के काम में हाथ बटाते हैं। यानी आज हमने आपकी मदद की कल आप हमारी मदद को आएंगे। यह प्रथा आज भी पहाड़ के गावों में जीवंत है। क्योंकि यह उनके अब तक बचे सामूहिक जीवन के अवशेषों की अभिव्यक्ति है। पर 'हुड़किया बौल' को पलटा बताने वाले ऐसा एक भी उदाहरण नहीं दे सकते जिसमें मालगुजार, थोकदार या पधान कभी हुड़का बजाने वाले या उनके खेतों में काम करने वाले गरीब किसानों के खेतों में काम करने गए हों।

काम के बदले अनाज

अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव पुरुषोत्तम शर्मा ने अपने लेख में उल्लेख किया है कि पहाड़ के बहुत से लोगों का कहना है कि पुराने जमाने में लोगों को काम के बदले अनाज दिया जाता था। यह सच है कि पहले काम के बदले फसल पर अनाज देने की प्रथा थी। यह प्रथा अभी 20-25 साल पहले तक पूरी तरह अस्तित्व में थी। इसमें लोहार, तेली, दास-दर्जी, हलिया, शिल्पकार दलित जातियों, जागर लगाने वालों, वैद्य या समारोहों में खाना पकाने वाले ब्राह्मण वर्ग के लोग भी शामिल थे। पर इन्हें भी काम के बदले अनाज की जो मात्रा दी जाती थी, वो उनके काम के बदले तय की गई मजदूरी का हिस्सा नहीं होती थी। इसमें काम कराने वाले ही खुद अपनी मर्जी से इन कामगारों को फसल पर अनाज दिया करते थे। यह प्रथा 'कुली उतार प्रथा' थी। जिसमें काम करने वाले को मेहनताना तो मिलता था, पर बिना मूल्य तय किए मालिक की मर्जी के अनुसार। जमींदारी विनाश कानून लागू होने से पहले पहाड़ की ज्यादातर कृषि भूमि राजाओं, मालगुजारों, थोकदारों, पधानों के पास थी। पक्के खायकारों को छोड़कर अगली पीढ़ी को भूमि हस्तांरण का भी अधिकार ज्यादातर गरीब किसानों को नहीं था। 'खायकर उसे कहते जो जमीन में खेती करके दे साथ ही मालगुजारी भी दे।' अंग्रेजों ने भी पहाड़ पर अपने 132 वर्षों के शासनकाल में इस व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं की। क्योंकि उन्हें इसी प्रभुत्वशाली वर्ग के जरिये नीचे तक अपना शासन चलाना था। शिल्पकारों की 99 प्रतिशत आबादी तब भूमिहीन थी और उनमें से ज्यादातर आज भी भूमिहीन ही हैं। ऐसी स्थिति में पहाड़ की ज्यादातर ग्रामीण आबादी तब इन राजाओं, मालगुजारों, थोकदारों, पधानों के रहमो करम पर थी और न सिर्फ उनका बल्कि बाद में उनके माध्यम से अंग्रेजों का भी 'बौल' बनने को मजबूर थी। पुरुषोत्तम शर्मा के लेख से इतर उत्तराखंड में आज भी हुड़किया बौल का सीधा संबंध खेती से माना जाता है। सिंचित भूमि पर धान की रोपाई के समय इस विधा का प्रयोग होता है। जिसमें महिलाएं कतारबद्ध होकर रोपाई करती हैं। ऐसा माना जाता है कि हुड़किया बौल की वजह से दिन भर रोपाई के बावजूद श्रमिकों को थकान महसूस नहीं होती। हुड़के की थाप पर लोकगीतों में ध्यान लगाकर महिलाएं तेजी से रोपाई के कार्य को निपटाती हैं। समूह में कार्य कर रही महिलाओं को हुड़का वादक अपने गीतों से जोश भरने का काम करता है। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी कुमाऊं के कई हिस्सों में जीवंत है।

ऋतुओं का स्वागत हिंदू त्योहार से

पुराणों में वृक्षों का अत्यधिक गुणगान किया गया है, सत्कवियों ने भी 'तरुवर फल नहिं खात हैं, सरवर पियहिं न पान' तथा 'वृक्ष कबहुं नहिं फल भखें, नदी न संचय नीर' जैसी सूक्तियों के द्वारा वृक्षों की महिमा गाई है, पुराणों में तो वृक्ष को बेटे के समान बताया गया है।

ओमप्रकाश मंजुल
पूरनपुर पीलीभीत

सनातन संस्कृति में पर्व उत्सवों की विशेष व्यवस्था की गई है। तीज-त्योहारों से लोक में उत्साह और ऊर्जा प्रवाहित होती है। लोगों में संपूर्ण वर्ष हर्षोल्लास बना और बढ़ा रहे, इसके लिए हिंदू संस्कृति ने सभी प्रमुख त्योहारों को प्रमुख ऋतुओं से जोड़ दिया। हर मौसम का मजा निराला होता है। इसलिए मौसम के मिजाज के अनुरूप ही त्योहारों को बनाकर विकसित किया गया है। सनातन धर्म में आदिकाल से या यूं कहें, आदिधर्म ने सनातन काल से त्योहारों व पर्वों के माध्यम से आने वाली ऋतु का स्वागत किया है। चंद्रवंदना, शरद-सुंदरी का आगमन कार्तिक मास (अक्टूबर) में होता है, जिसकी हिंदूलोक ने दीपों का थाल सजाकर आरती उतारी। इसे, 'दीप मालिका','दीपावली', 'दीपोत्सव' आदि नाम दिए गए। चैत्र मास (मार्च) में पदार्पण करके अपने प्रखर तेज से लोक को पानी-पानी कर देने वाली, सूरजमुखी ग्रीष्मकालीन नायिका का भारतीय मनीषा ने गर्मजोशी के साथ पवित्र होली के ज्वालालोक में अभिनंदन गीतों के साथ स्वागत किया। अपनी बूंदों की रिमझिम-रिमझिम रूपी नूपुरों की छम-छम से जमीन पर जमकर नाचने वाली, बरखारानी आषाढ़ मास (जुलाई) में आकाश से उतरती हैं। इनका जलाभिषेक हरियाली तीज के गीतों द्वारा किया गया है। तीनों ही ऋतुओं का स्वागत समारोह लंबे समय तक चलता रहता है। केसरवर्णी पवित्र होली का त्योहार दो सप्ताह तक, श्वेतांबरी शुभ दीपावली का त्यौहार एक सप्ताह तक तथा हंसमुखी हरियाली का पर्व अर्धसप्ताह तक मनाया जाता है। कैसा 'मणि-मुक्ता-कांचन' संयोग है, होली, दीपावली और हरियाली पर्व के क्रमशः केसरिया, सफेद और हरा रंग ही भारत के राष्ट्रध्वज में शोभा के साथ प्रयुक्त हैं।

कागजों पर पौधारोपण

विगत कई वर्षों से भारत की धर्मनिरपेक्ष सरकारें भी अर्धसप्ताह तक चलने वाले इस हरियाली पर्व का सरकारी नामकरण, 'वन महोत्सव' करके सप्ताह भर तक मानने व मनाने लगीं हैं। पावस ऋतु का पावन, 'हरीतिमा पर्व' श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया हरियाली तीज से पंचमी यानी नाग पंचमी तक चलता है। लोक में सुरसा की भांति बढ़ रही भौतिकता के कारण अब हरियाली तीज मात्र चूड़ी- बिंदी, 'मेहंदी प्रतियोगिता', झूला या 'सावनगीत प्रतियोगिता' तक ही सीमित हो जाने के कारण महिलाओं के लिए एक इवेंट बनकर रह गया है। हालांकि हरियाली तीज हिंदुस्तान का ऐतिहासिक ही नहीं, पौराणिक पर्व रहा है। जनमानस में इसका इतना अधिक प्रभाव रहा है, कि 'तीज' शब्द त्योहार का पर्याय ही बन गया। लोग-बागों ने पर्वों और उत्सवों के लिए, 'तीज- त्योहार' युगल शब्द का ही प्रयोग करना शुरू कर दिया, जो आज भी बदस्तूर जारी है। हालांकि प्रतिवर्ष 1 से 7 जुलाई तक भारत सरकार की ओर से, 'वन महोत्सव' नाम से वन संरक्षण, वृक्षारोपण और पर्यावरण शुद्धता को दृष्टि में रखकर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें लोक मानस को आकर्षित करने के लिए, 'आज देश की यही पुकार, बच्चे दो और वृक्ष हजार' तथा 'वृक्ष प्रदूषण-विष पी जाते, पर्यावरण पवित्र बनाते' जैसे कर्णप्रिय स्लोगन का उद्घोष किया जाता है। ऐसे ही गीत भी सावन मास में बजाए जाते हैं। पर इनमें से ज्यादातर चीजें कागजी ही हैं, जमीनी नहीं। सरकारी कर्मकांड को लोग, 'काम कम और बातें ज्यादा' के रूप में जानते हैं। अन्यथा 1960 के करीब जब कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी कृषि मंत्री थे, तब से चला आ रहा, 'वन महोत्सव' ईमानदारी के साथ संपन्न किया गया होता, तो आज संपूर्ण विश्व में भारत के वन दिखाई दे रहे होते। किंतु आजादी के बाद से ही भारत में भ्रष्टाचार ने ऐसे पैर जमाए कि पौधारोपण कागजों पर ही होता रहा।

- **हरियाली तीज हिंदुस्तान का ऐतिहासिक ही नहीं, पौराणिक पर्व रहा है, जनमानस में इसका इतना प्रभाव रहा है, कि 'तीज' शब्द त्योहार का पर्याय बन गया, लोगों ने पर्वों और उत्सवों के लिए, 'तीज- त्योहार' युगल शब्द का प्रयोग करना शुरु कर दिया, जो आज भी बदस्तूर जारी है।**
- **1960 में जब कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी कृषि मंत्री थे, तब से 'वन महोत्सव' ईमानदारी के साथ संपन्न किया गया होता, तो आज संपूर्ण विश्व में भारत के वन दिखाई दे रहे होते, किंतु आजादी के बाद से भ्रष्टाचार ने ऐसे पैर जमाए कि पौधारोपण कागजों पर ही होता रहा।**

प्रकृति की मानव को चेतावनी

हमारे ऋषिगण पौराणिक काल से वृक्षों का महत्व जानते और समझते थे। इसलिए उन्होंने,'हरियाली तीज' और 'नाग पंचमी' को अपने जीवन-दर्शन व जीवन-शैली में स्थान दिया था। महाभारत के 'दान-धर्म' पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं, कि जो जन पेड़-पौधे लगाकर हरीतिमा संवर्धन करते हैं, उन्हें इस लोक में तो यश मिलता ही है, पितरलोक में भी पितरगण उनके प्रति प्रसन्नता एवं प्रेम का भाव रखते है तथा देवलोक में भी श्रीनारायण और देवताओं की उन पर कृपा रहती है। जब तक हमारे ऋषियों की विचारधारा को देश-दुनिया ने अपनाया, तब तक प्रकृति का चक्र सही और संतुलित रहा। तब न तो प्राकृतिक क्रिया-कलापों में कोई व्यतिक्रम उपस्थित हुआ और न पर्यावरण प्रदूषण जैसी कोई समस्या पैदा हुई। किंतु जब से आधुनिक ज्ञान और अति नवज्ञान के दंभ में दुनिया में आप्त वचनों को भुला दिया और वनों का विनाश कर कंक्रीट के वन बनाने शुरू किए, अध्यात्मवाद को त्यागकर भौतिकता की कीचड़ को गले से लगाना शुरू किया, तब से केदारनाथ और वायनॉड जैसी हृदय विदारक त्रासदियों से हमें गुजरना पड़ रहा है। प्रकृति ने अकारण-असमय-अस्थान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, हिमपात, वज्रपात, ज्वालामुखी-विस्फोट और बादल-ब्लास्ट आदि के रूप में मानव को चेतावनी देना शुरू कर दिया है ।

पुराणों में वृक्ष को बेटे के समान बताया

इन दिनों उत्तरोत्तर ग्रीनहाउस गैसे बढ़ती जा रही हैं, ऑक्सीजन घटती जा रही है तथा वायुमंडल व सौरमंडल के क्रिया-कलापों में भारी उथल-पुथल से वैज्ञानिकों एवं मौसम विशेषज्ञों की भविष्यवाणियां फेल हो रहीं हैं। हमारे पूर्वजों के व्यापक दृष्टिकोण के कारण उनकी पलकों के नीचे पर्यावरण का विस्तृत फलक था। वे जानते थे, कि सर्प भी पर्यावरण का जहर (कार्बन-डाइ-ऑक्साइड) खींच कर पर्यावरण को स्वस्थ बनाते हैं। इसलिए उन्होंने नाग पंचमी का त्योहार मनाकर सर्पों की पूजा करने की भी परंपरा डाली। हालांकि नागपूजा का एक दूसरा संदेश यह भी है, कि हिंदू आदिकाल से इतना उदारमना है कि वह अपने स्वाभाविक शत्रुओं को भी अपने प्रेमिल व्यवहार से मित्र बनाने की क्षमता रखता है। इतना उदार और विशाल-हृदय दर्शन किसी भी धर्म-संप्रदाय में नहीं मिलता। वृक्षों की कृपा का तो कहना ही क्या! खुद मानवों से डंडे और पत्थर खाते हैं और बदले में उन्हें अपने मीठे, रसीले और अमृतोपम रसाल खिलाते हैं। वृक्ष हमारा विष यानी कार्बन-डाइ-ऑक्साइड स्वयं पीते हैं और अपना अमृत स्वरूप ऑक्सीजन हमें पिलाते हैं। दुनिया में इतनी मानव-हितैषी, दूसरी कोई योनि (प्राणी) नहीं है। इसलिए पुराणों में वृक्षों का अत्यधिक गुणगान किया गया है । सत्कवियों ने भी 'तरुवर फल नहिं खात हैं, सरवर पियहिं न पान' तथा 'वृक्ष कबहुं नहिं फल भखें, नदी न संचय नीर' जैसी सूक्तियों के द्वारा वृक्षों की महिमा गाई है। पुराणों में तो वृक्ष को बेटे के समान बताया गया है। कहीं-कहीं पेड़ को पुत्र से भी अधिक महत्व प्रदान किया गया है।

हमे वृक्षों को देवता मानने वाले हिंदू दर्शन की ओर मुड़ने की जरुरत है, हिंदू दर्शन में पाकर, पीपल और तुलसी, वट वृक्ष आदि पेड़-पौधों को, पकरिया बाबा', 'ब्रह्मदेव बाबा', 'तुलसी महारानी' आदि कहने के पीछे यही अवधारणा रही है कि पौधों का संरक्षण किया जाए।

300 वर्ष पुराने इतिहास में झांकें

पुराणों की बात न भी करें, तो मात्र 300 वर्ष पूर्व का ही इतिहास झांक लिया जाएं। यह ऐतिहासिक घटना (वस्तुतः दुर्घटना) राजस्थान की मारवाड़ रियासत के जोधपुर जिले के खेजलड़ी गांव की है। खेजलड़ी गांव में खेजड़ी (शमी) वृक्ष बड़ी संख्या में मिलते है। शायद इसी कारण गांव का नाम 'खेजलड़ी' पड़ा हो। खैर उस समय मारवाड़ रियासत के राजा अभय सिंह थे। 1731 में उन्होंने शमी के पेड़ों को काटने का फरमान जारी किया, पर वहां की विश्नोई जाति ने वृक्षों के विनाश का विरोध किया। हठ में अहंकार होता ही है, कोई भी हठ हो, पर राजा में तो हठ की पराकाष्ठा होती है। सो राजा नहीं माना, उधर विश्नोई समाज ने वृक्ष न काटने देने को जीवन का सिद्धांत और प्रतिष्ठा का विषय बना लिया था। एक कवि ने विश्नोई समाज की हठ का उल्लेख कुछ इस तरह के शब्दों से किया,

एक नियम था हरा वृक्ष कटने न कभी देना है।
अगर जरूरत पड़े पेड़ के बदले सर दे देना है।।

राजस्थान में अमृता देवी विश्नोई नामक 42 वर्षीय महिला के नेतृत्व में बलिदानी जत्थे के लोग काटे जाने वाले वृक्षों से चिपक गए और जीवन का मोह तथा मृत्यु का भय न मानते हुए कुल्हाड़ियों द्वारा बारी-बारी से कटते चले गए। इस प्रकार 363 वृक्ष-भक्त शहीद हुए और अमृता देवी तथा उनके अनुयाई मर कर भी अमर हो गए। जब तक विश्व में वृक्ष रहेंगे (जो सदा रहेंगे ही) तब तक इन शहीद विश्नोइ महिलाओं का नाम अमर रहेगा। (इस प्रसंग में करणप्रयाग उत्तराखंड) के एक कृषक, जगत सिंह चौधरी का उदाहरण भी कम प्रेरक नहीं है, जिन्होंने अकेले अपने दम पर 45 वर्ष पूर्व 4500 फीट की ऊंचाई पर अपनी चार एकड़ भूमि पर चीड़, बुरांश, काफल, आंवला, सागौन, संतरा, जामुन, रुद्राक्ष, देवदार आदि के 20,000 से अधिक वृक्षों वाला वन लगाया था। पर्यावरण विनाश के शिखर पर खड़े संसार की रक्षार्थ आज जल, जंगल, जमीन के नवीन समीकरण बनाए जाने की जरूरत है। आज जहां सारे विश्व में पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण विनाश के कारण 'त्राहिमाम' की स्थिति है, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण-सुरक्षा पर सम्मेलन हो रहे हैं, वहीं वृक्षों को देवता मानने वाले, हिंदू दर्शन की ओर मुड़ने की परम आवश्यकता है। यह दर्शन हजारों वर्षो से हमें सचेत करता आ रहा है। हिंदू दर्शन में पाकर, पीपल और तुलसी, वट वृक्ष आदि पेड़-पौधों को, पकरिया बाबा', 'ब्रह्मदेव बाबा', 'तुलसी महारानी' आदि कहने के पीछे यही अवधारणा रही है। अमृता देवी तथा उनके अनुयाइयों ने वृक्षों की खातिर अपने सर दे दिए थे। हम सर न दें, थोड़ा सा समय ही दे दें, तो वृक्षों के ऋण से उऋण हो जाएंगे। इतना भी न कर सकें, तो कम से कम अपने हाथों वनस्पति जगत की हिंसा तो ना ही करें। वेदों में वनस्पति की स्थान-स्थान पर स्तुति की गई है। इतना ही नहीं, हर प्रकार के धर्मानुष्ठान के समापन पर किए जाने वाले 'शांतिपाठ' में भी विश्व ब्रह्मांड के मुख्य देवी-देवताओं के साथ ही वन-वनस्पति की भी 'वनस्पतयः शांति' कहकर प्रार्थना की गई है। ●

एक्टर से पहले दरोगा थे राजकुमार

राजकुमार की पर्सनालिटी ही ऐसी थी कि फिल्म में उनके लिए खासतौर पर चुन-चुन कर डायलॉग लिखे जाते थे, इसके लिए डायलॉग राइटर्स को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन पर्दे पर दमदार दिखने वाले राजकुमार के सभी डायलॉग्स के पीछे एक संदेश छिपा होता था।

महज फिल्म वक्त का यह ये डायलॉग 'जानी बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है...' और 'गेंडा स्वामी...' ही काफी है। दमदार डायलॉग डिलीवरी के बेताज बादशाह कुलभूषण पंडित उर्फ राजकुमार का नाम फिल्म जगत की आकाश गंगा में ऐसे धुव्रतारे की तरह है, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। राजकुमार का जन्म पाकिस्तान के ब्लूचिस्तान प्रांत में 8 अक्तूबर 1926 को एक मध्यम वर्गीय कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजकुमार मुंबई के माहिम पुलिस स्टेशन में बतौर सब इंस्पेक्टर काम करने लगे। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना-जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे किसी जरूरी काम के लिए आए थे। वह राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और राज को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दे दिया। इसे राजकुमार ने तुरंत मान लिया और पुलिस की नौकरी छोड़कर बॉलीवुड में कदम रख दिया। 3 जुलाई को अभिनेता राजकुमार की पुण्यतिथि होती है। जिन्होंने बॉलीवुड में अपने अभिनय और संवादों से सभी के दिलों को छुआ है। 3 जुलाई 1996 को गले के कैंसर के कारण उनका निधन हो गया था। आज वो इस दुनिया में भले ही नहीं हैं लेकिन लाखों दिलों में जिंदा हैं। राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित है, लेकिन लोग उन्हें 'जानी' कहते हैं। जानी ने हिंदी फिल्मों में काम करके बहुत नाम कमाया। अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए वह 1940 में मुंबई (तब बंबई) आए। उन्होंने बॉलीवुड करियर की शुरुआत फिल्म 'रंगीली' से की थी। इस फिल्म के बाद कई फिल्में आईं, जैसे 'अबशार', 'घमंड' आदि। राजकुमार ने अपने फिल्मी करियर मे 'तिरंगा', 'मरते दम तक', 'पाकीजा', 'हीर रांझा' और 'मदर इंडिया' जैसी बेहतरीन फिल्में दीं। राजकुमार कहते थे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी फिल्में अच्छा कर रही हैं या नहीं, लेकिन वह विफल नहीं हो रहे थे। राजकुमार ने जेनिफर नाम की महिला से शादी की जो फ्लाइट अटेंडेंट थीं। शादी के कुछ समय बाद, जेनिफर ने अपना नाम बदलकर गायत्री रख लिया और राजकुमार के दो बेटे पुरु, पाणिनि राजकुमार और बेटी वास्तविक्ता राजकुमार हैं।

आठ अक्टूबर को अभिनेता राजकुमार की पुण्यतिथि है, जिन्होंने बॉलीवुड में अपने अभिनय और संवादों से सभी के दिलों को छुआ है, आठ अक्टूबर, 1996 को गले के कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, आज वो इस दुनिया में भले ही नहीं हैं लेकिन लाखों दिलों में जिंदा हैं।

अरुण सिंह
मुंबई ब्यूरो

दमदार एक्टिंग

राजकुमार ने कई सदाबहार फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग से सालों तक दर्शकों को अपना दीवाना बनाए रखा। बॉलीवुड में अपनी डेब्यू फिल्म 'रंगीली' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाले राजकुमार अदाकारी के साथ अपनी निजी जिंदगी में भी रौब और अलग अंदाज के लिए जाने जाते थे। उनके सिगार पकड़ने का स्टाइल हो या डायलॉग बोलने का तरीका। उनकी हर चीज ने लोगों को खूब इंप्रेस किया। उनकी फिल्मों के कई डायलॉग्स आज भी मशहूर हैं। 60 से लेकर 90 के दशक तक बॉलीवुड पर राज करने वाले राजकुमार के हर एक डायलॉग पर सिनेमाहॉल तालियों से गूंज उठता था। अपने दमदार डायलॉग से फैंस का दिल जीतने वाले राजकुमार असल जिंदगी में भी अपनी बेबाकी के लिए मशहूर थे। कहा जाता है कि उस दौर के सभी बड़े स्टार्स से अक्सर उनकी तकरार हो जाया करती थी। वो फिल्मों में भी अपनी शर्तों पर ही काम करते थे। फिल्म चाहे कैसी भी क्यों न हो सिनेमाहॉल में फैंस उनके डायलॉग के लिए पूरी फिल्म देख डालते थे। बॉलीवुड में राजकुमार के अलावा शायद ही कोई दूसरा एक्टर रहा हो जिसके लिए इतने बेहतरीन डायलॉग लिखे गए हों। राजकुमार की पर्सनालिटी ही ऐसी थी कि फिल्म में उनके लिए खासतौर पर चुन-चुन कर डायलॉग लिखे जाते थे। इसके लिए डायलॉग राइटर्स को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन पर्दे पर दमदार दिखने वाले राजकुमार के सभी डायलॉग्स के पीछे एक गहरा संदेश छिपा होता था।

बिंदाश अंदाज के मालिक

राजकुमार अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते थे। एक बार की बात है जब बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और राजकुमार एक पार्टी में मिले। अमिताभ पार्टी में विदेशी सूट पहनकर आए थे। उस समय सूट पहनना छोटी बात नहीं थी। राजकुमार ने अमिताभ के सूट की तारीफ की। अमिताभ ने खुश होकर उन्हें उस जगह का नाम और पता बताना चाहा तो राजकुमार ने जवाब दिया कि उन्हें कुछ पर्दे सिलवाने थे। यह बात सुनकर अमिताभ मुस्कुराने के अलावा कुछ भी नहीं कह सके। राजकुमार का एक और दिलचस्प किस्सा है वो ये कि एक बार राजकुमार शूटिंग पर नहीं पहुंचे तो निर्माता ने उन्हें घर पर फोन किया, किंतु राजकुमार ने फोन नहीं उठाया। अगले दिन जब वो शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचे तो निर्माता ने उनसे शिकायत की। राजकुमार ने पलटकर कहा-'फोन हमने अपनी सुविधा के लिए लगवाया है, दूसरों की सुविधा के लिए नहीं।' ये किस्सा 1989 का है जब राजकुमार और गोविंदा फिल्म 'जंगबाज' की एक साथ शूटिंग कर रहे थे। ब्रेक के दौरान दोनों साथ वक्त बिता रहे थे। यहां गोविंदा एक चमकदार शर्ट पहनकर आए थे। राजकुमार को उनकी शर्ट बेहद पसंद आई। उन्होंने गोविंदा से कहा 'यार तुम्हारी शर्ट तो बहुत शानदार है।' गोविंदा यह सुनकर बहुत खुश हुए और शर्ट राजकुमार को दे दी। दो दिन बाद गोविंदा उस समय हैरान रह गए, जब राजकुमार उस शर्ट का रुमाल बनवाकर अपनी जेब से निकालते हुए दिखे।

राजकुमार की लवस्टोरी

एक्टिंग के बेताज बादशाह राजकुमार एक बार फ्लाइट में सफर कर रहे थे। इस दौरान उनकी मुलाकात एयर होस्टेस जेनिफर से हुई। इसके बाद अक्सर दोनों मिलने लगे। मुलाकातों का सिलसिला कब प्यार में बदल गया दोनों को इसका अहसास तक नहीं हुआ। लिहाजा दोनों न केवल शादी का फैसला किया बल्कि शादी भी कर ली। शादी के बाद जेनिफर ने अपना नाम बदलकर गायत्री रख लिया। राजकुमार के जीवन से जुड़ा ऐसा ही एक मजेदार किस्सा डायरेक्टर मेहुल कुमार सुनाते हैं। उस दिन मेहुल कुमार का बर्थडे था। फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उनके बर्थडे पर राजकुमार ने एक केक मंगवाया। जिसके साथ एक तलवार भी मंगवाई थी। राजकुमार ने वह केक उसी तलवार से कटवाया भी था। राजकुमार ने मदर इंडिया, नील कमल, पाकीजा, दिल, पुलिस और मुजरिम, हीर-रांझा, लाल पत्थर, हिंदुस्तान की कसम, धर्म कांटा, तिरंगा, वक्त, कृष्ण सुदामा, रंगीली, बेताज बादशाह, सौदागर, मरते दम तक जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। राजकुमार के कई संवाद आज भी उनकी तरह अमर हैं। राजकुमार के बारे में एक और रोचक बात यह भी है कि अपने जीवन काल में उन्होंने लगभग 70 फिल्मों में काम किया। राजकुमार फिल्म फ्लॉप होने के बाद अपनी फीस बढ़ा देते थे। ऐसा करने पर जब निर्माता सवाल करते तो वो कहते थे 'फिल्म फ्लॉप हुई है, हम नहीं।' हालांकि 1952 से 1957 तक राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष भी करते देखे गए थे। पहली फिल्म 'रंगीली' 1952 में प्रदर्शित हुई जिसमें उनकी एक छोटी सी भूमिका थी। यह फिल्म सिनेमा घरों में कब लगी और कब उतर गई। यह पता ही नहीं चला। इसके बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली राजकुमार उसे स्वीकार करते चले गए। इस बीच

- **राजकुमार ने जेनिफर नाम की महिला से शादी की जो फ्लाइट अटेंडेंट थीं, शादी के कुछ समय बाद, जेनिफर ने अपना नाम बदलकर गायत्री रख लिया और राजकुमार के दो बेटे पुरु राजकुमार व पाणिनि राजकुमार और बेटी वास्तविक्ता राजकुमार हैं।**
- **राजकुमार फिल्म फ्लॉप होने के बाद अपनी फीस बढ़ा देते थे, ऐसा करने पर जब निर्माता सवाल करते तो वो कहते थे 'फिल्म फ्लॉप हुई है, हम नहीं' हालांकि 1952 से 1957 तक राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष भी करते देखे गए थे।**

उन्होंने 'अनमोल', 'सहारा', 'अवसर', 'घमंड', 'नीलमणि' और 'कृष्ण सुदामा' जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। महबूब खान की 1957 में प्रदर्शित फिल्म 'मदर इंडिया' में राजकुमार गांव के एक किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि यह फिल्म पूरी तरह अभिनेत्री नर्गिस पर केंद्रित थी। फिर भी वह अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय ख्याति भी मिली और फिल्म की सफलता के बाद वह अभिनेता के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। हालांकि एक दौर ऐसा भी आया जब राजकुमार की फिल्म 'शाही बाजार' बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। 'शाही बाजार' फ्लाप होने के बाद राजकुमार के तमाम रिश्तेदार यह कहने लगे थे कि तुम्हारा चेहरा फिल्म के लिए उपयुक्त नहीं है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि तुम्हारा चेहरा सिर्फ खलनायक बनने लायक है।

मासिक राशिफल

पंडित उपेन्द्र कुमार उपाध्याय
9897450817, 9897791284
ज्योतिषाचार्य, आयुर्वेदरत्न, कथावाचस्पति, यज्ञानुष्ठान विशेषज्ञ
अध्यक्ष-श्री शिवशक्ति ज्योतिष पीठ, बदायूं
निवास प्रभातनगर, निकट इंद्राचौक, सिविल लाइंस, बदायूं (यूपी)

मेष-

इस माह आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, यदि आप मित्रों के साथ यात्रा पर जा रहे हैं तो पैसा सोच समझकर व्यय करें, धन हानि हो सकती है। व्यक्तिगत मामलों को सुलझाते समय उदारता दिखाएं, लेकिन अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। बहुत करीबी प्रियजन से मिलने का योग बन रहा है। मुश्किल मामलों के समाधान के लिए अपने संपर्क का उपयोग करें, प्रेमी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। जीवनसाथी के साथ कुछ बेहतरीन पल गुजार सकेंगे। उपायः इत्र, परफ्यूम, कपूर का इस्तेमाल व दान करें कार्य सिद्ध होंगे।

वृषभः-

इस माह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इस राषि के जो जातक लघु उद्यमी हैं उन्हें किसी करीबी की आर्थिक लाभ पहुंचाने वाली कोई अच्छी सलाह मिल सकती है। पारिवारिक सदस्य या जीवनसाथी तनाव की वजह बन सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और तरक्की साफ नजर आएगी। कोरोनाकाल में खाली समय का पूरा आनंद उठाने के लिए लोगों से दूर रह कर पसंदीदा और महत्वपूर्ण काम निपटाने चाहिए। प्रेमी युगल सामान्य दिनों की अपेक्षा इस समय आपका अधिक ख्याल रखेगा। उपायः भैरो बाबा के मंदिर में दूध चढ़ाएं कार्य सिद्ध होंगे।

मिथुनः-

इस माह सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। आपका धन आपके काम तभी आएगा जब आप फिजूल खर्ची से बचेंगे। आपका कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। कुछ लोग आपके खिलाफ षडयंत्र रच रहे हैं। ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है जो आपका अहित चाहते हैं। आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। आपका प्रिय आपकी खुशी की वजह साबित होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। तरक्की के रास्ते खुलेंगे। कर्म-कांड, हवन-पूजन आदि का आयोजन करेंगे। उपायः खट्टी-मीठी टॉफियां, छोटी कन्याओं में बांटे कार्य सिद्ध होंगे।

कर्कः-

इस माह शारीरिक श्रम आपके सौंदर्य को निखारेगा। घर के सदस्यों को घुमाने ले जा सकते हैं। यात्रा में धन खर्च होगा। जीवनसाथी के साथ खरीदारी करेंगे। दांपत्य जीवन में गलत फहमी दूर होंगी। प्यार जीवन की डोर को मजबूत बनाए रखेगा। किसी तीसरे व्यक्ति की बातें सुनकर अपने प्यार के बारे में कोई राय न बनाएं। लोग आपको अपने बढ़िया कार्य के लिए पहचानेंगे। यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखे और दिक्कत से बचें। उपायः सफेद चंदन की जड़ सफेद कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें सभी कार्यसिद्ध होंगे।

सिंहः-

इस माह आपको आलोचना का शिकार होना पड़ सकता है। धन आपके काम तभी आएगा जब फिजूलखर्ची से बचेंगे। जिस पर भी आप भरोसा करते हैं, मुमकिन है वह आपको धोखा दे दे। न्यायालय संबंधी कार्यों में सफलता से मुश्किले हल करने में कामयाबी मिलेगी। आपका प्रिय आपको सदैव प्यार करता है, उस पर किसी तरह का संदेह न करें। कार्य में धीमी प्रगति हल्का-सा मानसिक तनाव दे सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। उपायः तामसिक वस्तुओं मांस-मदिरा का सदैव के लिए त्याग कर दें सभी कार्य सिद्ध होंगे।

कन्याः-

इस माह धन संचय करने के लिए परिजनों की सलाह लेना आवश्यक है। परिजनों की सलाह से आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बन रहे हैं। सभी विवादास्पद मुद्दों पर अनावश्यक बहस से बचें, इस माह जीवन में सच्चे प्रेम की कमी का अनुभव करेंगे। चिंता न करें समय के साथ बदलाव आते हैं और आपकी रोमांटिक जिंदगी में फिर बदलाव आएगा। आफिस से घर आते समय सावधानी से वाहन चलाने की जरूरत है, दुर्घटना की संभावना है। जीवनसाथी आप पर शक कर सकता है। उपायः सूर्यदेव को प्रातःकाल लालपुष्प अर्पित करें कार्य सिद्ध होंगे।

तुलाः-

इस माह सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। माह के मध्य में कर्ज चुकाने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। भावनात्मक रूप से खतरा उठाना आपके लिए हितकारी हो सकता है। परिजनों की गैरजरूरी मांगों को नजरअंदाज करने में भलाई होगी। प्रसिद्ध लोगों के मिलन से नई योजना का आइडिया मिलेगा। दूर की यात्रा का योग बन रहा है, लेकिन सफर के दौरान सावधान रहने की आवश्यकता है, धन की हानि हो सकती है। जीवन संगनी से अनबन हो सकती है। उपायः अपने प्रिय को सफेद शंख, शिप की वस्तुएं गिफ्ट करें सभी कार्य सिद्ध होंगे।

वृश्चिकः-

इस माह मजबूत और स्पष्टवादी बनें। कठोर फैसले लेने के साथ उनके परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहें। माह के मध्य में धन लाभ के योग हैं, इसलिए स्वभाव को शांत रखने की जरूरत है। आक्रमकता धन लाभ के योग से वंचित कर सकती है। रिश्तेदारों से कीमती तोहफा मिल सकता है। प्यार के नजरिए से देखें तो आप जीवन के रस का भरपूर आनंद लेंगे। कामकाज में अपनों का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा। जीवनसाथी का आंतरिक सौंदर्य बाहर भी पूरी तरह महसूस होगा। उपायः बिस्तर पर क्रीम कलर की चादर बिछाएं कार्य सिद्ध होंगे।

धनुः-

इस माह नफरत से दूर रहे क्योंकि यह आपके मन के साथ शरीर पर भी बुरा प्रभाव डाल सकती है। रात के समय धन लाभ होने की संभावना है, रुके हुए धन की प्राप्ति से मन प्रसन्न होगा। बच्चों की तरफ से कोई खुश खबर मिलने वाली है। शत्रु पक्ष आपके रिश्तें में दरार डालने की कोशिश करेंगे। पेशेवर तौर पर यह माह सकारात्मक रहेगा। अपनी खुशियों का इजहार करने के लिए उतावलापन न दिखाए। जीवनसाथी का रुखापन देखने को मिल सकता है। उपायः लक्ष्मीनारायण मंदिर में नियमित प्रसाद चढ़ाएं सभी कार्य सिद्ध होंगे।

मकरः-

इस माह संत महात्मा का आशीर्वाद मानसिक शांति प्रदान करेगा। माता-पिता फिजूलखर्ची से चिंतित हो सकते हैं। आप समूह में हों तो वाणी पर ध्यान रखें वरना कड़ी आलोचना का शिकार हो सकते हैं। यह माह कार्यक्षेत्र में आपकी प्रसिद्धि बढ़ा सकता है। आपके सहकर्मी आपके काम की तारीफ करेंगे। बॉस भी आपके काम से खुश होगा। कारोबारी भी आज कारोबार में मुनाफा कमा सकते हैं। खाली समय में कोई गेम खेलना ठीक रहेगा। जीवनसाथी से विवाद की प्रबल संभावना है। उपायः चंद्रमा की चांदनी में बैठ कर खीर खाएं कार्य सिद्ध होंगे।

कुंभः-

इस माह व्यापार को मजबूती देने के लिए कोई अहम कदम उठा सकते हैं, कोई करीबी कारोबार में आपकी आर्थिक मदद कर सकता है। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मौज मस्ती करेंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कारोबार से जुड़ी गोपनियता किसी के साथ साझा न करें। गोपनियता भंग होने पर बड़ी किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। हालात से उबरने के लिए दृढ़ इच्छा-शक्ति बनाए रखें। माह के मध्य में इस राशि के जातकों को वैवाहिक जिंदगी की अहमियत का अहसास होगा। उपायः मसूर की लाल दाल किसी गरीब को दान करने से कार्य सिद्ध होंगे।

मीनः-

इस माह आपकी प्रगति की बाधाएं दूर होंगी। घर से बाहर निकलते समय सकारात्मक विचार आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। किसी कीमती वस्तु के चोरी होने से मूड खराब हो सकता है। पुराने संबंधियों के मिलन से पुराने रिश्तें में ताजगी आएगी। किसी प्राकृतिक सौंदर्य से खुद को सराबोर महसूस करेंगे। कार्यालय में सब कुछ आपके पक्ष में रहेगा। जीवन के अहम मुद्दों पर घरवालों के साथ बैठकर बात कर सकते हैं। यात्रा संभव है, जीवनसाथी का आपके ऊपर खास ध्यान रहेगा। उपायः शिव मंदिर में नियमित गंगाजल चढ़ाएं सभी कार्य सिद्ध होंगे।